

Registration No. RAJBIL /2016 / 69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

UDY OG TIMES

Volume -8 Is Total Pages - 152

Issue-10

August - 2025

Price - Rs. 10



उद्योग उत्थान

राष्ट्रीय उद्यमी सम्मेलन, समालखा

विशेषांक

खास स्टोरी-

- 'सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सुरक्षा जरूरी'
- 'कौशल विकास का 'पाली मॉडल'

Principal Sponsor Our MOU Partner

Supported by:

















UDYOG

Volume -8

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI Issue - 10

August 2025

TOTALITIC O	13300 20	Linkast Form
Editorial Board	<u>d</u>	
■ Patron		
Shri Ghanshyam Ojha	a, National President	098290-22896
Shri Prakash Chandra	ry 099299-93660	
Shri Om Prakash Gup	sta, National Gen. Secreta	ery 095602-55055
■ Editor		
Dr. Kirti Kumar Jain		094141-90383
■ Co-Editor		
Dr. Sanjay Mishra		098295-58069

विवरणिका	
सम्पादकीय	03
सन्देश	05
Contribution of RSS	15
कुटीर और लघु उद्योग	17
राष्ट्र विजयी हो हमारा	21
प्रगति रिपोर्ट	23
MSME Ecosystem	25
Empowering Women	27
HSIIDC & True Commitment	31
Odisha Industrial Powerhouse	35
मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2025	37
Haryana's Industrial Transformation	39
Feature Revolutionizing Delhi Gov't	43
Chhattisgarh Industrial Development	45
राजस्थान ने रचा नया इतिहास	47
CSIR-LUB Partnership	51
Government-e-Marketplace	53
India Manufacturing Show	55
India Industrial Fair	63
कौशल विकास का पाली मॉडल	83
State Reports	105

Corporate & Head Office :

Life Membership 1000/-

Price - 10/-

Shri Vishwakarma Bhawan 48, Deen Daval Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002

Website: www.lubindia.com Email: headoffice@lubindia.com Ph.: 011-23238582

Registered Office:

Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011 Ph.: 0712-2533552



GST Reform: A Lifeline for MSMEs

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain kkjain383@gmail.com

Days after the US announced the irrational 50 percent tariffs on imports from India, the government's latest GST rationalisation exercise is without doubt a rare opportunity for our small businesses to breathe easier. They have long struggled with a tax regime that is complex, fragmented and capital-draining, and add to it the weight of Trump's added tariffs.

The first thing that stands out in the recent GST reform discussions is the trimming of four slabs into a simpler two-tier structure. This will cut away the red tape that choked enterprises of both time and money. In short it means no more endless battles with inverted duty structures, and no more refunds stuck in the system.

Equally important is the impact these reforms will have on the working capital for MSMEs. The proposed automated, pre-filled GST system will not only be faster and more efficient but also help MSMEs get the much-needed liquidity on time through refunds-capital that can be channelled into growth and expansion. Once implemented, it will save MSMEs from getting trapped in the bureaucratic red tape and reduce the amount of manual work they do.

The proposed reforms will also fuel our "Make in India" ambition and will make our MSMEs more competitive at the global level. The goods manufactured in India will attract more global buyers. While we cannot control tariffs imposed by other nations, we can strengthen our internal economy. This reform builds the resilience our businesses need to withstand and overcome such external shocks.

In a nutshell, the recent announcements may be more than rate rationalisation. For our entrepreneurs, this could be liberation.





NORTH EAST RECION'S L'ARGEST EXPO

30 31 OCT 01 02 NOV. 2025

Veterinary Ground, Khanapara Near Vivanta Hotel, Guwahati-781022, Assam









मुख्यमंत्री, हरियाणा चण्डीगढ़। Chief Minister Haryana Chandigarh



नायब सिंह माननीय मुख्यमंत्री

मुझे ये जानकार खुशी हुई है कि लघु उद्योग भारती हरियाणा प्रान्त द्वारा 15 सितम्बर, 2025 को पट्टी कल्याणा, पानीपत में उद्यमी एवं अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय पत्रिका उद्योग टाइम्स का विशेषांक 'उद्योग—उत्थान' भी प्रकाशित किया जा रहा है।

खुशी की बात है कि लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में पूरे भारत के 2500 से अधिक उद्यमी भाग ले रहे हैं। लघु उद्योग भारती एक मात्र ऐसा औद्योगिक संगठन है, जो भारत में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत है और जिसने औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर न केवल उल्लेखनीय कार्य किया है बल्कि प्रत्येक राज्य एवं जिला स्तर पर अपनी शाखाएं भी स्थापित की है।

हरियाणा सरकार राज्य के समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक अनुकूल बनाने और हरियाणा को एक आदर्श निवेश—गंतव्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार ने कारोबार की सहूलियत बढ़ाने और कारोबार लागत को कम करके उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने, प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार करके संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है।

मैं उद्यमी सम्मेलन एवं इस अवसर पर उद्योग टाइम्स के प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ।

(नायब सिंह)





SNACK THE RIGHT WAY









NACHO CRISPS | NUTS & SEEDS | TACOS | TORTILLA WRAP





Scan or Visit shop cornitos in to expore Nachos Range





LUB's Commendable Contribution to the MSME Sector, ensures National Progress

Dr. Pramod Sawant Hon'ble Chief Minister

It gives me great satisfaction to acknowledge the significant contributions of Laghu Udyog Bharati since its inception. This organization has become a formidable voice for the MSME sector, which is crucial to our state's prosperity.

I have personally noted the dynamic efforts of LUB's Goa State Unit through regular awareness programs, community empowerment and outreach programs. I was particularly impressed by the success of the Goa MSME Convention held at the Raj Bhavan in January 2023, as well as during the Vibrant Goa in November 2024, which brought together a vast number of entrepreneurs.

It is at such forums that I see LUB working not just for industrial interests, but for the larger goal of state and national progress.

Our collaboration has been particularly fruitful. I appreciate the insightful recommendations of LUB's state officials during the pre-budget consultations, which have led to the successful implementation of vital schemes like the state-backed CGTMSE enhancement. This partnership demonstrates our shared commitment to improving the Ease of Doing Business in Goa.

The LUB's work extends commendably to empowering women entrepreneurs and promoting our unique cultural heritage through the Kunbi handloom project. These initiatives are a true embodiment of our vision for a 'Swayampurna Goa'.

The Govt. of Goa remains a steadfast partner in journey of Laghu Udyog Bharati for strengthening MSMEs for Viksit Bharat. My best wishes are with the entire team of LUB for a grand success of Samalkha Udyami Smmelan in Haryana.





लघु उद्योग भारती और दिल्ली सरकार एमएसएमई सेक्टर को नई ऊर्जा और गति देने एक दिशा में अग्रसर

सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा माननीय कैबिनेट मंत्री उद्योग दिल्ली सरकार

लघु उद्योग भारती के समालखा राष्ट्रीय अधिवेशन (13 से 15 सितम्बर, 2025) के अवसर पर मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

मेरे लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि 31 वर्ष पूर्व दिल्ली से प्रारंभ हुई लघु उद्योग भारती आज विराट स्वरूप धारण कर देश का सबसे बड़ा और सशक्त संगठन बन चुकी है, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्यरत है।

लघु उद्योग भारती दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं से मेरा सतत संवाद बना रहता है। उनके द्वारा दिए गए सुझावों को प्राथमिकता से लेते हुए, दिल्ली में कारोबारी सहजता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने के हर प्रयास को सरकार ने आगे बढ़ाया है।

आज यह देखकर संतोष होता है कि सरकार और संगठन एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। यह तो अभी केवल शुरुआत है, आगे का एक लंबा सफर साथ में मिलकर तय करना है। मुझे विश्वास है कि इस सामृहिक प्रयास से दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में MSME सेक्टर को नई ऊर्जा और गति प्राप्त होगी।

आगे भी, आपके मार्गदर्शन और सुझावों के अनुरूप, हम दिल्ली में विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण तथा व्यापारिक माहौल को और अधिक सरल व अनुकूल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं।

एक बार पुनः, लघु उद्योग भारती के संगठनकर्ता, दायित्ववान उद्यमियों और समस्त कार्यकर्ता सदस्यों को इस अधिवेशन की सफलता के लिए मंगलकामनाएँ।





Corporate Office: 215-219, Tower 4, ABC Sector-135, Noida - 201304, UP India +91 120-6900219 | sales@ssgaslab.com | www.ssgaslab.com

Research Center: A-6/3, Jhilmil Industrial Area GT Road, Delhi-110095, India Manufacturing Facility: A-4, EPIP 5, Kasna Rd. Industrial Area, Surajpur, Greater Noida-201310, UP, India





'उद्योग हित' से ''राष्ट्र हित'' के लिए कार्यरत है लघु उद्योग भारती



लखनलाल देवांगन माननीय कैबिनेट मंत्री वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम विमाग, छत्तीसगढ़ शासन

लघु उद्योग भारती की ओर से प्रदेश भर में आयोजित बहुत से कार्यक्रमों में, मैं स्वयं सम्मिलित हो चुका हूँ, और वहां मैंने लघु उद्योग भारती को न केवल लघु एवं मध्यम उद्योगों की, अपितु हमारे सूक्ष्मऔर ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों एवं महिला उद्यमियों के हितों की भी बात करते हुए देखा।

मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ लघु उद्योग भारती ने 17-18 अक्टूबर, 2024 को उद्यमियों के लिए एक क्षेत्रीय सम्मलेन का आयोजन किया था, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के साथ मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला था। कार्यक्रम में सम्पूर्ण मध्य क्षेत्र के 500 से अधिक उद्यमी बंधु उपस्थित थे, जहाँ उद्योगों के समक्ष आने वाली विविध समस्यायों के साथ समाधान पर भी सार गर्भित चर्चा की गई। तब मैंने अनुभव किया, कि यह संगठन वास्तव में "उद्योग हित" के माध्यम से "राष्ट्र हित" के लिए ही कार्य कर रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है, अतःएव सरकार ने, लघु उद्योग भारती के सदस्यों द्वारा छोटे उद्योगों को लाभ पहुँचाने वाले विषयों को एकत्रित कर, नीति में उसे अधिक से अधिक समाहित करते हुए, नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया है, जिसे पूरे देश में सराहा जा रहा है।

लघु उद्योग भारती द्वारा 13 से 15 सितम्बर तक समालखा (हरियाणा) में वृहद् उद्यमी सम्मलेन का आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य की भागीदारी हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं लघु उद्योग भारती को अपने उद्देश्य में निरंतर अग्रसर होने और सफल होने के लिए मंगल कामना प्रेषित करता हैं।





लघु उद्योगों के विकास में लघु उद्योग भारती का टुैक रिकॉर्ड शानदार

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ माननीय कैंबिनेट मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार

भारत के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास और उत्थान में लघु उद्योग भारती संगठन का उल्लेखनीय योगदान रहा है। संगठन की ओर से आयोजित फ्लैगशिप ट्रेड फेयर इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर (आईआईएफ) और महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई सार्थक पहल स्वयंसिद्धा प्रदर्शनी के भी अवलोकन का अवसर मुझे मिला। संगठन के ये दोनों ही कार्यक्रम सफल हैं। लघु उद्योग भारती ने उद्योगों और सरकार के बीच संवाद—सेतु का कार्य किया है जिससे उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सका।

मेरे पास अभी राजस्थान के उद्योगों को आगे बढ़ाने का दायित्व है और अगर केवल अपने प्रदेश की बात भी बात करूं, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से एमएसएमई सेक्टर के कल्याण के लिए बनाई जानी वाली अलग—अलग मंत्रालयों और खासतौर पर उद्योग नीति के निर्माण से लेकर उनके व्यावहारिक समाधानों को सुझाने में संगठन ने अनुकरणीय कार्य किया है।

संगठन के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर ही विभाग ने उद्योगों की समस्याओं के स्थाई निराकरण के लिए गठित टास्क फोर्स में भी लघु उद्योग भारती को प्रतिनिधित्व दिया। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में बतौर पार्टनर जोड़ा। पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव में नोडल एजेंसी बनाने के साथ अभी 2026 से जयपुर में आयोजित होने वाले विश्व स्तरीय इण्डिया स्टोनमार्ट के आयोजन में भी लघु उद्योग भारती की प्रमुख भूमिका होगी। प्रदेश के औद्योगिक विकास में संगठन की सक्रिय सहमागिता के लिए सर्वदा स्वागत है।



Government of Rajasthan



Shri Narendra Modi Hon'ble Prime Minister



Shri Bhajanlal Sharma Hon'ble Chief Minister Rajasthan



Shri Rajyavardhan Rathore Hon'ble Minister for Industry and Commerce Rajasthan



Shri K.K. Vishnoi Hon'ble Minister of State for Industry and Commerce Rajasthan

INDIA'S BIGGEST STONE INDUSTRY SHOWCASE





Organiser



Principal Sponsor



Co-Organiser

Fair Sponsor



 $in fo@stone mart-india.in \mid www.stone mart-india.in \mid +91-7300053633$





सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की सशक्त आवाज है लघु उद्योग भारती

चैतन्य कश्यप माननीय कैबिनेट मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम उद्योगों के विकास के लिए निरंतर अग्रसर हैं। हर्ष का विषय है कि इस कार्य में लघु उद्योग भारती भी उद्योगों की सशक्त आवाज बनकर सरकार का सहयोग कर रही है।

हाल ही के कुछ महीनों में एमएसएमई विभाग ने लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर 50 से अधिक RAMP कार्यशालाएं संपन्न की हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश की उद्योग नीति एवं भूखण्ड नीति को प्रत्येक उद्यमी तक पहुँचाने का कार्य किया गया।

लघु उद्योग भारती की सांगठनिक व्यापकता प्रत्येक जिले तक होने से हमें उद्यमियों की मन की बात जानने में आसानी होती है। संगठन से प्राप्त विषयों में से अनेक का सरकार द्वारा निराकरण किया जा चुका है और शेष विषयों का समाधान भी शीघ्र किया जाएगा।

संगठन की सबसे सराहनीय कार्यप्रणाली यह है कि यहाँ हर विषय का अध्ययन करने वाले कार्यकर्ता मौजूद हैं। यही कारण है कि संगठन केवल समस्याएँ ही नहीं लाता, बल्कि उनके संभावित समाधान भी प्रस्तुत करता है, जिससे सरकार को निर्णय लेने में सहलियत होती है।

पिछले दिनों लघु उद्योग भारती के नवीन भवन "उद्यम सेतु" के लोकार्पण पर मुझे उपस्थित रहने का अवसर मिला। यह भवन अपने नाम को सार्थक करते हुए शासन एवं उद्यमियों के बीच निरंतर समन्वय का कार्य करेगा, ऐसा मेरा मानना है।

समालखा (हरियाणा) में संगठन की अखिल भारतीय बैठक और उद्यमी सम्मेलन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। निश्चय ही इस बैठक से भारतवर्ष के औद्योगिक विकास में मध्यप्रदेश की सहभागिता और बढ़ेगी। मध्यप्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के लिए लघु उद्योग भारती के साथ हर स्तर पर कार्य करने हेतु सदैव तत्पर है।





लघु उद्योग भारती की सक्रियता उद्यमियों व प्रदेश सरकार के बीच समन्वय के लिए अत्यंत उपयोगी

राकेश सचान माननीय कैबिनेट मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश

हमारी सरकार ने आधारभूत सुविधाओं और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। शासन उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर निराकरण करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में लघु उद्योग भारती सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास में कार्यरत एक महत्वपूर्ण संगठन है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में संगठन के पदाधिकारियों से सतत मिलना हुआ। मुझे जो बात प्रभावित करती है वो है उनकी सेवा—भावना। प्रदेश में संगठन द्वारा सरकार के साथ उद्योग एवं उद्यमिता विकास के लिए निरंतर सहयोग प्रशसनीय है।

इसी वर्ष जनवरी, 2025 में लघु उद्योग भारती के प्रादेशिक सम्मेलन में विभिन्न जिलों से आये लगभग 800 उद्यमी बन्धुओं के साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण बात ये है कि उद्यमियों ने केवल अपनी समस्यायें ही नहीं रखी, बल्कि उनका समाधान कैसे हो सकता है, इस पर भी सुझाव दिए।

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि लघु उद्योग भारती का संगठन 70 जिलों में सक्रिय है। यह स्थिति उद्यमियों व प्रदेश सरकार के बीच समन्वय के लिए अत्यंत उपयोगी है। संगठन द्वारा औद्योगिक विकास के लिए नवीन उद्योगों की स्थापना के साथ उद्यमिता, हस्तशिल्प और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु किये जा रहे कार्यों से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, जिससे प्रदेश में पूंजी निवेश के साथ बेरोजगारी कम किये जाने का सरकार का उद्देश्य भी पूरा होगा।

लघु उद्योग भारती द्वारा 13 से 15 सितम्बर तक समालखा (हरियाणा) में वृहद उद्यमी सम्मेलन के आयोजन में उत्तर प्रदेश राज्य की भागीदारी हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं लघु उद्योग भारती को अपने उद्देश्य "उद्योग हित—राष्ट्र हित" में निरंतर अग्रसर और सफल होने के लिये मंगल कामना प्रेषित करता हूँ।



श्री नरेन्द्र मोदी साननीय प्रधानमंत्री





श्री भजनलाल शर्मा _{याननीय मुख्यमधी}

स्वस्थ पशुधन सम्पदा की ओर बढ़ते कदम

बीमार पशुओं के इलाज के लिए डायल करें

हेल्प लाइन नंबर 🕲 1962

- सेक्स सॉर्टेड वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराएं और बछड़ी पाएं
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का नि:शुल्क बीमा कराएं

समय प्रातः 7:00 से सायंकाल 4:30 बजे तक

कॉल करने का

536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से प्रदेश के गरीब पशुपालकों को घर बैठे मिल रही नि:शुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं

संरक्षित पशुधन सुरक्षित पशुधन अपने पशुधन का बीमा अवश्य कराएं

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क करें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान



1

देश की आर्थिक रीढ़ एमएसएमई के विकास में लघु उद्योग भारती का महत्वपूर्ण योगदान

बलवंत सिंह राजपूत माननीय मंत्री – उद्योग, एमएसएमई, कॉटेज एवं ग्रामीण उद्योग, गुजरात सरकार

सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए समर्पित संगठन लघु उद्योग भारती की और से 13 से 15 सितंबर तक समालखा (हरियाणा) में 'वृहद् उद्यमी सम्मेलन' का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश में औद्योगिक, आर्थिक, बुनियादी ढांचा के विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक सुधारों के साथ नए भारत के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत है और उनके मार्गदर्शन में हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की अगुवाई में गुजरात सरकार भी विकसित भारत के लिए सर्वांगीण विकास वाले गुजरात को बनाने की दिशा में सशक्त कदम उठा रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिनमें अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 7. 3 ट्रिलियन डॉलर होगा। एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आघार है और रोजगार निर्माण और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

देश की आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले इस एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) क्षेत्र के विकास में लघु उद्योग भारती का महत्वपूर्ण योगदान है। संगठन के फ्लेगशिप ट्रेड फेयर इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर (आईआईएफ) के आयोजन यहां राजकोट में भी सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं और साथ ही महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संगठन ने देशभर में उनके उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयंसिद्धा प्रदर्शनियों का भी आयोजन कर रहा है, वो बहुत सराहनीय कदम है। इससे हजारों की संख्यां में महिला उद्यमी आगे आई हैं। एक बार पुनः वृहद उद्यमी सम्मेलन की सफलता के लिए लघु उद्योग भारती टीम को बधाई और शुभकामना।

Global Trade Challenges & Reciprocal Tariffs



NK Gupta Executive Member LUB's Faridabad Unit, Haryana

Global trade is essential due to geographical and economic différences. Uneven resource distribution and cost advantages make trade inevitable. High GDP nations drive demand, benefiting export-oriented countries.

Reciprocal Tariffs:

These are taxes imposed in response to similar measures by other nations. While meant to protect local industries, repeated tariffs can lead to trade wars, higher prices, and economic slowdown. Hence, global cooperation is vital.

Challenges for Bharat:

Recent US tariffs have impacted Indian industries. To counter this, Bharat must safeguard local sectors and ensure affordable imports. Generating employment through local manufacturing and making goods accessible to all is crucial. This aligns with the vision of Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India).

Action Plan:

- Boost quality production in India at competitive costs.
- Enhance global competitiveness of Indian goods.
- Avoid excessive protectionism while fostering trade relations.
- Encourage citizens to prioritize Indian products.
- Promote innovation, research, and ease of doing business.
- Follow the mantra: Reform, Perform, Transform.

A united effort towards self-reliance will help India overcome global trade challenges and build a resilient economy.



Bringing the Farm's Best to Your Kitchen

GPA FOODS PVT. LTD.

🖾 agropure@agropure.net 😩 www.agropure.net 📞 011 - 47820000





Wide Angle Udyog Times Desk

PM Shri Narendra Modi on 15th August used the prestigious pulpit of the Red Fort to lavish Praise on the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS), saying that the Sangh's contribution to the nation marks a 'proud and golden chapter.

Speaking about the contribution of individuals and organisation to nation building in his Independence Day address, the PM said:

"Today, with great pride, I wish to mention one such institution. One hundred years ago, the RSS was founded, these 100 years of service to the nation constitute a proud and golden chapter. With the resolve of nation-building through characterbuilding, with the aim of serving Maa Bharati, the Swayamsevaks have, for a century, dedicated their lives to the welfare of the motherland".

The remarks of the PM, himself a swayamsevak, also praised Late Shri Shyama Prasad Mookerjee, the founder of Bhartiya Jan Sangh, as BJP was known in its original incarnation, who died in jail after being imprisoned for companioning against Special Status for J&K.



"Dr Mookerjee was the first great personality of the nation to sacrifice his life for the constitution of Bharat. The removal of the wall of the Article 370 and the realisation of the mantra of "One Nation, One Constitution have been our true tribute to him", P.M. said referring to his govt's landmark decision on J&K in 2019.

Although Sangh was invited to be a part of Republic Day parade in 1963, this was, perhaps, the first instance of praise for the organisation which has defied bans, controversies and intense opposition from influential political and academic quarters to become one of the country's major influences and a challenge to the Nehruvian/ liberal version of nationalism and speculations.

Modi went the full distance in expressing his veneration for the organisation. Service, dedication, organisation and unmatched discipline, these have been its hallmarks. In a



sense, that. RSS is the world's largest NGO, with a century-long history of devotion. Today, from the ramparts of the Red Fort, I salute all the swayam-sevaks who have contributed to this century-long journey of national service, and the nation takes pride in the grand and dedicated journey of the RSS, which will continue to inspire us.

Major Announcements:

Semiconductors: From Lost Decades to Mission Mode

Recalling how attempts to set up semiconductor factories 50-60 years ago were "killed at birth" while other nations prospered, PM Modi announced that India is now on mission mode. By the end of this year, the nation will roll out its first Made in India chip.

 Nuclear Energy Capacity to Grow Tenfold by 2047 Work is underway on 10 new nuclear reactors as part of India's mission to increase nuclear power generation capacity by over ten times in the next two decades.

GST Reforms - A Diwali Gift

Next-generation GST reforms will be unveiled on Diwali, reducing taxes on essential goods and providing relief to MSMEs, local vendors, and consumers.

Reform Task Force for a \$10 Trillion Bharat

PM Modi announced the creation of a dedicated Reform Task Force to drive next-generation reforms. Its mandate: accelerate economic growth, cut red tape, modernise governance, and prepare Bharat for the demands of a \$10 trillion economy by 2047.

 ₹1 Lakh Crore PM Viksit Bharat Rozgar Yojana PM Modi launched a major employment scheme worth ₹1 lakh crore, under which newly employed youth will receive ₹15,000 per month. The scheme aims to benefit 3 crore young Indians, strengthening the bridge from Swatantra Bharat to Samriddha Bharat.

High-Powered Demography Mission

PM Modi highlighted the dangers of demographic imbalance due to infiltration and illegal migration in border areas. He announced the launch of a High-Powered Demography Mission to address this national security challenge, ensuring the unity, integrity, and rights of India's citizens are safeguarded.

Energy Independence - Samudra Manthan Begins

PM Modi pointed out that a large share of India's budget still goes toward importing petrol, diesel, and gas. He announced the launch of the National Deepwater Exploration Mission to tap ocean resources, alongside major expansions in solar, hydrogen, hydro and nuclear power.

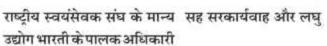
Made in India Jet Engines - A National Challenge

PM Modi made a dramatic announcement that just like how we made vaccines during COVID, and UPI for digital payments, we should build our own jet engines too for our jet engines and asked our scientists and youth to take it up as a direct challenge.

कुटीर और लघु उद्योग सबसे कम प्रदूषण करते हैं, और रोजगार सबसे अधिक देते हैं, इनकी सुरक्षा जरूरी



प्रेरक पाशेय डॉ. कृष्ण गोपाल



(लघु उद्योग भारती, मध्यप्रदेश के भोपाल में नवनिर्मित भवन 'उद्योग सेतु' के उद्घाटन के अवसर पर दिए विशेष उदबोधन के संपादित अंश)

तकनीक के साथ उद्योगों में बढ़ता केन्द्रीकरण

आज सूक्ष्म और लघु उद्योग कैसे सुरक्षित रहें और आगे बढ़ें,
ये विश्व में एक बड़ा संकट खड़ा है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी,
वैसे ही संपत्ति, मशीन और उद्योग का केंद्रीकरण बढ़ेगा।
इसको रोक पाना मुश्किल काम है। दुनिया की संपत्ति का
बड़ा हिस्सा गिनी—चुनी कंपनियों के पास है। भारत में भी
1% लोग ऐसे हैं जिनका 26% आमदनी और 46% एसेट पर
कब्जा है और यह दिन—प्रतिदिन बढ़ रहा है और इससे सारी
दुनिया परेशान है। तकनीक और नए शोध रोजगार को कम
करते हैं। अमेरिका की जीडीपी भारत से सात गुना है और
जनसंख्या में हम उनसे तीन गुना से ज्यादा है। फिर भी वहां
पर बेरोजगारी है, क्योंकि रोजगार और संपत्ति और प्रॉफिट
सब केंद्रीयकृत होता जा रहा है।



रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योगों की ताकत

आज भी भारत हिम्मत से खड़ा है और जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, वे देश में 90% उद्योग जन्य रोजगार देते हैं। 90% जो बड़े—बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं, बड़ी इंडस्ट्री हैं, उनका कंट्रीब्यूशन केवल 6% है रोजगार में। ये बीएचएल, सेल, जिंदल, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी सब मिला लीजिए। रोजगार में उनका हिस्सा केवल 6.5% है, जबकि एमएसएमई का हिस्सा 90% है। भारत के एक्सपोर्ट और हमारे औद्योगिक क्षेत्र के टोटल जीडीपी दोनों में एमएसएमई की भागीदारी 45% है।

पलायन को रोकने में सक्षम हैं लघु उद्योग

देश में एक बड़ी गंभीर समस्या पलायन की भी है। लोग गांव छोड़कर जाते हैं। गांव 7 लाख हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र मिलाकर के मुश्किल से 600, 700 से ज्यादा नहीं है। लोग गांव छोड़कर पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, सूरत,अहमदाबाद, नोएडा जाते हैं। ये सारे मिलाकर के 15 हैं केवल। और देश में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्लम्स में रहते

उद्योग उत्थान विशेषांक

हैं। गंदी बस्ती में एक-एक कमरे में 15, 16, 18, 20 नौजवान रहते हैं। आप कल्पना करिए। उनका सामाजिक जीवन... उनके बूढ़े माता-पिता कहां हैं? दूर गांव में। अपने बच्चों और पत्नी को छोडकर दस-पंद्रह हजार की नौकरी करने के लिए महानगरों में जाता है। वह अपने घर से, मिड्डी से,गांव से, परिवार, बुढे,मां-बाप, दादा-दादी को छोडकर वहां जाता है। इसको रोकने का काम केवल ये लघु उद्योग कर सकते हैं। मध्यम उद्योग कर सकते हैं। क्योंकि ये निकट में रोजगार देते हैं। ये सारे देश में बिखरे हुए हैं। 6 करोड़ यूनिट है इनकी। यह केवल 20, 50 या 100 जगह नहीं है। 6 करोड़ यूनिट हैं। कहीं दो लोग, कहीं तीन और कहीं 10 लोग काम कर रहे हैं। कहीं 20 और 50 भी। अपने घर के आसपास ही काम मिल जाता है उसको। इसलिए लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग ये पलायन को रोकते हैं और घर को बसाए रखते हैं। लघ उद्योगों में बड़ी संख्या में काम करने वाले लोग पिछड़े वर्ग के हैं। अनुसूचित वर्ग के हैं। जनजाति के हैं। और इसलिए समाज का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग इनमें रोजगार पा जाता है। और अपना घर छोड़ के भी नहीं जाता। एक एकड जमीन, एक गाय, भैंस और बूढ़े मां-बाप के साथ रहता है। वो अपनी जमीन से जुड़े रहकर अपनी सामाजिकता को संभाल करके रखता है। इस पक्ष पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है।

छोटे उद्योगों के लिए बड़ा प्रयास करती है लघु उद्योग भारती

अभी जो सुनामी चल रही है वह है सारे उद्योगों को केंद्रीयकृत करने की। लघु उद्योग भारती उसमें बड़ा संघर्ष कर रही है। बिजली के कनेक्शन, जमीनों के आवंटन और हर चीज के लिए इन उद्योगों को संघर्ष करना पड़ता है बड़ी कंपनियों से। इनकी छोटी कंपनी साबुन बना रही है, तो वही साबुन बड़ी कंपनी भी बना रही है। बड़ी कंपनी विज्ञापन करती है। अब जीएसटी दोनों पर 18% लगेगा, तो कैसे काम चलेगा? बड़ी कंपनी को रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है। इन सब बारीकियों को लेकर लघु उद्योग भारती के कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में सरकार के समक्ष इन उद्योगों की पैरवी कर उन्हें राहत दिलाने की कोशिश करते हैं।

उपभोक्तावाद के दौर में भ्रामक विज्ञापनों से कृत्रिम जरूरत होरही है पैदा

लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मध्यम दर्ज के उद्योग आज संकट में है। अकेले भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एक आध्यात्मिक भाव है। हम जमीन से जुड़े हैं और थोड़ा कम में भी काम चला लेते हैं। लेकिन हमारा परिवार भाव अभी भी बना हुआ है। इन बड़ी—बड़ी कंपनियों से और तथाकथित जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उससे हम टक्कर लेंगे। सारे विश्व में संकट है यह। और यह संकट उपभोक्तावाद का है। ये बड़ी कंपनियां भ्रामक विज्ञापनों से हमारे मन के अंदर उसकी आवश्यकता क्रिएट करती है। हमको लगने लगता है यह जूता नहीं पहना, तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। इस ब्रांड



की घड़ी, उस ब्रांड का शर्ट, कोट, और गाड़ी या किसी ब्रांड की मोटरसाइकिल, ये बीमारी सब जगह फैल गई है। जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप खरीदते हैं। और उनकी कंपनी चलती है। ये मल्टीनेशनल अपने विज्ञापन के आधार पर हमसे खरीददारी कराएंगी। लघु उद्योग सबसे कम एनर्जी में चलता है। सबसे कम वायु में प्रदूषण करता है। मनुष्य की शक्ति से यह काम चलाता है। और सारी धरती जो गर्म हो रही है उसमें इसकी भूमिका सबसे कम है। इसलिए इन लघु उद्योगों को बचाना है, बढ़ाना है, संवर्धित करना है। इनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना है। और इसमें लघु उद्योग भारती के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, इसलिए उनका अभिनंदन करता हं।

सामाजिक विषमता लंबे समय तक नहीं चलने वाली

अभी बीते दिनों बड़े उद्योग चलाने वाले एक सज्जन से मिलना हुआ जिनके पास करीब 6000 श्रमिक काम करते थे। हमने कहा वे अपनी कोठी बड़ी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर मजदूर का दो कमरे का मकान बनाना भी ये उनकी जिम्मेदारी है।

उनकी फैक्ट्री में 5 वर्ष काम कर लिया जिसने उसके पास दो कमरे तो होने चाहिए। साथ ही फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के बच्चे भी पढ़ पाए। वे अपने बेटे की ₹1 लाख महीना फीस दें, तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मजदूर का बेटा ₹500 फीस भी नहीं दे पाए, यह नहीं चलेगा। मजदूर के परिवार का हेल्थ कार्ड बने, उनका चेकअप हो, बीमारी का इलाज हो ये हमारी जिम्मेदारी है। वर्ष में कभी फैक्ट्री के मालिक और मजदूर साथ बैठकर खाना खाएं। सबके अंदर परमात्मा है। अब सामाजिक विषमता लंबी नहीं चलेगी। देश में कई स्थानों पर फैक्ट्री परिसर में अच्छे सहमोज के कार्यक्रम कर रहे हैं। मजदूर परोसते हैं। मालिक खाता है। कहीं मजदूरों का सार्वजनिक सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, वे हमारे परिवार का अंग है। आर्थिक दृष्टि से भी जो संभव हो, उनकी सहायता करें।

नियमों के पालन का संकल्प लेकर बनें आदर्श नागरिक

हम एक महान देश के नागरिक हैं। एक बार मन में पक्का करें कि छोटी—मोटी कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन हम नियमों का पालन करेंगे। कानून से बच के चलना ठीक नहीं है। हम हमेशा उदाहरण जापान, जर्मनी और इजराइल का देंगे। जबकि नियमों का पालन करते हुए हम भी आदर्श नागरिक बन सकते हैं।

अक्सर देखने में आता है कि इंडस्टी का गंदा पानी जमीन के नीचे डाल देते हैं। साथ ही ठीक प्रकार से लेबर लॉ का पालन भी नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। कठिनाई होती है बिजली कनेक्शन, जीएसटी या अन्य चीजों में। लेकिन धीरे-धीरे देश कानून का पालन करने वाला भी तो बन सकता है। थोड़ा कठिनाई भी झेलें। मिलकर योजना बनाएं। अभी मैं राजस्थान के बालोतरा-पाली गया। वहां पर पूरे उद्योग जगत के लोगों ने मिलकर इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी एक जगह ले आए। कहीं नाले में नहीं डाला। करोड़ों लीटर पानी प्रतिदिन एक जगह लाते हैं। साफ करके दोबारा से उसको युज करते हैं। टेक्सटाइल का काम वहां होता है। कम से कम 400 500 इंडस्ट्री चलती है। एक बुंद भी गंदा पानी कहीं नदी में, नाले में, कुएं में नहीं डालते। लेकिन सब ने मिलकर के प्रयत्न किया था। सरकार ने भी कुछ सहायता करी। इसी तरह आवश्यक है कि हम संविधान के लिए समर्पित और सच्चे नागरिक के रूप में खड़े हो जाए।

With Best Compliments From :



METAL DYNE AUTO PARTS PVT LTD.

(AN ITAF 16949:2016 & ISO 9001:2015)

Manufacturers of:
ALL TYPES OF SHEET METAL, TRUNNING
COMPONENTS, NEW TOOLING & PIPE
LASER CUTTING.

Plot No. 224 & 180K, Sector-3 IMT Bawal-12501 (Haryana) Cell: 8930036111, 893093111

E-mail: arun@metaldyneauto.com,

metaldyneauto@gmail.com

Website: www.metaldyneauto.com



GHU UDYOG BHARTI **PUNJAB**



Pardeep Mongia State President Laghu Udyog Bharati Punjab



Anii sharma State Jt. General. secretary Laghu Udyog Bharati Punjab



Suresh Gupta State Jt. Cashier Laghu Udyog Bharati Punjab



Davinder Kaushal State secretary Laghu Udyog Bharati Punjab



MONGIA & CO. (Mfg. Div.)

Mfg: Deep Freezers, Water Coolers, Dehumidifiers, Chillers and Commercial Kitchen Equipment

R.O. Village Baldpura, Barwala Road, Deratiassi M. 92161 25258, 56. Email: mongia@mongia.co.in





RAHUL GUPTA

RVL POLY INDUSTRIES PVT. LTD.

[A FSSC J2000 CERTIFIED COMPANY]

Printed Wrappers for Espiler Paper, Paper Sweet Wrappers, PE Cascal Papers & Sounds, Lines & Lines Sags, Street Fiber & HEFE/SPF (Spiles Fabrical Stage)

H. G. & Works: | Sample Industrial Fash, Stock -- A, Same Dark Manyal, Purpos -- 140 not (NASA)

Website (mm,nmh,nm

Email: 1 conditionment undansiellerintenen





PREM METAL PLAST (P) LTD.

GSTIN: 03AAECP8587A1ZH

REGD. OFFICE & WORKS LANE NO. 10, LUXMI INDUSTRIAL PARK, VILL. SAIDPURA, BARWALA ROAD, DERABASSI

+91-98140 17533

संकटों पर मात कर यह, राष्ट्र विजयी हो हमारा





अंतस के उदगार घनश्याम ओझा राष्ट्रीय अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती president@lubindia.com

भगवान विश्वकर्मा और माँ भारती के चरणों में प्रणाम।

हरित प्रदेश हरियाणा के पट्टी कल्याणा में श्री माधव जन सेवा न्यास द्वारा संचालित सेवा, साधना और ग्राम विकास केंद्र परिसर में लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उद्यमी सम्मेलन के अवसर पर देश के सभी अंचलों का प्रतिनिधित्व करने वाले और अपनी उद्यमिता से राष्ट्र की खोई अस्मिता को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लेने वाले संगठन के गौरवशाली उद्यमी गण। आप सभी का हार्दिक स्वागत...... अभिनन्दन।

निजी उद्यम से बड़े उद्देश्य तक

संगठन के साथ निरंतर काम करते—करते हमारा संबंध भी और गहरा होता जाता है, बिल्कुल परिवार जैसा। संगठन से पहले आप अपने उद्यम के साथ जुड़ते हैं, फिर उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। वो जो विशेष उद्देश्य है, वही हमारी कार्यशैली और व्यक्तित्व में भी झलकता है। संगठन से सीखकर हम कुशल उद्यमी बनते हैं, और अपने उद्योग की अभिवृद्धि भी करते हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में आये व्यापक परिवर्तन के कारण 'राष्ट्रोद्धारो लघुउद्यमें ही हमारे जीवन का ध्येय—पथ बन जाता है।

उद्योगों के समक्ष है बड़ी चुनौती

मित्रों, एक वैश्विक चुनौती आई थी कोविड की, बहुत संघर्ष करके उस भयानक काल खंड से निकल कर हम आगे आये। अब एक और चुनौती सामने खड़ी है ट्रम्प टैरिफ की। लेकिन यहां बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है, बल्कि टैरिफ की आड़ में पश्चिम के उस सोच की है जिसमें वो भारत को अपने समकक्ष खड़ा होते हुए देखना नहीं चाहते। अपनी शर्तों पर दुनिया के विकासशील राष्ट्रों पर व्यापार थोपना चाहते हैं और उनमें भी भारत निशाने पर सबसे ऊपर है। "लघु उद्योग भारती ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के अखिल भारतीय संगठन के रूप में सम्पूर्ण भारतवर्ष में जो प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता अर्जित की है, वो अनमोल है। उसका आंकलन करना सहज नहीं है, क्योंकि उसके लिए बीते तीन से अधिक दशकों में संगठन के निमित्त संगठनकर्ताओं और देवतुल्य उद्यमी सदस्यों का निष्काम भाव से किया गया कार्य है।"

वैश्विक जीडीपी में चीन से क्यों पिछड़ा भारत

केवल पांच दशक पहले चीन और भारत की जीडीपी लगभग समान थी, लेकिन आज चीन 17 ट्रिलियन डॉलर पर समृद्धि के दूसरे पायदान पर खड़ा है और हम 4 ट्रिलियन से कुछ ऊपर। ये बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण साफ है। सरकारों की अकर्मण्यता और ब्यूरोक्रेसी की अनिच्छा के साथ हम उद्यमियों की अदूरदर्शिता।

याद रखें, सिर्फ समय बदला है, लेकिन भारत के प्रति पश्चिम की नीति और नियत दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं आया। देश की तरक्की से कई विकसित राष्ट्रों को बेचैनी हो रही है और वे हमारे विकसित भारत के मिशन को नहीं पचा पा रहे। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग्य विधाताओं में भी भारत का नाम अभी तक शामिल इसीलिए नहीं हो पाया।

सामयिक परिदृश्य में आखिर मार्ग क्या ?

और इसे पाटने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना होगा हमें तीन काम करने होंगे— स्वदेशी का अवलम्बन, विदेशी खासतौर पर चीनी—अमेरिकी उत्पादों पर निर्भरता को न्यूनतम या खत्म करना और सामयिक तकनीक के साथ श्रेष्ठ और गुणवत्तापरक उत्पादों का निर्माण करना। हमें वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल तक जाना है और उसके लिए अपना विजन डेवलप करें।

संगठन में सदस्य अपने समय, श्रम और संसाधनों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा से अपने दायित्व का समुचित निर्वाह करते हैं, फिर भी कई बार अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। लेकिन हम जिस बड़े उद्देश्य को लेकर बढ़ रहे रहे हैं, उसमें हमारे मन में यही भाव रहना चाहिए —

राष्ट्र भक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा संकटों पर मात कर यह, राष्ट्र विजयी हो हमारा।



'SANT' Group Product Line

Valves









Forged Fittings









DI Grooved Fittings











DI Screwed Fittings











Water Meters











UL / FM Valves











SANT VALVES PVT. LTD. G.T.Road By Pass, Jalandhar 144012 (Pb.)

www.santvalves.com

Phone: 0181 508 4693/94/95 info@santvalves.com

लघु उद्योग भारती - प्रगति रिपोर्ट कार्यकाल वृत्त (2023-25)





प्रतिवेदन ओम प्रकाश गुप्ता राष्ट्रीय महासचिव लघु उद्योग भारती, नई दिल्ली gs@lubindia.com

लघु उद्योग भारती परिवार के आदरणीय सभी सदस्य गण, सादर नमस्कार !

प्रस्तावना-

25 अप्रैल, 1994 को लघु उद्योग भारती की स्थापना जिस ध्येय और संकल्प के साथ हुई थी, उसकी ली आपके सहयोग और विश्वास से और अधिक उज्ज्वल हो रही है। बीते 31 वर्षों में संगठन ने निरन्तर नित—नये आयाम प्राप्त किये हैं। उद्योग जगत के उत्थान, समाज की सेवा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लघु उद्योग भारती का योगदान आप सबके समर्पण से सम्भव हुआ है।

नयी कार्यकारिणी का गठन-

25 अगस्त, 2023 को दिल्ली में सम्पन्न अधिवेशन में, वर्ष 2023-25 के लिये नयी कार्यकारिणी का गठन हुआ। उस अवसर पर मुझे महासचिव का उत्तरदायित्व मिला। यह मेरे लिये सम्मान के साथ-साथ परीक्षा का अवसर भी था। माननीय डॉ. कृष्णगोपाल जी के मार्गदर्शन, माननीय श्री प्रकाश चन्द्र जी व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा जी के नेतृत्व और आप सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन के कार्य को गति मिली।

संगठन विस्तार-

आपके परिश्रम से संगठन के सदस्यों का विस्तार 596 जिलों में 1056 इकाइयों में 61931 सदस्यों तक पहुँच चुका है। विशेष रूप से 58 इकाइयों में 5196 महिला उद्यमियों के अतिरिक्त युवाओं का जुड़ाव भी संगठन को नई दिशा दे रहा है।

बैठकों और अधिवेशनों की भूमिका-

पिछले दो वर्षों में कोर कमेटी की 8, कार्यसमिति की 2, कार्यकारिणी की 4 और पदाधिकारियों की नियमित बैठकें हुईं। इनसे नीति—निर्धारण और कार्य योजना स्पष्ट हुई। प्रांतीय अधिवेशन और (तिथि/स्थान डालें) में राष्ट्रीय अधिवेशन ने कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और दृष्टि दी।

कार्यकर्ता प्रशिक्षण-

राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रांतीय नेतृत्व के साथ कई प्रशिक्षण सत्र हुए व अनेकों बैठकें हुईं। इनमें संगठनात्मक चर्चा के साथ—साथ उद्योग नीति, डिजिटलीकरण, गुणवत्ता मानक (QCO), MSME अधिनियम संशोधन, ई—कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इससे संगठन और उद्योग जगत दोनों की समझ बढी।

दिल्ली मुख्यालय में डिजिटल पहल-

दिल्ली में मुख्य कार्यालय में डिजिटल पहल के अंतर्गत डाटा इंटीग्रेशन की परियोजना शुरू की गयी। जिसमें प्रदेशों, प्रांतों, जिले व इकाई स्तर की जानकारियों संकलित करने का कार्य विधिवत तरीके से प्रारंभ किया गया। इसी कार्यकाल में 25 उत्पाद समूह व 25 आयाम निर्धारित किये गए। इनमें मुख्यतः Food — Agro, Plastic — Polymer, Footwear, Handicraft, Umbrella, Marble & Utensils तथा आयाम में Environment, Skill Development, Technology, Banking and Labour जैसे विषयों पर निरंतर बैठकें होती रहीं।

उद्योग टाइम्स-

उद्योग टाइम्स पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है तथा विभिन्न समसामयिक विषयों पर विशेष संस्करण भी प्रकाशित किये जा रहे हैं। इसमें उद्योग जगत के नीतिगत बदलाव, समस्याएं और उद्यमियों के अनुभव स्थान पाते हैं। इसका डिजिटल संस्करण भी अब अधिक उद्यमियों तक

उद्योग उत्थान विशेषांक

पहुँच रहा है। सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग टाइम्स मंत्रीगण, अधिकारीगण व अन्य संगठनों को नियमित रूप से भिजवाई जाती है।

प्रवास और संवाद-

राष्ट्रीय पदाधिकारीऔर संगठन मंत्री निरन्तर प्रवास पर रहे। उनके प्रत्यक्ष संवाद से कार्यकर्ताओं मेंउत्साह बढ़ा और स्थानीय समस्याओं का समाधान भी सरल हुआ। इन प्रवासों ने संगठन को मजबूती दी।

सोशल मीडिया और वेबसाइट-

2022 से सोशल मीडियाविभाग और अधिक सक्रिय हुआ।
LUB की उपस्थिति Facebook, Linkedin, X, Instagram,
Youtube तथा Whatsapp चैनल पर उपलब्ध है। सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन कम से कम 6-7 पोस्ट्स
साझा की जा रही हैं। वेबसाइट और मोबाइल ऐप को नया
रूप दिया गया। इससे संवाद और सूचना का प्रवाह तेज
हुआ।

मासकोम के अंतर्गत नयी पहल की गयी जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म, साप्ताहिक न्यूज़ लेटर, उद्योग टाइम्स, नॉलेज बैंक की पहल तथा डिजिटल स्टूडियो का कार्य भी दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है।

संगठन द्वारा निर्धारित 6 करणीय कार्य जैसे कि स्थापना दिवस, मासिक बैठक, विश्वकर्मा जयंती, उद्यमी सम्मेलन, स्नेह मिलन तथा उद्यमिता का कार्य निरंतर चल रहा है। इसके अतिरिक्त पंच परिवर्तन कार्य, व्यवस्था परिवर्तन चिंतन तथा आर्थिक समूह के साथ बैठकों में मौलिक चिंतन किया जा रहा है।

तकनीकी उन्नयन (Technology Upgradation) के नाते भी लघु उद्योग भारती ने नयी परियोजना के तहत CSIR के साथ MoU किया जिसमें 100 दिन में 100 तकनीकों का सफलतापूर्वक हस्तांतरण किया। इसके लिए 13 प्रयोगशालाओं में 700 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया। संगठन ने लघु उद्योगों को डिजिटली सशक्त करने के उद्देश्य से लीप ई—कॉमर्स प्लेटफार्म का निर्माण किया।

उद्योग और एकेडेमिया में सहयोग के लिए 12 विभिन्न संस्थाओं जैसे कि IIT, IIM, EDII और अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से एमओयू किये ताकि उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

गत दो वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसे कि MSME की नयी परिभाषा, मानक ब्यूरो द्वारा नए QCO लाना, ळैज के मुद्दे, बैंकिंग क्षेत्र, पर्यावरण, विदेशी व्यापार तथा जल विभाग से सम्बंधित विषयों पर सरकार के साथ संवाद तथा पत्राचार करके सुलझाने का प्रयत्न किया गया। विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों जैसे Ministry of Finance, Commerce & Industry, Environment, MSME, Transport, Labour & Employment and Skill Development के साथ लगातार संपर्क बनाये रखा।

दिल्ली भवन तथा कौशल विकास व प्रशिक्षण केंद्र-

दिल्ली मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालय व कौशल विकास केन्द्रों का निर्माण हुआ है जिनमें उल्लेखनीय सोहन सिंह समृति कौशल विकास केंद्र, जयपुर, जोधपुर, भोपाल हैं। यहां पर विभिन्न कौशल विकास तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं।

संगठन द्वारा QCI (Lean Management/ ZED), Net-zero Emission तथा SIDBI, NSIC इंस्टिट्यूट के साथ मिलकर निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

GeM के साथ समझौता करने के बाद सदस्यों को नियमित रूप से साप्ताहिक कार्यशालाओं द्वारा GeM Portal पर पंजीकरण तथा व्यापार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक 51 साप्ताहिक वेबीनार तथा अन्य केन्द्रों पर हुए सेमिनार में लगभग 4000 सदस्यों की सहभागिता रही। यदि हम मिलकर कौशल, तकनीक और विपणन पर ध्यान दें, तो लघु उद्योग आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन सकते हैं।

आभार-

पिछले दो वर्षों की इस यात्रा में संगठन के प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी और सहयोगी का अपार योगदान रहा। माननीय मार्गदर्शक डॉ. कृष्णगोपाल जी के मार्गदर्शन, श्री प्रकाश चन्द्र जी के प्रेरक नेतृत्व और अ. भा. अध्यक्ष, श्री घनश्याम ओझा जी के सतत प्रयासों के लिए विशेष आभार।

आप सबके सहयोग और समर्पण से ही यह कार्यकाल सफल और प्रेरक रहा। भविष्य में भी हम सब मिलकर संगठन को और ऊंचाइयों तक ले जायेंगे। इन दो वर्षों में अगर जाने—अनजाने में कोई भूल हुई हो, तो उदारतापूर्वक क्षमा करें।

LUB's Vision for a Future-Ready MSME Ecosystem Where Innovation Meets Industry

Empowering MSMEs through Strategic Technology Mapping & Academic Partnerships



Wide Angle
Dr. Arshpreet Kaur
Nodal Officer-Research & Industry
Collaborations, LUB's HO, New Delhi

In the evolving industrial landscape, technology adoption is no longer a luxury but a necessity for survival and growth. Laghu Udyog Bharati (LUB), with its nationwide presence and deep connections with the grassroots MSME ecosystem, has embarked on a mission to catalyze innovation-led growth by enabling access to cutting-edge research, indigenous technologies, and strategic collaborations with premier research institutions.

The Vision: A National Technology Mapping & Transfer Mission

The Technology Mission of Laghu Udyog Bharati aims to systematically map, disseminate, and facilitate the adoption of indigenous technologies by MSMEs across states. The mission is built on a structured framework to accelerate technology transfers from labs to production floors.

Key Objectives:

- Enhance MSME productivity, innovation, and global competitiveness.
- Address bottlenecks in awareness, accessibility, affordability, and adoption.
- Create state-level technology ecosystems for sustained industry-academia engagement.

The Mission Blueprint:

Dedicated State Technology Nodal Persons:
 Each state will have appointed nodal persons

responsible for driving technology transfers, organizing lab visits, and ensuring post-adoption support under the guidance of LUB's National Head Office at New Delhi.

Technology Transfer Targets:

Realistic and measurable targets to be set based on state-wise industrial capacity:

Mandatory Lab Visits:

Nodal Persons will facilitate at least two lab visits per year per state. These engagements aim to bridge trust gaps and initiate collaboration opportunities between MSMEs and scientists.

· Standard Operating Protocols (SOPs):

A uniform reporting and documentation mechanism will be implemented through visitor documentation formats, event reporting templates, follow-up mechanisms for LOIs and warm-to-hot lead conversions and unique ticket-based tracking for each technology engagement.

Centralized Digital Dashboard:

A real-time tracking system will monitor Statewise monthly progress, LOI follow-ups, Tech transfer and commercialization status. This tool will empower timely intervention and bottleneck resolution at the central level.

Industry Sensitization Seminars:

Each state will organize at least two awareness programs per year, helping MSMEs understand the value proposition of technology and how to avail themselves of LUB's facilitation.

 Impact Documentation & Feedback: Quarterly surveys and MSME testimonials will help measure outcomes and feed into continuous improvement. Impact stories will be published to motivate broader participation and policy advocacy.

Building Strong Bridges with Academia:

LUB's industry-academia initiative goes beyond technology transfer; it actively facilitates expert guidance to MSMEs on operational, product, and process challenges. Through structured collaborations with top institutions, LUB envisions helping small businesses not only adopt innovations but also solve real-world problems with the help of domain experts.

In pursuit of this, Laghu Udyog Bharati (LUB) has been actively collaborating with premier academic and research institutions across India. Recent MoUs include:

- Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) under the initiative "100 Days 100 Technologies" for rapid technology transfer to SMEs. CSIR technologies cover diverse fields such as advanced materials, chemicals, agri-tech, energy, water treatment, healthcare, engineering solutions, food technology and more. You can explore these technologies at the following link: https://techindiacsir.anusandhan.net/online/Contr ol.do
- Indian Institutes of Management (IIMs) for entrepreneurial upskilling, strategic capacity building, skill development and targeted training programs on entrepreneurship, digital transformation, financial literacy, Management Information Systems (MIS) and advanced management. To learn more about IIM Mumbai, refer to https://iimmumbai.ac.in/
- Atal Incubation Centre at Guru Gobind Singh Indraprastha University (GGSIPU) for providing support and guidance for digital marketing, consulting on lean product development, design thinking and low-cost prototyping to foster innovation within budget constraints. For more information about incubation and innovation support for startups and MSMEs provided by AIC GGSIPU, please see: https://aicggsipu.org/
- Indian Institute of Technology (IIT) Ropar and Defence Research & Innovation Foundation (DRIF) for strengthening MSME participation in the Defence & Aerospace sectors, addressing research requirements of the industry, product

- development, process upgradation and improvisation. Know more about IIT Ropar at https://www.iitrpr.ac.in/
- Zakir Husain Delhi College, University of Delhi, for internships with SME. View College details at https://www.zakirhusaindelhicollege.ac.in/

These collaborations aim to enhance technology adoption, skill development, R&D partnerships, and policy advocacy, thereby strengthening MSMEs and building a future-ready industrial ecosystem.

We have also collaborated with:

- Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) for addressing succession planning in family businesses (https://ediindia.org/). Many family businesses face succession crises when leadership is passed from one generation to the next. EDII provides expert guidance and training to ensure a smooth transition and sustainable growth.
- Vidyalankar Polytechnic (VP) for framing SOPs for Industry 4.0, internships, industrial visits and consultancy to bridge the gap between academia and industry

(https://vpt.edu.in/diploma/polytechnic/)

The Way Forward: A Movement, Not Just a Mission

Our goal is not just technology transfers; it is about creating a national movement for innovation among small enterprises. With over 55,000 LUB members, the scale and spirit of collaboration can truly redefine India's industrial future.

We call upon all our members to participate actively; share your challenges, join lab visits, explore technologies, and contribute to a self-reliant industrial Bharat.

Let's shape a future where India's smallest factories build the biggest innovations; powered by our own scientists, incubated in our own labs, and adopted by our own entrepreneurs.

Together, we build not just businesses; but Bharat's technological self-reliance.

For queries or your enterprise's problem statements, write to us on mail:

industryacademia.lub@gmail.com net-zero@lubindia.com or contact at 9650226899



Empowering Women Entrepreneurs through Swayamsiddha Exhibitions

Total 62 B2C Exhibitions have been organized in 5 states with Brand Name Swayamsiddha. More than 6000 Women Entrepreneurs have showcased their products. Now, in the next phase, this Exhibition is ready for becoming an international event soon.



Journey
Anju Bajaj
National Secretary
Laghu Udyog Bharati, New Delhi
bajajanju55@gmail.com

Over the past few years, the Swayamsiddha Exhibitions have evolved into a remarkable platform for women entrepreneurs across India. Spearheaded by the Women Wing of Laghu Udyog Bharati, these exhibitions have successfully showcased women-led enterprises, fostered self-reliance, and promoted traditional crafts and modern innovations alike.

A Nationwide Movement-

From its inception in 2021, Swayamsiddha has grown to become a nationwide movement. Over 60 exhibitions have been organized across states including Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, and Assam, both in physical and virtual modes.

These events have served as a bridge connecting women entrepreneurs with markets, policymakers, and consumers.



Swayamsiddha means that which is selfproven, that is, complete in itself and not dependent on anyone in any way.

First Women Unit at Ujjain

Recalling the journey of Swayamsiddha, the LUB's Madhya Pradesh State Head Women's Work Smt. Uma Sharma said that the country's first women's unit of the organization was formed in Ujjain in the year 2012, in which the unit's President Smt. Prerna Dabade and Secretary Smt. Seema Vaidya were given the responsibility. On this occasion, about 120 women displayed their products in the exhibition.

The First Mahila Udyami Sammelan was also organized by the Ujjain unit on 8th April, 2015 in which more than 800 women participated. On this occasion,

Swayamsiddha Exhibitions at a glance

Assam - 01
Madhya Pradesh - 19
Punjab - 02
Rajasthan - 40
Total - 62

उद्योग उत्थान विशेषांक

an exhibition of handicraft and other products made by women associated with the cottage industry was also organized. This Exhibition was inaugurated by Smt. Yashodhara Raje Scindia.



State Joint General Secretary of Laghu Udyog Bharati Rajasthan, Smt. Manju Saraswat said that Jodhpur Women Wing organized a successful exhibition named "Shakti" under the Atmanirbhar Bharat Flagship Scheme in 2021. But due to the Corona epidemic, it was not physical but virtual.



First Swayamsiddha Exhibition at Bhopal

But in the year 2021, the first Swayamsiddha exhibition was formally organized in Bhopal and more than 100



women entrepreneurs participated in it. In this exhibition, the village craftsmen also demonstrated their skills.

After this, the women's unit of Jaipur Anchal started a wonderful series of Swayamsiddha exhibitions. In this series, three exhibitions were also organized in the City Palace of Jaipur with cooperation of then MP Smt. Diya Kumari.



Celebrating Local Talent and Enterprise

Each exhibition reflects India's rich cultural and entrepreneurial diversity. Whether it was the Diwali Mela in Jodhpur, the Mahila Samruddhi Pradarshani and the Swavlambi Bharat Trade Fair in Katni, these events have provided a marketplace for MSME and non-MSME stalls featuring handicrafts, textiles, jewellery, food products, and innovative services. Attendance figures highlight their growing impact, with some exhibitions hosting over 100 participants.

According to Smt. Anju Singh, associated with Swayamsiddha Aayaam, to promote women entrepreneurship under Swayamsiddha, specific skill training will be started for women of rural and urban areas so that they can strengthen themselves financially by generating employment. Many such entrepreneurship programs were organized by the various departments of the Govt, of India in which women started enterprises related to sewing, handicrafts, food industry and cow products.

Key Highlights and Impact

Empowerment Through Exposure:

Women entrepreneurs have gained exposure to national markets, branding opportunities, and valuable networking with industry stakeholders.

Regional Outreach:

Rajasthan led with 40 exhibitions, followed by



Madhya Pradesh with 19, reflecting strong regional participation.

Supportive Ecosystem:

Organized in collaboration with various industry bodies, the exhibitions have also provided training and guidance on marketing, digital tools, and government schemes.

Beyond Business - Building a Self-Reliant Bharat

Swayamsiddha goes beyond commerce; it nurtures confidence among women to take their ventures forward. It has amplified the voices of women from small towns to urban centers, fostering inclusivity and economic independence.

The upcoming national calendar for 2025–26 envisions even more extensive outreach, with a planned 62 exhibitions across India. These will continue to strengthen the Atmanirbhar Bharat (self-reliant India) vision, focusing on women-led growth.

Women in New Role and Identity

The success of the Swayamsiddha Exhibitions exemplifies how community-driven initiatives can empower women, boost entrepreneurship, and celebrate India's cultural heritage. As the movement expands, it promises to inspire countless more women to step into the entrepreneurial world with confidence and pride.

Laghu Udyog Bharati has worked for the empowerment of thousands of women through women units. Today women are moving on the path of progress with their new identity and new role. Swayamsiddha platform has proved to be a better platform for marketing and showcasing their products and in future there is a plan to organize this exhibition at the international level.



When it Comes to Delivering the Best Healthcare We Go the Distance



When it comes to your health, Nothing but the best would do. 800 Beds | 21 Modern Operation Theatres | 3500+ Dedicated Medical Professionals

OUR ACCOMPLISHMENTS



Experience of 25000+ Joint Replacement Surgeries



One of North India's Most Comprehensive Cancer Centre with Experience of 300+ BMTs



Vast Experience of Successful Complex Neurosurgeries (Brain & Spine Surgeries)

Centres of Excellence

- · Cancer Care & Surgical Oncology
- . Hematology & Bone Marrow Transplant
- . Radiation Oncology & Nuclear Medicine
- · Dialysis & Kidney Transplant
- · Brain and Spine Surgery

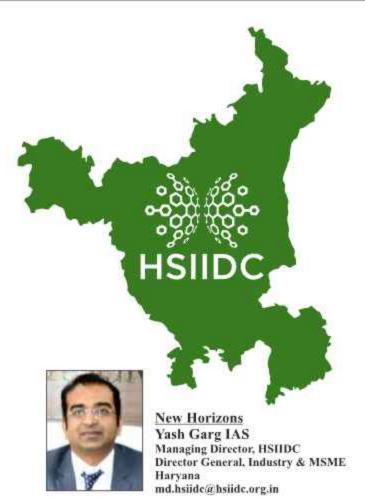
- · Advanced Cardiac Care
- · Robotic Joint Replacement
- · Institute of Robotic Surgery
- . ENT & Cochlear Implant
- Adult to Paediatric Orthopaedics
- Paediatric Cardiology & Cardiac Surgery
- · Paediatrics
- Paediatric Surgery
- Urology





Haryana's 1" Hospital to be Accredited with American Accreditation Find us online





Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Ltd. (HSIIDC), established in 1967, is a premier government-owned entity under the aegis of the Government of Haryana. As the nodal agency for industrial infrastructure development, HSIIDC plays a pivotal role in transforming Haryana from a primarily agrarian state into one of India's most industrialized regions.

HSIIDC is committed to fostering economic growth by providing state-of-the-art infrastructure, facilitating industrial investments, and supporting new enterprises with a comprehensive suite of services under its "Total Industrial Support" model. The corporation has successfully developed numerous Industrial Estates and Industrial Model Townships (IMTs) across the state, including major hubs like Gurugram, Faridabad, Manesar, and Panipat.

Features:

- Government of Haryana Undertaking 100% ownership.
- Catalyst for Industrial Growth Developed land bank for Industrial, Residential, Commercial and Institute usage.

HSIIDC

True Commitment for Industrial Development of

New Haryana

 Mega Projects – Western Peripheral (Kundli-Manesar –Palwal) Expressway, Global City Gurugram, Integrated Multi-Modal Logistic Hub, Nangal Chaudhary, etc.



- Diversified Revenue Streams Includes industrial, commercial, residential and institutional land sales, mining operations, toll collections, and service charges.
- Sustainability Focus Develops green belts, sewage treatment plants (STPs), and common effluent treatment plants (CETPs).
- Industry-Specific Initiatives & Achievements

Automotive Secto

- Haryana produces two-thirds of India's passenger cars, 60% of motorcycles, and 50% of tractors.
- Maruti Suzuki announced a ₹7.410

उद्योग उत्थान विशेषांक

croreinvestment for its third manufacturing plant at **Kharkhoda**, reinforcing Haryana's position as an automotive hub.

 Uno Minda is building a new alloy-wheel plant at IMT Kharkhoda with an investment of ₹542 crore, expecAted to produce 1.2 lakh wheels/month.

Textiles

- HSIIDC has developed a Textile Hub in Panipat, supporting both traditional and modern textile enterprises.
- The Atmanirbhar Textile Policy 2022–25 has been extended till December 2026, with the cap removed on cases under the Capital Investment Subsidy scheme.



Electronics & IT

- Haryana is a top exporter of software and electronics, with exports of electric machinery reaching \$462.5 million in FY21.
- HSIIDC has developed the Electronics Manufacturing Cluster at IMT Sohna and Electronic Hardware Park at Kundli, attracting investments in ESDM (Electronics System Design & Manufacturing)
- MSMEs
- Haryana's MSME ecosystem thrives in sectors like automobile, food & beverages, textiles, engineering, and metals.
- HSIIDC supports MSMEs through infrastructure like Common Facility Centers (CFCs), Footwear Park (Bahadurgarh), and Apparel Park (Barhi).
- The Haryana Enterprises and Employment Policy (HEEP) 2020 provides fiscal incentives, skill development, and export facilitation for MSMEs.

2) Recent Achievements (2024-2025)

 Strategic Investment Partnership with Toyota Boshoku: HSIIDC allotted 21 acres of land at IMT



- Bawal, Rewari to Toyota Boshoku Device India Pvt. Ltd. for a new manufacturing facility. The project involves a capital investment of ₹434 crore and is expected to generate 1,500 jobs, boosting the "Make in India" initiative.
- MoU with Central Bank of India:
 Signed in May 2025, this partnership aims to enhance industrial financing in Haryana, offering better credit access and financial services to MSMEs and large enterprises.
- Launch of New Citizen Services:
- Under the Right to Service Act, HSIIDC introduced three new services with strict delivery timelines:



- Mortgage permission within 2 days
- Provisional Transfer Letter (PTL) within 45 days
- Final Transfer Letter (FTL) within 7 days. These services improve transparency and ease of doing business.



- During the 50 years of its existence, HSIIDC has driven industrialization in the state through development of 36 Industrial Estates including 6 Industrial Modal Township & Theme Parks- over an area of 35000 acre.
- Land Procurement & Valuation Initiatives: HSIIDC is actively procuring land for new industrial areas and has initiated a transparent land valuation process to ensure fair market pricing.

3) Why Partner with HSHDC

- Partnering with HSIIDC offers unmatched credibility and strategic value. As a governmentbacked institution with decades of industrial leadership, HSIIDC aligns your initiative with Haryana's vision for inclusive and sustainable growth.
- Credibility & Legacy: Trusted by global investors and industry leaders.
- Sectoral Reach: Strong presence in automotive, textiles, electronics, food processing, and MSMEs.
- Infrastructure Excellence: 6 IMTs, 24 Industrial Estates, 11 Theme Parks, and multiple SEZs.
- Policy & Investment Support: Single-window clearance, capital subsidies, and export facilitation.
- Sustainability Commitment: Clean air initiatives, CETPs, and green corridors.
- HSIIDC has pioneered the concept of Industrial

- Model Township's (IMTs) based on mix land use sites for Industrial, Residential, Commercial & Institutional developments providing a unique ecosystem to facilitate walk to work:
- These Industrial parks are thriving locations of industrial & business, approx. 11137 number of Industrial Plots allotted. Major companies and industries like Maruti Suzuki, Honda, Denso, Unitech, Mitsubishi, ATL, Asian Paints, Yokohama, Coca-Cola, Pepsi, Yakult, Danone, Indian Institute of corporate Affairs, National Institute for Food Technology, Entrepreneur & Management (NIFTEM) etc. operate out of these Industrial Estates.
- Ease of doing business support is provided through the Estate Management Procedures (EMP), which lays down clear guidance for allotment of plots, payment schedule, implementation, leasing/ transfer of plots etc. These activities are also governed the right to service at specifying timelines delivery of major services.
- The plots are allotted as plug & play condition (with primary infrastructure like road, water, power, & sewer connection) enabling the allotties to start project implementation immediately after getting all necessary approvals.



KBS CERTIFICATION SERVICES LTD.



Our Services

Sustainability Services

ESG Assurance, ISO 14064-GHG, CBAM Readiness Consulting, GHG Certification, Sustainability Assurance Assessment Reasonable & Limited, Net Zero Assessment, Water Foot printing. World Commission of Dams Assessment, Global Reporting Initiative Carbon Neutrality as per PAS 2060, Airport Carbon Accreditation Service (ACA Level 1 to 4)

Management System Certification Services





Product Certification Services

- . CE Marking
- · REACH
- · GOST-R Certification
- RoHS Compliance among others



Training Services

Lead Auditor, Lead Implementer, Internal Auditor & Awareness Training for ISO 9001, 14001, 45001, 22000, FSSC 22000 V6, 22301, 27001, 50001, 42001, 14064 courses among others.

Climate Change Services

- Validation, Verification and Associated Services under various GHG Crediting Programs/ Schemes like: CDM, Gold Standard for Global Goals (GS4GG), VCS, CCB (Climate, Community & Biodiversity), SD Vista, Puro Earth, Global Carbon Council, BioCarbon Standard, Social Carbon, Open Forest Protocol, JCM, NABCB, CERCARBONO, UCR, Plan VIVO, ICR, ISOMETRIC, Global Emission Standard and COLCX among others.
- Validation and Verification for International Emission Reduction Projects and Programmes (under Article 6.2 Mechanism of the Paris Agreement) by the Climate Division of Federal Office of the Environment. (FOEN), Government of Switzerland.

Second Party Inspections

Energy Audits with certified energy auditors; Life Safety and Fire Safety Audits; Environmental Safety Audits; Hygiene, Workplace and Behavioral Safety, Electrical Safety Audits; Safety and Environmental Performance Ranking: Emergency Preparedness Audit; Incident and Accidents Investigation, Corporate Safety Strategy & Framework Design and Advisory, Safety and Environment legal compliance; Establish Safety Culture; Resource Management Compliance(Raw Material and Waste); Rating/Scoring of EOHS system, Compliance and conformity level for Industrial 4 revolution among others.

Third Party Inspections

Energy Audits: Social Assessment, Environment Impact Assessment, Supply Chain Assessment, Customer Satisfaction Assessment, Vendor Capacity and Capability Assessment, Product Stage - Raw materials, in-process, Pre-Dispatch Assessment ; Infrastructure inspections; Product Performance Witness in Certified Laboratory, Performance Assessment of Vendor and Product Performance among others.



+91 9971998084



info@kbscertification.com



www.kbscertification.com

An Emerging Industrial Powerhouse

The Government of Odisha has consistently worked to transform the state into one of India's most attractive destinations for investment and industry. With a strong foundation of natural resources, strategic location, progressive policies, and modern infrastructure, Odisha today offers a dynamic ecosystem for businesses across sectors.

The State of Odisha combines mineral wealth, port connectivity, and a skilled workforce with proactive governance to provide a competitive edge to investors. The state's long-term vision, articulated through Odisha Vision-2036 and Vision-2047, charts a clear roadmap for inclusive, sustainable, and future-ready industrial growth.

Investment Momentum in recent times

In the past one year, Odisha has witnessed an unprecedented surge in industrial investments, with 228 large projects approved across diverse sectors amounting to over ₹ 6 lakh crore and creating employment potential for more than 3.57 lakh people. The investments span core sectors like steel and aluminium, petrochemicals and logistics, speciality chemicals, green hydrogen and rare earths, textiles and apparel, and electronics and semiconductors, among others. Further, more than 56 projects with an investment of more than ₹ 1.78 lakh crore have already been grounded, with 25 more projects worth around ₹ 24 thousand crore lined up for ground breaking on 15th Sep 2025.

The recent surge of investments reflects the trust of national and global investors in Odisha's policies and infrastructure. Notable projects include:

 Vedanta Group's ₹1.28 lakh crore aluminium smelter in Dhenkanal.



Mohan Charan Majhi Hon'ble Chief Minister, Odisha

- SRF Ltd. ₹10,000 crore speciality chemicals plant in Ganjam.
- Semiconductor MoUs worth ₹2,655 crore, with collaborations involving global partners.
- ₹1,113 crore biotechnology development scheme, aligned with Odisha's Biotech Policy.
- Green hydrogen, LNG, and solar projects in Gopalpur and Paradip.
- Indian Oil Corporation's ₹61,000 crore naphtha cracker project at Paradip.
- Ease of Doing Business & Deregulation

Odisha has been recognized nationally for its business reforms. The state pioneered a **Single Window**Clearance System backed by legislation, and its digital platform GO SWIFT integrates services across the entire investment lifecycle.

In addition to digital upgrades, Odisha has been a frontrunner in deregulation reforms aimed at

उद्योग उत्थान विशेषांक

reducing the cost of compliance for businesses. Key measures include the reclassification of non-polluting industries into White Category, flexible zoning frameworks to optimise land use, revision of working hours for factories and establishments, and adoption of investor-friendly inspection and self-certification systems. These reforms, aligned with initiatives like the Jan Vishwas Bill, have made Odisha's regulatory environment simpler, faster, and more predictable.

Industrial Infrastructure

To complement policy reforms, Odisha has invested in modern, ready-to-use infrastructure:

- Industrial land bank managed by IDCO, with ready plots in strategic locations such as Gopalpur, Dhamra, Kalinga Nagar, Jharsuguda, Paradip, and other strategic industrial districts of the state.
- New sector-specific parks are being developed, including Textile & Apparel Parks, a Medical Devices Park, Food Processing Parks, and Electronics Manufacturing Clusters, etc.
- Plug-and-play estates with pre-built sheds, common utilities, and logistics support are operational across major clusters.
- Worker hostels and amenities are being created in industrial estates to ensure a skilled workforce base:

The sectoral distribution of industries reflects Odisha's balanced approach to growth: Kalinga Nagar (steel & downstream metal), Jharsuguda (aluminium & power), Gopalpur (chemicals, green hydrogen, rare earths), Balasore (textiles, plastics, defence),

Rayagada and Koraput (food processing, agro-industries), Paradip (petrochemicals, logistics, energy), and Bhubaneswar (IT, ESDM, semiconductors).

This spread ensures inclusive industrialisation across coastal, mineral-bearing, and urban districts alike.

Sectoral Opportunities

Odisha's industrial base is now highly diversified. Core strengths in steel, aluminium, and downstream



industries are complemented by rapid growth in chemicals, semiconductors, green energy, biotechnology, textiles, and food processing.

A progressive incentive framework under Industrial Policy Resolution 2022, MSME Policy 2022, and other sector-specific policies offers land and capital subsidies, tax reimbursements, employment cost support, and special benefits for green and inclusive projects. The Startup Odisha initiative nurtures innovation and entrepreneurship, further enriching the ecosystem.

The Road Ahead

Odisha is steadily positioning itself as the industrial hub of eastern India and a rising global destination for investment. With its reform-oriented governance, sectoral diversity, and future-ready infrastructure, the state offers unmatched opportunities for entrepreneurs and enterprises seeking long-term growth.

The Industries Department, Government of Odisha, welcomes businesses across India and abroad to partner in this journey of shared prosperity.







एमएसएमई विकास नीति-2025 के लाभ (Benefits)



1. निवेश और वित्तीय सहायता

- सूक्ष्म व लघु इकाइयों को 40% तक पूंजी अनुदान, मध्यम इकाइयों को 7 वर्ष तक।
- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 60% तक अनुदान।
- मशीनरी, टूल्स, डाई, जिग, स्पेयर पार्ट्स,इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन पर भी सहायता।
- पेटेंट/आईपीआर पर अधिकतम 50 लाख तक सहायता।
- ISO, BIS, BEE, ISI, AGMARK आदि प्रमाणन पर 100% अनुदान, अधिकतम 20—50 लाख तक।



माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

- निर्यात इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन (निर्यात प्रदर्शन आधारित 1.3 गुना तक)।
- रोजगार सृजन पर 2 गुना तक मल्टीपल लाभ।
 प्राथमिकता क्षेत्र (कम औद्योगिक घनत्व वालेजिले) में अतिरिक्त 1.5 गुना लाभ।
- फ्रेंट सब्सिडी निर्यात के लिए 40 लाख / वर्षतक।
- सौर ऊर्जा संयंत्र 2 करोड़ तक अनुदान।



2. हरित एवं आधुनिक उद्योग लाभ



चैतन्य कश्यप माननीय मंत्रां, एमएसएमई

- ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों पर 50% अनुदान।
- लघु इकाइयाँ 50 लाख तक, मध्यम इकाइयाँ —2.5 करोड तक।
- आधुनिक तकनीक, IoT, Lean Tools, Testing Labs, AI और Robotics आधारित मशीनों पर 40-50% तक अनुदान।
- SME IPO कराने पर 40 लाख तक सहायता ।

3. औद्योगिक क्षेत्र व क्लस्टर विकास लाभ



- निजी औद्योगिक क्षेत्र / क्लस्टर विकसित करने पर 50% तक विकास लागत, अधिकतम 40 करोड़।
- फ्लैटेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर 50-60% सहायता, अधिकतम 40 करोड।
- फर्नीचर, टॉय, फुटवियर आदि क्षेत्रों को विशेष पैकेज।

4. विशेष पैकेज लाभ

(क) इथेनॉल इकाइयाँ

- 1.50 रु. / लीटर उत्पादन पर सहायता।
- स्टांप ड्यूटी व पंजीयन शुल्क पर 100% छूट।
- मंडी शुल्क में 50% तक छूट।
- प्रशिक्षण लागत-10,000रु. / नए कर्मचारी (उसाल तक) ।

(ख) वाहन स्क्रैपिंग

- पूंजी अनुदान —10% (1 करोड़ तक) एवं 20% (3 करोड़ तक)।
- स्टांप ड्यूटी छूट 25 लाख तक।

- ISO प्रमाणन पर 10 लाख तक।
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु 25 लाख तक।

(ग) सर्कुलर इकॉनॉमी

- वेस्ट रीसाइक्लिंग व ट्रीटमेंट पर 40: अनुदान (2 करोड़ तक)।
- इलेक्ट्रिक वाहन इकाइयों को अतिरिक्त 10: लाभ।

(घ)लॉजिस्टिक्सव वेयरहाउसिंग

- स्थायी पूंजी निवेश पर 30: अनुदान, 12.5 करोड़ तक।
- स्टांप ड्यूटी व पंजीयन शुल्क 100% छूट।
- पावर ड्यूटी से 7 वर्ष की छूट।
- गुणवत्ता प्रमाणन पर 5 लाख तक।
- रोड व रेलवे साइडिंग विकास पर 1.5 करोड़ तक।
- सौर संयंत्र हेतु 2 करोड़ तक।

5. क्षेत्र-विशेष लाभ

- टेक्सटाइल सेक्टर बिजली पर 2 रु. / यूनिट की छूट,
 7 साल तक।
- फार्मा सेक्टर WHO-GMP/USFDA प्रमाणन पर 1 करोड़ तक सहायता, टेस्टिंग लैब पर 50 लाख तक।
- फूड प्रोसेसिंग बिजली पर 1 रु./यूनिट छूट, मंडी शुल्क में 50: तक राहत।
- फर्नीचर, टॉय, फुटवियर बिजली छूट, ट्रेनिंग लागत
 10,000 रु./कर्मी, रोजगार सब्सिडी 5,000 रु. /माह/कर्मी।
- रेडीमेड गारमेंट्स-बिजली पर 2 रु./यूनिट छूट (7 वर्ष),
 ब्याज सब्सिडी 5% (7 वर्ष), ट्रेनिंग लागत 13,000 रु. / कर्मी ।



Haryana's Industrial Transformation: Growth, Investment & HSIIDC's Pioneering Initiatives



New Dimension Sunil Kumar Industry Coordinator HSIIDC

Haryana - The Heart of Emerging India

Haryana has rapidly evolved into one of India's foremost industrial and economic powerhouses. Its strategic location, proximity to Delhi, world-class infrastructure, and investor-friendly policies have positioned it as the "Heart of Emerging India." Despite covering just 1.34% of India's area, the state contributes approximately 3.6% to the national GDP, underscoring its remarkable industrial output.

In the last decade, Haryana's Gross State Domestic Product (GSDP) has expanded 2.78 times, growing from ₹4.35 lakh crore in 2014-15 to an estimated ₹12.1 lakh crore in 2024-25. The contribution of industry to the Gross State Value Added (GSVA) has also seen a significant jump from 27% to nearly 33%, signaling the state's strong pivot toward manufacturing and industrial activities.

Gurugram, referred to as the 'BPO capital of India,' has long been a thriving ahub for IT and outsourcing services, hosting numerous multinational corporations and shaping India's global outsourcing leadership.

Between 2019 and 2024, Haryana attracted INR 1.76 lakh crore in Foreign Direct Investment (FDI), reflecting the confidence of global investors in its industrial ecosystem.

Infrastructure Development: Catalyzing Haryana's Industrial Growth

A major factor behind Haryana's industrial success is



Nayab Singh Saini Hon'ble Chief Minister, Haryana

its strategic location. With nearly two-thirds of its territory within the National Capital Region (NCR), Haryana 'enjoys unmatched access to one of India's largest consumption and trade centers, Well-connected through expressways, highways, and freight corridors, the state offers seamless logistics, making it an ideal destination for warehousing, distribution, and manufacturing operations.

Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC)

Haryana is an integral part of the DMIC, one of India's most ambitious infrastructure initiatives aimed at enhancing connectivity between Delhi and Mumbai through industrial townships, freight corridors, and logistics hubs. With direct access to highways, expressways, and rail links, Haryana's participation in DMIC has attracted auto, engineering, and electronics sectors, reinforcing its role as a manufacturing powerhouse.

Amritsar-Kolkata Industrial Corridor (AKIC)

उद्योग उत्थान विशेषांक

The AKIC aims to create a seamless trade and manufacturing route across North and East India. Haryana's strategic location provides access to this corridor, enabling the state to tap into larger national supply chains and expand its export capabilities, especially in sectors like textiles, electronics, and agroprocessing.

Strategic Connectivity: Hisar is a very strategic place it has proximity to both AKIC and DMIC, i.e. Eastern and Western DFCs, along with access to National



Highways NH-52 and NH-09. New Aviation hub at Hisar is being developed.

Urban Extension Road-II (UER-II)

The UER-II project enhances last-mile connectivity around Delhi's periphery, linking industrial areas in Haryana to key consumption centers and freight nodes. It supports Haryana's industrial estates by reducing transportation time, enabling efficient logistics, and ensuring uninterrupted supply chains for both domestic and international trade.

A 75.71 km access-controlled expressway designed to decongest Delhi and enhance connectivity between Haryana and the National Capital Region (NCR).

Key Features: 54.21 km stretch in Delhi and 21.50 km in Haryana. Direct links to Bahadurgarh and Sonipat, improving industrial connectivity. Integration with major highways like NH-44 and NH-48 facilitates efficient goods movement.

Kundli-Manesar-Palwal Expressway (KMP Expressway)

Acting as a peripheral expressway, KMP connects northern and southern parts of Haryana, easing congestion, accelerating goods movement, and providing connectivity to major industrial townships like Manesar, Bawal, and Sohna. It plays a critical role in enabling auto manufacturing, electronics clusters, and warehousing hubs.

Regional Rapid Transit System (RRTS)

The Delhi-Panipat RRTS corridor is a high-speed regional rail project that connects Delhi with northern Haryana. Spanning approximately 103 km, the corridor links key urban centers such as Kundli, Gannaur, Samalkha, and Panipat. This is designed to integrate seamlessly with metro and rail networks in the NCR.

The RRTS will drastically reduce commute times, offering safe, reliable, and fast transportation. It is expected to catalyze economic development by improving access to healthcare, education, and employment, while facilitating smooth passenger and freight movement in one of India's most densely populated regions.

Haryana Orbital Rail Corridor (HORC)



The Haryana Orbital Rail Corridor is aimed at creating a high-speed rail loop connecting Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar, and Kharkhoda. With a total length of 121.7 km, the corridor will link major industrial and logistics hubs across the state.

HORC's integration with existing railway lines and freight corridors will facilitate multimodal logistics, reduce congestion, and support the growing industrial ecosystem by providing efficient transportation corridors across Haryana.

Haryana's Industrial Landscape: Sector-wise Achievements

1. Information Technology & IT-Enabled Services

Gurugram stands as a major hub, hosting global technology firms such as Google, Microsoft, IBM, Oracle, Cisco, Wipro, HCL, Genpact, and Aricent (Altran). Leveraging Haryana's talent and infrastructure, these companies serve global clientele and expand digital solutions.

2. Automotive & Engineering

Haryana is home to major automotive players like Hero MotoCorp, Hero Electric, Suzuki, RICO Auto Industries, Denso, and Pricol.

3. Consumer Goods & FMCG

Leading brands such as Nestlé, Perfetti Van Melle, Amul, Yakult, and Danone operate in Haryana, benefiting from logistical efficiency and access to the NCR market.

4. Pharmaceuticals & Healthcare

Haryana's medical sector is witnessing rapid growth with investments from Baxter, and Agilent Techno-



logies. The state's healthcare infrastructure and focus on medical tourism are set to bolster this sector's expansion.

5. Industrial & Manufacturing Giants

Global engineering and industrial players such as Siemens, Mitsubishi, Asian Paints, Duracell, and Asahi India Glass (AIS) highlight Haryana's capabilities in advanced manufacturing.

6. Financial Services & Consulting

Gurugram's rise as a financial hub is marked by the presence of firms like American Express, Tata Consultancy Services (TCS), and Hughes, supporting Haryana's knowledgedriven economy.

Future-Focused Projects Global City Project -Gurugram

Spanning over 1,000 acres, this mixed-use smart city integrates commercial, residential, and cultural zones. With 25% of Phase 1 infrastructure completed, the project is set for full completion by 2026.

Electronics Manufacturing Cluster (EMC) - Sohna

A 500-acre facility with industrial plots, warehouses, incubation centers, and 24/7 power supply supports electronics manufacturing under the EMC 2.0 initiative.

Expansion of Industrial Model Townships (IMTs)

Haryana is developing 10 new IMTs and mixed-use townships, with seven locations including Rai, Ambala, Jind, Sohna, Faridabad, Bawal, and Kharkhoda actively progressing.

Haryana's industrial journey is a testament to strategic vision, robust infrastructure, and forward-thinking policies. As it continues to attract investments across sectors-from automotive to electronics, FMCG to textiles-the state is not only shaping its own economic future but also contributing to India's growth on the global stage. With projects like the Global City in Gurugram and EMC Sohna, supported by HSIIDC's sound governance, Haryana is well on its way to becoming a model for sustainable and inclusive industrial development.





LAGHU UDYOG BHARATI PUNJAB



LAGHU UDYOG BHARATI

HOSHIARPUR



LAGHU UDYOG BHARATI

BATHINDA



LAGHU UDYOG BHARATI

MOHALI



LAGHU UDYOG BHARATI

AMRITSAR



Revolutionizing Business: Delhi Gov't & MCD's Landmark Move Towards 'Ease of Doing Business'







Mayor, MCD

Udyog Times Desk

In a progressive stride towards fostering a businessfriendly environment, the Delhi government and the Municipal Corporation of Delhi (MCD) have initiated a significant reform that simplifies the licensing process for factories in the city. The new order, which recognizes existing business registrations and property documents as fleemed" factory licenses, is a testament to the commitment to promote 'Ease of Living' (EoL) and 'Ease of Doing Business' (EoDB).

Reducing Redundancy and Compliance Burdens:

The previous system of requiring a separate factory license from the MCD for units in governmentrecognized industrial areas was an additional, redundant compliance burden. The new order correctly identifies that such a license did not offer any substantial contribution to the factories, as other regulatory bodies already handle critical compliance aspects. The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) enforces environmental norms, the Delhi Fire Service ensures fire safety, and the MCD itself factors in structural safety when sanctioning building plans. This new approach eliminates the need for a separate, duplicative process, showcasing a forward-thinking policy that trusts existing regulatory frameworks.

A Streamlined and Fairer Fee Structure:

The former fee structure, based on the electric power (HP) used by a factory, was flawed. It effectively taxed

mechanization and introduced distortions in verifying horse power. The new system replaces this with a simple and fair fee of 5% of the property tax. This change not only promotes transparency but also removes an incentive for misreporting, creating a more equitable system for all.

Appreciating the Seamless Process:

The new process is a model of efficiency and convenience. For MSME's, their MSME

Udyam Registration Certificate is now recognized as the MCD factory license, while large units can use their

"By fulfilling this long-standing demand, the industryfriendly government of Delhi has indeed provided relief to entrepreneurs. Laghu Udyog Bharati expresses its gratitude to the Delhi government for this decision."

> Ghanshyam Ojha National President, LUB

allotment letter or lease-deed issued by GNCTD/ DSIIDC.

The integration with the property tax portal is the highlight of this reform. Instead of a separate application and inspection process, factory owners can now simply upload their relevant documents and pay the new fee at the time of paying their property tax. A single receipt with an endorsement of the deemed permission will serve as proof, effectively eliminating the need for a separate factory license. This initiative demonstrates a clear commitment to leveraging technology to create a simple, transparent, and timebound system for entrepreneurs, saving them valuable time and resources.

This order is a commendable step by the Delhi government and MCD, reflecting a proactive approach to governance that prioritizes the welfare of businesses and the overall economic growth of the city.









RAJASTHAN'S LARGEST B2B BUSINESS EXHIBITION

19-20-21 SEPTEMBER 2025

EXHIBITION GROUND, ARAVALI VIHAR R.H.B, BHIWADI, RAJASTHAN - 301019

ORGANISED BY



TITLE SPONSORS



DIGITAL PARTNER



SPONSORS



CHANNEL PARTNER



BANKING PARTNER



SPONSORS



PRINTING PARTNER





Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024–30

Salient Features:

The Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30 is a comprehensive framework aligned with the Government of India's Vision @ 2047 under Amrit Kaal. It is aimed at transforming the state into an littractive investment hub by leveraging its natural resources, human capital, and strategic location.

With a strong emphasis on inclusive growth, technological advancement, environmental protection, and ease of doing business, the policy seeks to stimulate economic development, create employment opportunities, and enhance Chhattisgarh's contribution to the national economy. The extensive range of incentives and specific packages for diverse sectors and social groups underscores a strategic approach to tailored industrial promotion and sustained growth.

Key Objectives

- Ensuring inclusive industrial development across districts, divisions, and development blocks, with long-term planning for equitable growth.
- Encourage investment in agro-based industries, minerals, pharmaceuticals, textiles, engineering, IT/ITES, defence products, forest produce, and modern technology sectors.
- Provide training, skill alignment, and stipends to prepare human resources for industrial needs, with strong linkages between industry and academia.
- Focus on new-age enterprises such as AI, robotics, biotechnology, GCC, IT, and IT-enabled services, creating jobs for educated youth.
- Establish industrial parks in high-potential areas, providing developed land, plots, industrial sheds, flat-factory complexes, and plug-and-play facilities.



Vishnu Deo Sai Hon'ble Chief Minister, Chhattisgarh

Strategic Provisions

 Development blocks are divided into three groups with higher differential incentives based on current industrialization levels.

State Map and CM pic with Name And 2-3 Pics of Infra

- Strengthen local industries to replace heavily imported goods while enabling exports global markets.
- Special packages for high growth sectors pharma and medical devices, textiles and garments, agro & food processing, electricals & electronics, Al/robotics/Computing, IT & ITES, Data Centres, GCCs, defence, aerospace, and space technology.
- Additional incentives for SC/ST entrepreneurs, women, ex-servicemen (including Agniveers and paramilitary), third gender, differently abled, NRIs, surrendered Naxalites, and Naxal- affected individuals.



 Establishing more incubation centres, foster entrepreneurship, and support startups with infrastructure and financial incentives.

Categorization under the Policy

- Based on investment size: Micro, Small, Medium and Large Industries
- Based on sector/product: thrust, general, services, and core sector industries

Major Incentives

 Fixed capital investment subsidy: 15% to 50%, depending on sector, development block and investment size

- Provision of employment booster: Enterprises employing 100-1000+ workers get additional capital investment subsidies, with limits increased by 1.1-1.5x.
- Interest subsidy: 40% to 55%, depending on sector, development block and investment size
- Exemption from electricity duty, stamp duty, land diversion charges
- Employment assistance in form of 20% wages for 5 years. Employment assistance for textiles / garment – Rs. 6000 per female and Rs. 5000 for male for 5 years
- Incentives for training, EPF, environment protection, transport, among others
- Anchor Unit Subsidy: First five anchor units in strategic sectors with investments over ₹200 crore receive an extra 5% subsidy on approved fixed capital investment.
- Bespoke Policy: Enterprises investing Rs. 1000 crores and above or providing employment generation of 1000 and above



निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान ने रचा नया इतिहास अपार संभावनाओं वाले प्रदेश में निवेशक राज्य की विकास यात्रा में बनें सहभागी

राजस्थान विशेष उद्योग टाइम्स डेस्क



मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि समृद्ध, सशक्त और सर्वोपिर राज्य बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर राज्य की विकास यात्रा में सहमागी बनें।

श्री शर्मा 28 अगस्त को जयपुर में राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान मिनरल पॉलिसी, रीको प्रत्यक्ष आवंटन नीति, डेटा सेंटर नीति, वस्त्र एवं परिधान नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जैसी नीतियां जारी की गई।

विजन डॉक्यूमेंट-2047 राजस्थान के सुनहरे भविष्य का खाका

श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देशभर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के कुल खनिज ब्लॉक आवंटन का 20 प्रतिशत अकेले राजस्थान से हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट-2047 को

उद्योग उत्थान विशेषांक

मंजूरी दी है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान के सुनहरे भविष्य का खाका है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 सौर परियोजनाओं को मंजूरी, नई भूमि आवंटन नीति, पंच गौरव जैसे नवाचारों एवं निर्णयों से ऊर्जा एवं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

जोधपुर-पाली औद्योगिक गलियारा विकास का एक नया अध्याय

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। जोधपुर—पाली औद्योगिक गलियारा, दिल्ली—मुंबई औद्योगिक गलियारे का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 19 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा वस्त्र, कृषि, इंजीनियरिंग और ऑटो क्लस्टर उद्योगों पर केंद्रित यह परियोजना राजस्थान को औद्योगिक मानचित्र पर नया स्थान दिलाएगी।

प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए अनेक कदम-

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति—2024 जारी की गई है, जो 2030 तक प्रदेश के अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 125 गीगावाट के स्तर तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तथा 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम अभियान' से प्रेरणा लेते हुए 'हरियालो राजस्थान' की शुरुआत की है। अभियान के तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है तथा अब तक हम 17 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुके हैं।

जिलों के विकास से बनेगा विकसित राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में असीमित अवसरों के साथ प्राकृतिक संसाधन एवं कुशल मानव संसाधन मौजूद है। राज्य सरकार ने पिछले डेढ साल में पानी, बिजली, बुनियादी दांचे और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। पेयजल और सिंचाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राम जल सेत् लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, माही बांध योजना सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। साथ ही, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, 1 हजार 300 गांवों को डामर सडकों से जोडना, मिसिंग लिंक रोड का निर्माण, जयपुर एयरपोर्ट का विस्तार सहित विभिन्न कार्यों से राज्य में विकास के नए मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ और राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर भी उपस्थित रहे।

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना स्वरोजगार से युवाओं की उद्यमशीलता को मिलेगी नई राह

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके सपनों को नई उड़ान



देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अपनी विभिन्न योजनाओं और फैसलों से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि युवा शक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर संसाधन और समर्थन उपलब्ध हों। अपनी इसी नीति के तहत राज्य सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। 23 अगस्त, 2025 को राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में इस योजना का अनुमोदन किया गया। योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहन करना तथा उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की नई राह खोलना है। इससे युवा आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य लोगों को रोजगार प्रदाता भी बनेगा।

2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकेंगे या पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार, विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण कर सकेंगे। योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इससे युवा उद्यमियों के स्वरोजगार की राह में आने वाली वित्तीय बाधाएं दूर होंगी और वे नवाचार, गुणवत्ता और अपने व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।

विशेष वर्गों को मिलेगा 1 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान

इस योजना को पूरी तरह समावेशी बनाते हुए राज्य सरकार ने इसमें विशेष प्रावधान किए हैं। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्ड धारक बुनकर एवं शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इससे समाज के सभी वर्गों तक आत्मनिर्भर बनने के समान अवसरों की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

युवा उद्यमियों की राह को और अधिक सुगम करते हुए इस योजना में वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा।

राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना महज ऋण और सब्सिडी देने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उस दूरदर्शी नीति का हिस्सा है, जो राजस्थान को आर्थिक समृद्धि की नई ऊंचाई तक लेकर जाएगी। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर युवा वर्ग को केन्द्र में रखकर नवीन नीतियां बना रही है। राजस्थान स्किल पॉलिसी, युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना और युवा नीति 2025 युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उनके लिए रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नियुक्तियां तथा निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य तय किया हैं। साथ ही, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन तथा रोजगारपरक योजनाओं एवं कार्यक्रमों से युवाओं को निरंतर सौगातें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जैसे नवाचार प्रदेश में स्वरोजगार क्रांति की मजबूत नीव बनेंगे।





(ह) ट्रंPDCL सस्ती नहीं मु<mark>फ्त बिजली</mark> की ओर क्रू



श्री विष्णु देव साय माननीम मुख्यमंत्री, घर्तीसगढ















पीएम सूर्य घर 🄉 मुफ़्त बिजली योजना

मासिक बिजली बिल से भी कम ई.एम.आई. में लगाएं रूफ टॉप सोलर प्लांट

सीलर प्रसार क्षमता	केंद्र सरकार की सर्वितेही	राज्य सरकार की समित्री	कुल सहावता राशि	आसात भारितक EME
1kW	₹30,000	₹15,000	₹45,000	₹167
2 kW	₹60,000	₹30,000	₹90,000	₹333
3 kW	₹78,000	₹30,000	₹1,08,000	₹800

•बैंक द्वारा ६% ब्याज दर पर आसान किश्तों में १० वर्षों के लिए ऋण सुविधा (ई.एम.आई.) उपलब्ध



हमारा संकल्प हाफ बिजली से मुफ्त बिजली



आवेदन प्रक्रिया व अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं

https://pmsurvaghar.gov.in/



Visit us: ♥♥♥○/ChhattisgarhCMO ♥♥♥○/DPRChhattisgarh ⊚www.dprcg.gov.in

CSIR-LUB Partnership: Driving Innovation & Growth for MSMEs



The collaboration between Laghu Udyog Bharati (LUB) and the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) has emerged as a powerful enabler of technological transformation for India's MSME sector. Through the flagship' '100 Days, 100 Technologies' program and sustained engagement under CSIR 365, this partnership has been instrumental in ensuring that laboratory innovations reach the grassroots of industry, empowering entrepreneurs to scale their businesses with science-driven solutions.

What began as an initiative to promote technology transfer from CSIR laboratories to industry has now blossomed into a movement that fosters innovation, enhances competitiveness, and creates pathways for an Atmanirbhar Bharat. By facilitating lab visits, training programs, live demonstrations, and awareness camps, CSIR and LUB have successfully built a bridge that connects India's robust R&D ecosystem with the real needs of small and medium enterprises.

Success Stories that Inspire: Innovation in Construction & Safety

LUB's members across India have adopted CSIR's

breakthroughs in sustainable and safe construction materials.

Smt. Purnima Chaudhry (Marble Plaza, Delhi) has implemented ecofriendly flooring, wall tiles, bricks, and paver blocks made from marble waste, thereby transforming industrial waste into wealth.

Sehgal and Sehgal Industries, based in Delhi, partnered with CSIR-CBRI to create Fire-Resistant, Water-Repellent Shelters for the Maha Kumbh, ensuring the safety of millions of pilgrims.



Similarly, Shri Neeraj Sehgal (Sehgal Doors, Delhi) integrated Bulletproof Movable Booths and Fire-Resistant Doors, strengthening national security and industrial safety standards. Notably, a bulletproof door developed with CSIR technology has been successfully installed

at the WHO building at Delhi by Sehgal Doors, underscoring the global trust placed in Indian innovation.



Shri Sundeep Goyal of Deep Cables, Delhi, has further advanced safety standards with Fire-Retardant, Low-Smoke, Less-Toxic Wires and Cables, again leveraging CSIR-CBRI expertise.

Health, Environment, and

Advanced Technologies

CSIR's impact extends far beyond construction, touching critical areas of public health, environmental sustainability, and advanced technology.

In Uttar Pradesh, Shri Hitesh Riyat of Rapid Cool deployed a standalone UV air Disinfection System (CSIR-CBRI), making workplaces and public spaces safer.



Smt. Aarti Sehgal of Dauerhaft, Delhi, is manufacturing Fire-Retardant Intumescent Coatings (CSIR-CBRI) that significantly improve building safety.

In Delhi, Shri
Onkar Tiwari of Biomimicry
Technologies has integrated IoTenabled & Cloud-Connected Air
Quality Monitoring Systems
(CSIR-CSIO) and piloted a water
service delivery monitoring suite in
collaboration with CSIR-CSIO,



NEERI, CEERI, CMERI, and CSMCRI. These ready-to-deploy innovations are directly contributing to national missions such as Jal Jeevan Mission, ensuring cleaner air, safer water, and smarter resource management.



Expanding this momentum, Shri Senthil Kumar of Global Lab and Consultancy Services LLP also adopted CSIR-CSIO's IoT-enabled air quality monitoring system, while Shri Kumar Ramaiah of Antares Engineering Solutions Pvt. Ltd.

introduced CSIR-CSIO's UV-C disinfection systems.

Similarly, Shri Rahul Baloriya of Rahul Infotech (Madhya Pradesh) has deployed CSIR-AMPRI's intelligent smoke, heat, and fire alarm sensors.





The health and wellness sector too has been energized by CSIR innovations. Dr. R. Lavanya of 108 Towels World India Pvt. Ltd. (Tamil Nadu) has commercialized CSIR-NBRI's Lotus-based Textile Technology, while D.A.K.

Thangamani of Lotus Agro Products has brought CSIR-NBRI's Lotus Tea to consumers.

In Telangana, Shri Anil Kumar B. of Aswini Homeo & Ayurvedic Products Pvt. Ltd. has introduced both a Herbal Nano Serum and Biofertilizers developed by CSIR-NBRI.

Meanwhile, Shri Nagendra Kumar of Nagpur Polyfilms Pvt. Ltd. rolled out CSIR-CEERI's field-deployable water testing kit, and Shri Shushma of Yellow Medi Plus Pvt. Ltd. (Delhi) advanced healthcare delivery through an IoT-enabled portable endoscope for minimally invasive surgery (CSIR-CEERI).

In Tamil Nadu, Shri Subramani Reddy G. of Hemagni Build-Pro Industries Pvt. Ltd. adopted CSIR-SERC's lightweight, foldable hospital modules, expanding access to emergency medical infrastructure.

On the sustainability front, Shri Prateek Bansal of Surya Comp-ounds & Masterbatches Pvt. Ltd. has successfully deployed CSIR-NPL's recycling technology, recovering valuable materials from multilayered plastic waste and strengthening India's circular economy.

Tangible Benefits for MSMEs

- Increased Productivity: The infusion of technology enabled enterprises to meet growing demand.
- New Product Development: Businesses diversified into innovative, science-based products.
- Market Expansion: Entrepreneurs entered new markets.
- Sustainability: Waste-to-wealth models and ecofriendly innovations enhanced green growth.

Conclusion

With dozens of MSME success stories already shining across India, the CSIR-LUB collaboration is proving to be a game-changer. By ensuring that laboratory-developed technologies reach industries across various sectors, including food, construction, safety, health, and the environment, this partnership empowers entrepreneurs, strengthens innovation, and lays the foundation for a self-reliant, developed India (Viksit Bharat).





Government-e-Marketplace (GeM) Virtual Class: A Game Changer for Growth Story of Entrepreneurs

Efficient • Transperent • relusive



Unique Initiative
Janak Bhatia
LUB's National Co-Treasurer &
Convener- GeM
Mail

The Government-e-Marketplace (GeM) is India's national public procurement portal with a mission to enhance transparency, efficiency and inclusivity in procurement. It is a fully digital, cashless and system-driven platform that offers an end-to-end solution for all government buyers and sellers. GeM is committed to transforming the way India procures goods and services by making procurement smart, inclusive and sustainable.

At GeM, inclusion is not just a policy, it's about people. It's about the small entrepreneur in a village who finally gets a chance to sell directly to the government, the woman-led startup that finds new markets for her innovation, or the artisan whose traditional craft now reaches buyers across India.

By opening doors for MSEs, startups, women entrepreneurs, SC/ST enterprises and artisans, GeM is making sure that public procurement reflects the true diversity of our country. Initiatives like Startup Runway and the SARAS Collection are more than platforms, they are bridges that connect talent, tradition and opportunity.

From simplified onboarding to transparent tendering, every step on GeM is designed to make it easier for those who were once left out to now step in with confidence. This is how GeM is helping inclusion come alive, not in theory, but in everyday success stories.



On Foundation Day of GeM, Shri Janak Bhatia National Joint Treasurer & GeM Coordinator greets Shri Mihir Kumar, CEO, GeM.

Today, GeM has emerged as India's largest public procurement platform, with an order value exceeding ₹15 lakh crore across nearly 3 crore orders. It connects over 1.6 lakh buyers with a community of 23 lakh+ sellers, offering unmatched choice across 11,000+ product categories and 340+ service categories. Significantly, nearly 45%* of the total order value comes from MSEs, underscoring GeM's role in strengthening grassroots businesses and turning inclusive growth into a reality.

Micro and Small Industries have a battery of activities to operate. May it be raw material, machinery, manpower, technology, compliances, or production. However, the most important in all this is supply or revenue generation. Normally MSMEs are a part of supply chain however in case the MSME direct suppliers in the public procurement or private market, it not only increases their margins and capacity to develop and invest in new products but also make them stronger and more independent which is required for Atmanirbhar Bharat. Ancient Indian Economy flourished on this concept since small and local manufacturing was the backbone of the industry.

Among this public procurement is one of the very important aspects to strengthen the Small Industry if they can adapt it. With direct supply, they can also

उद्योग उत्थान विशेषांक

reduce intermediators. As India goes digital in technology, the Government has also advanced their system by starting an Government-e-Market platform. All government departments are posting their requirements on GeM portal.

Laghu Udyog Bharati understood the importance of public procurement for small industries and signed an MOU in their National Executive meeting in 2024 with GeM to help MSMEs by Onboarding them. LUB is creating awareness and providing support for registration for uploading their catalogues, elevating them with trademark, bid preparation and participation.



After the signing the MOU, it was understood that the purpose of the MOU can be achieved through a regular interaction with stakeholders and GeM officials. Hence, Laghu Udyog Bharati started weekly interaction with members and has conducted more than 50 physicals cum virtual interaction from head office. The GeM CEO was also very serious for such important interactions and sometimes he personally came at head office with entrepreneurs.

It was understood that regular meetings are required for the industry to make them aware and provide them solutions to their problems in onboarding and it is not possible physically everyone to attend always. Considering this an online weekly series was planned on Webex platform in association with GeM.

This GeM Class proved to be a very useful and productive arrangement with lots of entrepreneurs getting involved and onboarding themselves. Furthermore, these sessions were planned in local languages like Tamil, Malayalam, Kannada etc. Thus, engagement of more entrepreneurs was ensured and continuity with fixed day and time became a word of mouth.

The Laghu Udyog Bharati also worked with GeM in their exhibition by providing a platform and training sessions during this period. More than 20000 entrepreneurs have associated themselves with the GeM through 60 events and webinars.

Along with the sessions, feedback was also taken to verify the impact of the events. Many success stories were received. Many entrepreneurs who were reluctant to register and were not sure about the GeM portal benefits were enthused to get onboarding and receive supply orders. They got benefitted with their industry getting a new wave of growth. Their margins improved and they started working on new products. They saw a new horizon with a large no of items they can produce and supply on GeM under public procurement.

Weekly Wednesday Webinar is very Appreciable



Arun Kumar Soni Sara Udyog, Kolkata, WB

Laghu Udyog Bharati's initiative for growth of MSME sectors by hand holding and helping the service providers to sell their products to Government entities

through Government e-marketplace Portal has resulted in increase in sale and prompt payment realisation and consequent financial strengthening. We thank to the entire LUB's team for their support.

We Learn Skills and a lot of Things in GeM Webinars



Ram Chandra Kumar Libra Scale Industries Tupudana, Ranchi - Jharkhand We Manufacture 1Kg to 100 Tons Electronic Weighing Machine and Systems. Our company is registered with GeM Portal. Earlier, I joined LUB's weekly

interaction of GeM webinar and I observed that various technical issues are resolved very quickly during session. We are a also Proud Member Of Laghu Udyog Bharti.



06-08 NOVEMBER 2025 @ BIEC, Bangalore





New Heights
K Narayana Prasanna
President
Laghu Udyog Bharati, Karnataka
president@lubkarnataka.org

What began as a modest concept proposed by a collective of industry leaders in Karnataka has now evolved into a colossal organization dedicated to advancing the development of MSMEs across the nation. The India Manufacturing Show was initiated in 2009 by the Laghu Udyog Bharati-Karnataka State Unit, aiming to promote and highlight the manufacturing strengths and capabilities of Indian industries to both global and local markets.

The IMS primarily highlights the most recent trends, innovations, and advancements occurring within the manufacturing sector, particularly in the realm of new product development both in India and globally. Additionally, the Show facilitates the Vendor Development Program, sourcing opportunities, and avenues for direct B2B interactions.

IMS serves as an exemplary platform for businesses across all sectors of the manufacturing industry. Throughout the years, IMS has consistently contributed to the growth of the Indian market and has played a crucial role in providing viable opportunities for companies entering the region. The IMS platform also organizes Technical Seminars aimed at motivating and inspiring emerging entrepreneurs and aspiring students, guiding them towards becoming 'Entrepreneurs' who will contribute to the nation soon.

As the largest and most influential manufacturing

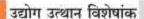
exhibition, IMS continues to support the industry at all levels-achieving business outcomes, facilitating knowledge exchange, and acknowledging excellence. Six editions of the India Manufacturing Show, an international exhibition, have been successfully conducted in the years 2010, 2012, 2014, 2017, 2022, and 2023.

The 7th edition is set to take place from November 6-8, 2025, at BIEC, Bengaluru. This international event aims to provide both manufacturing and marketing support to various industries. Currently, the IMS has established itself as the leading trade fair for engineering companies in the country. IMS offers participating companies a distinctive platform to showcase products and services to key manufacturers within the ecosystem.

IMS presents an ideal opportunity for exhibitors to display their latest technologies, machinery, equipment, research and development, communications, and logistics in sectors such as Aerospace & Défense Engineering, Automation & Robotics, Energy & Environment, Electronics and Electricals, and General Engineering. Notable participants will include representatives from India and overseas-multinational corporations, foreign original equipment manufacturers, central government organizations, state governments and their departments, as well as corporates and MSMEs.

As part of the Exhibition, the IMS also hosts comprehensive Conference targeting B2B interactions and vendor development to enhance MSMEs as competitive producers and suppliers of components for large industries of local and international markets.











श्री विष्णु देव साय माननीय मुख्यमंत्री, धरीधनक

- 13 लाख किसानों को ₹3,716 करोड़ बकाया बोनस राशि वितरित
 - देश में सर्वाधिक **₹3,100** प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी



सुशासन से समृद्धि की ओर

gg : # ChloringarkCMO - ChloringerbCMO - ChloringerbCMO - ChloringerbCMO - DPPChloringerb -

minimization of the second of

1st



The 1" Edition of IMS-2010 marked a significant milestone in India's industrial journey. The show was jointly organized by Laghu Udyog Bharati, Karnataka and K&D Communications Ltd., with the active support of the Government of Karnataka and the Ministry of MSME, Government of India.

This inaugural edition laid the foundation for what would go on to become India's flagship platform for manufacturing and engineering excellence, particularly focused on empowering the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Objective & Purpose of IMS-2010:

- Promote India's manufacturing and engineering capabilities across a global audience
- Support MSME growth through collaboration with large enterprises, PSUs, and global partners
- Provide a level playing field for Indian manufacturers to showcase innovation, capabilities, and competitiveness
- Create a single largest collaborative platform bringing together stakeholders from public and private sectors

Participation Highlights:

- · Total Exhibitors: Over 500, including:
 - MSMEs
 - Large Corporates
 - Public Sector Undertakings (PSUs)
 - International Manufacturers & Engineering Firms
- Audience Profile:
 - · Entrepreneurs
 - Technocrats
 - Policymakers
 - · Government Officials
 - · Corporate Leaders & Intrapreneurs



The overwhelming participation across sectors reflected the growing confidence in India's industrial potential and the appetite for collaboration, innovation, and expansion.

Key Outcomes:

- First-of-its-kind exposure for MSMEs to directly interact with large enterprises, policymakers, and global visitors
- Business development opportunities through direct engagement, partnerships, and lead generation
- Strengthened positioning of India as a global manufacturing and engineering hub
- Encouraged knowledge-sharing and technology adoption, especially among smaller enterprises

Conclusion

The success of IMS 2010 established a strong foundation for future editions of the India Manufacturing Show. By offering unmatched access to markets, technologies, and networks, the event delivered on its promise to be India's premier manufacturing and engineering summit, with a strong focus on inclusive industrial development.

As the inaugural edition, IMS-2010 set the tone for what would become a growing legacy of innovation, collaboration, and growth in India's industrial landscape.

2nd

12012

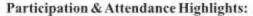
INDIA MANUFACTURING SHOW

September 27-30, 2012 @ BIEC, Bangalore

The 2nd Edition of IMS-2012 was successfully organised by the IMS Foundation, under the aegis of Laghu Udyog Bharati, and in association with Reliance Broadcast Network. IMS-2012 reaffirmed its position as India's largest and most impactful manufacturing event.

The four-day event continued to provide a unified business platform for stakeholders from all sectors of the manufacturing industry, facilitating business growth,

innovation sharing, and international collaboration.



- Total Visitors: Over 7,500 industry professionals
- International Participation: Increased footfall from Germany and other parts of Europe
- Exhibitor Feedback: Reported a notable increase in business visitors compared to the first edition
- Duration: 4 days of continuous exhibition, networking, and knowledge exchange

Exhibition Highlights:

IMS-2012 brought together manufacturers, suppliers, and technology providers under one roof, creating a diverse and dynamic business environment. The show successfully:

- Offered real-time business opportunities for companies entering or expanding in the Indian market
- Enabled cross-sector networking, promoting collaboration and visibility among SMEs, large enterprises, and global participants
- Provided exhibitors with tangible returns through lead generation and brand exposure

Conferences & Knowledge Sessions:



In addition to the exhibition, IMS-2012 hosted a series of **industry conferences**, featuring thought leaders and experts across various manufacturing sectors. These sessions facilitated:

- Policy Dialogue
- · Industry Trend Analysis
- Technology Adoption Discussions
- SME Support Strategies

The conferences served as a knowledge-sharing platform, aligning industry practices with global standards and encouraging innovation-driven growth.

Conclusion:

The IMS-2012 successfully built on the momentum of its inaugural event. It attracted a broader international audience, increased industry participation, and strengthened its reputation as **India's go-to platform** for manufacturing innovation, business development, and strategic partnerships. The IMS Foundation remains committed to expanding the show's scope and global reach in future editions, making it an essential part of India's industrial transformation journey.





The 3rd edition of the IMS-2014 was successfully organized with the aim of providing a robust platform for showcasing manufacturing excellence and innovation in India and abroad.

The show was inaugurated with great enthusiasm by Shri Ananth Kumar, Union Minister, in the presence of several foreign dignitaries and esteemed guests. The inaugural session set a vibrant tone for the three-day international exhibition, emphasizing the government's support for India's manufacturing sector.

Exhibition Highlights:

Total Exhibitors: 108

Products & Services Displayed: Over 700

Estimated Business Delegates: 6,180

Business Leads Generated: Over ₹200 Cr.

Focus: Latest technological innovations across multiple industrial sectors

The exhibition floor buzzed with dynamic networking, live demonstrations, and business interactions. Participants ranged from SMEs to large corporations, all showcasing advancements in technology, products, and services that drive the manufacturing ecosystem.

Key Outcomes:

- The show served as a significant platform for business matchmaking, knowledge exchange, and technology transfer.
- Multiple strategic alliances and partnerships were initiated during the event.
- The large volume of business leads-estimated at over ₹200 crores-highlights the event's commercial success and the strength of India's industrial potential.





Conclusion:

The 3rd edition of IMS-2014 reinforced its reputation as India's premier manufacturing show. The scale of participation and the quality of exhibits underscored the country's growing stature in the global manufacturing landscape. Building on this momentum, the IMS Foundation aims to further expand the reach and impact of future editions, encouraging more international participation and deeper engagement with emerging technologies.



4th

MS2017

INDIA MANUFACTURING SHOW

Oct. 30 - Nov.1, 2017 @ BIEC, Bangalore

The 4" edition of IMS-2017 was organized by the IMS Foundation, under the aegis of Laghu Udyog Bharati, and in association with Tafcon Projects (Pvt) Ltd.

IMS-2017 continued its mission to create a unified platform that brings together the best of Indian manufacturing capabilities alongside global innovations, with a strong focus on emerging industrial sectors.

The three-day event featured a comprehensive International B2B Exhibition held concurrently with sector-specific international conferences.

These conferences addressed critical domains

- including:
 Energy & Environment
- · Aerospace & Defence
- Industry 4.0
- · Automotive Industry

Participation Statistics:

- Total Exhibitors: 203
- Including MSEs, PSUs, Government Pavilions, and International Participants
- Visitors: Approximately 5,000 Business Visitors and 450 Delegates for the Conference
- Exhibitor Profile: Ranged from Micro and Small Enterprises to Public Sector Units and international companies

The exhibition floor provided a rich ecosystem for business networking, collaboration, and showcasing of technological advancements and solutions relevant to both domestic and international markets.

The 4" edition of IMS-2017 reinforced its status as a premier event in India's manufacturing landscape. With a significant increase in sectoral coverage, participation diversity, and knowledge-driven conferences, the event successfully bridged gaps



between industry, government, and academia. The IMS Foundation is committed to building on this success by expanding future editions with wider global collaboration and deeper sectoral integration, aligning with India's goals of industrial growth and innovation leadership.

Shri Ananthkumar, Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs and Chemicals & Fertilizers, Govt. of India inaugurated the 4th Edition on IMS 2027. Other eminent dignitaries present on the occasion included, Shri P. Ramadas, Managing Director, ACE Manufacturing Systems Ltd., Mr. Robert Grobbauer, Managing Director, AT & S India, Shri Farooque Shahab, Chief General Manager, State Bank of India along with Shri H.V.S. Krishna, Chairman, IMS Foundation, Shri P.S. Srikantta Dutta, President, Laghu Udyog Bharati – Karnataka and Shri I.P. Wadhwa, Managing Worker, TAFCON Group.

The event was a unique platform for Entrepreneurs, Decision Makers. Senior Government Officials, Investors, Industry Members, Traders, Equipment Buyers & Suppliers, Academia, Engineers and Trade Delegations to congregate, brainstorm, showcase and forge meaningful partnership for business.





INDIA MANUFACTURING SHOW

September 15-17, 2022 @ BIEC, Bengaluru

The 5^a edition of the IMS-2022 was focused on India's industrial and technological growth, particularly in the MSME sector. The event was inaugurated in the esteemed presence of Union Minister for Parliamentary Affairs Shri Prahlad Joshi, Chief Minister Govt. of Karnataka Shri Basavaraj Bommai and Minister for Large & Medium Industries, Govt. of Karnataka Dr. Murugesh Nirani.

Several senior officials from Central and State Government departments, along with industry leaders, domain experts, and dignitaries, also attended the ceremony, reflecting the high-level commitment to strengthening India's manufacturing ecosystem.

Key Focus Sectors:

The core emphasis of IMS-2022 was to showcase and support advancements in:

- · Aerospace & Defence Engineering
- Automation & Robotics
- Energy & Environment
- · Electronics & Electricals
- General Engineering

These sectors were chosen for their alignment with national priorities such as *Atmanirbhar Bharat* and the modernization of India's industrial base.

Exhibition Highlights:

- Total Exhibitors: Over 300 companies from across India, including both large corporates and MSMEs
- Business Visitors: 11,947 over three days
- · International Visitors: 40+
- Exhibitor Representatives On-Site: 1,699
 - Special Attendees: VIPs: 187
- Total Footfall (Registered): 15,269

The event saw unprecedented participation and interest from multiple stakeholders across industry, academia, government, and international business communities.



Special Feature: Vendor Development for MSMEs

One of the most impactful highlights of IMS -2022 was the exclusive Vendor Development Session focused on creating business opportunities for MSMEs. Major DPSUs and corporate leaders unveiled:

- Reserved procurement lists for MSME participation
- Opportunities for co-creation, collaboration, joint ventures, and subsidiary development

This session facilitated direct engagement between MSMEs and organizations like DRDO Labs, HAL, BEL, BHEL, and BEML, making the event a critical hub for technology access and supply chain integration.

Knowledge Exchange: High-Level Conferences

The event hosted 10 high-level conferences, addressing key industry themes and enabling:

- Policy Discussion and Roadmap Setting
- · Technology Transfer and R&D Insights
- · MSME-Centric Capacity Building
- Domain-specific Vendor Engagement

These conferences positioned IMS-2022 as more than just an exhibition - a knowledge platform for India's next phase of industrial development.

Conclusion:

The 5th IMS-2022 set new benchmarks in terms of scale, participation, and sectoral impact. Its strategic focus on MSMEs in Aerospace & Defence, supported by Government and Industry, provided meaningful outcomes in business development, vendor collaboration, and technological innovation.

The IMS Foundation and Laghu Udyog Bharati-Karnataka reaffirm their commitment to making future editions even more inclusive, globally relevant, and aligned with India's vision of self-reliance and industrial leadership.



6th



INDIA MANUFACTURING SHOW

November 2-4, 2023 @ BIEC, Bengaluru

This 6^a edition of IMS-2023 delivered a high-impact platform for innovation, industry networking, business growth, and strategic partnerships. Backed with full support from the Ministry of Defence, Gov. of India, IMS 2023 emerged as a flagship event, bringing together key stakeholders from India's aerospace, defence, and general engineering ecosystems.

Participation & Attendance Highlights:

- Total Exhibitors: Close to 300
- Defence Public Sector Units (DPSUs) & Corporates Represented: 273
- Business Visitors: 14,371
- Exhibitor Marketing Representatives: 2,974
- VIP Visitors: 107
- Total Footfall: Well over 14,000+
- Business Leads Generated: ₹200 Crores+

Key Focus Sectors:

IMS-2023 showcased cutting-edge advancements across five verticals, highlighting India's potential in high-growth areas:

- Aerospace and Defence
- 2. Automation, Robotics, and Drones
- 3. Electricals and Electronics
- 4. General Engineering
- 5. Energy, Environment & EV Transportation

This strategic focus enabled a convergence of innovation, investment, and industry development opportunities across multiple domains critical to India's self-reliant growth agenda (Atmanirbhar Bharat).

Impact & Outcomes:

IMS-2023 proved to be a powerful platform for technology transfer, joint ventures, codevelopment, and MSME collaboration, making it the largest and most diverse MSME-focused expo for aerospace and defence in South India.



Opportunities for MSMEs:

Exhibitors gained direct access to key buyers including OEMs, DPSUs, Armed Forces, and global aerospace leaders, enabling MSMEs to showcase capabilities, pitch innovations, and pursue procurement and partnership opportunities.

Government & Institutional Support:

The show was supported by India's leading DPSUs including: DRDO, ISRO, HAL, ADA, BEL, BHEL, BEML, Ordinance Factories, and more. Their presence reaffirmed the commitment to strengthening the role of Indian industry, especially MSMEs, in strategic manufacturing.

· Global Participation:

Several top international aerospace and defence companies participated, unveiling their latest technological innovations and fostering global collaboration.

· Business Engagement:

A strong focus on B2B networking led to the generation of over ₹200 Crores in business leads, establishing IMS-2023 as a high-return investment platform for exhibitors.

Conclusion:

The 6th IMS-2023 marked a major milestone in the evolution of India's manufacturing landscape particularly in aerospace, defence, and general engineering. With increased scale, enhanced sectoral focus, and record-breaking participation, IMS 2023 set a new benchmark for industry exhibitions in India.

The event's success has paved the way for even more ambitious editions in the future. The LUB's Karnataka Unit remain committed to fostering industrial growth by building stronger industry-government-academia partnerships, empowering MSMEs, and promoting innovation-led manufacturing excellence.



नयी उड़ान पल्लवी लड्डा अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती महिला इकाई, भीलवाड़ा

प्रेरणा और प्रारंभिक विचार-

सनातन चेतना के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद को उनके गुरुवर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक संदेश दिया और कहा कि "हे नरेंद्र! तुम प्रयोगवादी इंसान बनना।"इसी से प्रेरणा लेकर इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2014 का बीजारोपण हुआ। इस मेले का प्रथम विचार मार्च 2014 में लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रान्त की प्रांतीय बैठक में संगठन के मार्गदर्शक श्री साँकल चंद्र बागरेचा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर प्रांत प्रचारक श्री मुरलीधर जी की विशेष उपस्थिति में किया गया। इसके बाद अप्रैल 2014 में पूना (महाराष्ट्र) में आयोजित लघ् उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसे राष्ट्रीय स्तर पर दिशा मिली। एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन और छिपी उद्यमी प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से इस फेयर के आयोजन का निर्णय लिया गया। और आखिरकार 20 से 23 सितम्बर, 2014 को जोधपुर में इस ऐतिहासिक आयोजन की श्रृंखला का शंखनाद कर दिया गया। इस कार्यक्रम में ही फेयर-2015 की भी घोषणा कर दी गई, जिसका आयोजन पुनः जोधपुर में किया गया।

संगठन एवं प्रबंधन-

फेयर का आयोजन लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा की अध्यक्षता में हुआ। जोधपुर प्रान्त अध्यक्ष श्री राजेंद्र राठी के संयोजन में विभिन्न समितियां गठित की गईं। भूमि एवं वास्तु पूजन का शुभारम्भ 16 सितम्बर, 2014 को किया गया।

उद्योग दर्शन @ जोधपुर



उद्घाटन सत्र-

20 सितम्बर, 2014 को फेयर के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्री संतोष गंगवार, वस्त्र मंत्री, भारत सरकार रहे। अध्यक्षता श्री गुलाबचंद कटारिया, मंत्री, राजस्थान सरकार ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जोधपुर सांसद श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित रहे। इस सत्र में MSME सेक्टर के महत्व और उसके भविष्य को लेकर सार्थक संदेश दिया गया।

संगोष्ठियाँ और सेमिनार-

फेयर के दौरान कई महत्वपूर्ण संगोष्ठियाँ आयोजित की गई,जिनमें विशेषज्ञों ने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए।

प्रथम संगोष्ठी (21 सितम्बर, 2014) का विषय था "पश्चिमी राजस्थान के खनिज संसाधन – अवसर और चुनौतियाँ।" इसमें मुख्य अतिथि सांसद श्री अर्जुनराम मेधवाल रहे।



उद्योग उत्थान विशेषांक

वक्ताओं में श्री डी.एन. पांडे, डॉ. डी.के. सक्सेना, श्री सी.डी। नारायण स्वामी, श्री पी. संथिल कुमार, श्री राकेश गोरवामी और डॉ. पी.सी. पुरोहित ने खनिज संसाधनों की संभावनाओं पर चर्चा की।

द्वितीय संगोध्वी (21 सितम्बर, 2014) में MSME Conclave का विषय"Financing the MSME, Transforming India" पर आधारित था। इसमें श्री नागेन्द्र पारख,डॉ. डी. आर. अग्रवाल, श्री वी. वैद्यनाथन, श्री अजय ठाकुर, श्री राकेश मेहता और प्रोफेसर गौरव वल्लभ जैसे विशेषज्ञों ने MSME फाइनेंसिंग पर गहन विचार रखे।

तृतीय संगोष्ठी (22 सितम्बर, 2014) "Direct Taxes" विषय पर हुई। इसका आयोजन टैक्स बार एसोसिएशन जोधपुर के साथ संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य अतिथि सीए श्री



कैलाश भंसाली विधायक, जोधपुर रहे। सत्र की अध्यक्षता सीए श्री बी.एम. कोठारी ने की तथा सीए श्री कपिल गोयल (दिल्ली) और सीए श्री सुरेन्द्र चोपड़ा वक्ता रहे।

थीम और राष्ट्रीय मार्गदर्शन-

फेयर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की "Make in India-Made in India" थीम को सार्थक करने के लिए "आओ उद्यमी बनो" का नया नारा दिया गया। आयोजन के दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी के सतत मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एच.वी.एस. कृष्णा और राष्ट्रीय महासचिव श्री ओ.पी. मित्तल ने प्रबंधन सुनिश्चित किया।

विशेष आकर्षण और सुविधाएँ-

राजस्थान में पहली बार वातानुकूलित स्टॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई। कुल 17 राज्यों के उद्यमियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। इस प्रकार यह फेयर एक Multi-State एवं Multi-Product Beneficial Event सिद्ध हुआ।

प्रचार-प्रसार और सहभागिता-

फेयर का प्रचार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया। इसकी वेबसाइट को 11,500 लोगों ने देखा। फेयर में कुल 270 प्रदर्शक (Exhibitors) शामिल हुए तथा करीब 30,000 उद्यमियों ने भाग लिया। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए कुछ स्टॉल नि:शुल्क और कुछ रियायती दरों पर भी उपलब्ध कराए गए।

प्रदर्शनी की प्रमुख झलकियाँ-

फेयर में इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प, हैंडमेड उत्पाद, कारपेट, पेंट्स, स्टेनलेस स्टील बर्तन, पत्थर उद्योग, सोलर, ऑटोमोबाइल्स, दरी, पॉटरी तथा अन्य विविध उत्पादों की शृंखला प्रदर्शित की गईं। इन उत्पादों की मशीनरी के लाइव प्रदर्शन में लोगों का विशेष आकर्षण रहा। फेयर का मुख्य फोकस Import Substitute (आयात— स्थानापन्न) पर रखा गया।



समापन-सत्र-

23 सितम्बर, 2014 को समापन सत्र की मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं वित्त राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण रहीं। विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद श्री नारायण पंचारिया तथा श्री दुर्गादास जी (क्षेत्रीय प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) उपस्थित रहे। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर की बाधाओं और संभावनाओं पर सुझाव सुने और नई घोषणाओं का आश्वासन दिया। इंडिया इण्डस्ट्रियल फेयर—2014 जोधपुर राजस्थान में एमएसएमई सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने न केवल उद्यमियों को एक साझा मंच दिया, बल्कि "मेक इन इंडिया" थीम को वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया।





लघु उद्योग भारती ने इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर (आईआईएफ) के दूसरे संस्करण का आयोजन 2 से 5 अक्टूबर, 2015 तक जोधपुर में किया। मेले ने उद्योग, व्यापार और नवाचार की दिशा में नई संभावनाओं के द्वार खोले और हजारों उद्यमियों को एक साथ ज्ञान, उत्पाद और तकनीक से रू–ब–रू कराया।

- मेले की प्रमुख विशेषताएँ-

- आयोजन स्थल पर 8 वातानुकूलित डोम लगाए गए, जिनमें 350 स्टॉल स्थापित किए गए।
- विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश से उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- मेले में लगभग 35,000 लोगों की भागीदारी रही, जो



आयोजन की सफलता का प्रमाण है।

- उद्घाटन समारोह-

 समारोह की अध्यक्षता श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत सरकार ने की।

उद्योग दर्शन @ जोधपुर

- मुख्य अतिथि श्री गुलाबचंद कटारिया, गृहमंत्री, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ट अतिथि श्री अरुण चतुर्वेदी, समाज कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार।
- अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधिः श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सांसद, जोधपुर, श्री नारायण पंचारिया राज्यसभा सदस्य, श्री बाबूसिंह राठौड़ व श्री जोगाराम पटेल (विधायक) तथा महापौर श्री घनश्याम ओझा।

- संगोष्ठियों का विस्तृत कार्यक्रम-

- 3 अक्टूबर, 2015
- विषय- ई-कॉमर्स के बढ़ते महत्व और MSME क्षेत्र के लिए अवसर

मुख्य अतिथि— श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सांसद— जोधपुर, वक्ता श्री नवीन गौड़ एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफिसर ईपीसीएच, श्री हुसैन कसुरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष—पेपरफ़ाई, श्री विशाल ग्रोवर (महाप्रबंधक मार्केटिंग— ट्रेड इंडिया।

2. विषय-सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा की उपयोगिता

मुख्य अतिथि— श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, वक्ता श्री बी.के. डोसी प्रबंध निदेशक— राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लि., श्री ए.के. जैन प्रबंध निदेशक— राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लि., श्री सुमन कुमार निदेशक — सनएडिसन इंडिया लि. यूएसए, श्री योगेश बिड़ला निदेशक — बिडला सोलर प्रोजेक्ट कम्पनी।

4 अक्टूबर, 2015

1. विषय-MSME सेक्टर के लिए आसान क्रेडिट फ्लो

मुख्य अतिथि— श्री अर्जुनराम मेघवाल—सांसद बीकानेर, वक्ता श्री मनोज श्रीवास्तव सहायक महाप्रबंधक— सिडबी, श्री एम.एम। शर्मा क्षेत्रीय प्रबंधक— बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री राजीव अरोड़ा सहायक महाप्रबंधक—स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री हितेश शाह क्लस्टर मैनेजर—डीसीबी बैंक, श्री अनिल चौधरी राजस्थान वित

उद्योग उत्थान विशेषांक

निगम जोधपुर, विशेष उपस्थिति— श्री जे.जी। हिंगराजिया प्रबंध निदेशक, इंडेक्स टीबी, गुजरात सरकार।

- विषय- आगामी GST कानून, आयकर एवं अन्य कर सुधार मुख्य अतिथि— श्री अर्जुनराम मेघवाल, सांसद, बीकानेर, वक्ता— श्री कपिल गोयल (सी.ए.), श्री बिमल जैन (सी.ए)
- 5 अक्टूबर, 2015
- विषय- युवाओं के लिए कौशल विकास की आवश्यकता और अवसर



अध्यक्षता— डॉ. यशवंत बी. प्रीतम जिला कलेक्टर जोधपुर, मुख्य अतिथि श्री गौरव गोयल प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल विकास निगम—IAS, प्रमुख वक्ता— श्री राहुल मोहनोत सीईओ, बिरला व्हाइट सीमेंट, श्रीमती अंजु बजाज सदस्य, लघु उद्योग भारती, नई दिल्ली।

2. समापन समारोह-

मुख्य अतिथि–श्री कलराज मिश्र, केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री अध्यक्षता–श्री गजेन्द्र सिंह खीवसर

विशेष उपस्थिति डॉ. बी.आर. छीपा कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, श्री घनश्याम ओझा महापौर, जोधपुर, विधायक– श्री सूर्यकान्ता व्यास, श्री जोगाराम



पटेल, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वजुभाई वधासिया, श्री राजेंद्र राठी, श्री ओमप्रकाश मित्तल आदि उपस्थित रहे। समारोह से पूर्व श्री कलराज मिश्र ने मेले का अवलोकन कर उत्पादों की सराहना की।

- मेले का महत्व-

 छोटे एवं मझोले उद्योगों (MSME) को बड़े मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला।



- विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने आपसी अनुभव साझा किए।
- ई-कॉमर्स, सौर ऊर्जा, जीएसटी और स्किल डेवलपमेंट जैसे समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।
- आयोजन ने जोधपुर को व्यापार और उद्योग जगत में एक नए केंद्र के रूप में स्थापित किया।

निष्कर्ष-

इण्डिया इंडस्ट्रीयल फेयर-2015 ने यह साबित कर दिया कि यदि उद्योग, सरकार और औद्योगिक संगठन साथ आएं, तो आर्थिक विकास और नवाचार के नए आयाम खोले जा सकते हैं। यह आयोजन न केवल व्यापार और तकनीक का संगम बना, बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखा गया। इस तरह के मेलों से स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है और उद्योग जगत के लिए नए अवसर पैदा होते हैं।





उद्योग दर्शन @ जयपुर



लघु उद्योग भारती की ओर से इंडिया इंडिस्ट्रियल फेयर-उद्योग दर्शन के तीसरे संस्करण का आयोजन 16 से 19 सितंबर, 2016 तक गुलाबी नगरी जयपुर में किया गया। राज्य की इस सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदर्शनी में 22 राज्यों से 466 स्टॉल्स के साथ लघु उद्योगों के उत्कृष्ट उत्पाद प्रदर्शित किये गए। आईआईएफ के इस संस्करण की शानदार सफलता को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश के रूप में देखा गया।

जयपुर के जेईसीसी परिसर, सीतापुरा में आयोजित ये आयोजन लघु उद्योगों के राष्ट्रीय कुंभ का दिग्दर्शन था। इस मेले का आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया एवं स्किल डवलपमेन्ट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल रही।

इस फेयर में पहली बार केन्द्र के रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के साथ लघु उद्योग से जुड़ी इकाइयों को न केवल संवाद के स्तर पर जोड़ा गया, बल्कि उनके लिए उत्पादन के स्तर पर नई संभावनाओं को भी तलाश किया गया। इसके साथ ही फेयर में टेक्सटाइल, हैण्डीक्राफ्ट, सौर ऊर्जा, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और आईटी क्षेत्र की भी सहभागिता रही। फेयर में एमएसएमई कॉन्क्लेव, स्टार्टअप अवॉर्ड और महत्वपूर्ण तकनीकी सत्रों के आयोजन ने इसे खास बना दिया।

16 सितम्बर को इसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, राजस्थान के उद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर और रेलवे निदेशक श्री मधुराजन कुमार ने किया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मित्तल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री मोहनलाल शर्मा, सांसद श्री रामचरण बोहरा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोक परनामी सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।



भागीदारी और स्टॉल्स-

प्रदर्शनी में 22 राज्यों से 466 स्टॉल्स लगाए गए। इनमें टेक्सटाइल्स, हैंडीक्रापट, सौर ऊर्जा, ऑटोमोबाइल्स, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, फर्नीचर, मशीनरी और आईटी सेक्टर की विशेष भागीदारी रही। BSNL, NSIC, MSME, DRDO और पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी प्रमुख कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। कोटा डोरिया, पंजाब की फुलकारी, मृगनयनी, दक्षिण भारत का सिल्क, कोयंबटूर की ई-रिक्शा और अन्य कई आकर्षक उत्पादों ने आगंतुकों का ध्यान खींचा।

MSME कॉन्क्लेव और स्टार्टअप अवॉर्ड-

17 सितम्बर को MSME कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र और राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार ने 'MSME दिवस' की घोषणा की और विभिन्न उद्योग पुरस्कारों की शुरुआत की। इसी फेयर में पहली बार स्टार्टअप इंस्पायर अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें 100 छात्रों में से चयनित विजेताओं को 1 लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये की नकद राशि प्रदान की गई।

तकनीकी सत्र-

फेयर के दौरान कई तकनीकी—सत्र आयोजित किए गए। स्किल डवलपमेंट सत्र में NSDC के श्री राजीव माथुर ने नई गाइडलाइन्स पर प्रकाश डाला। MSME Opportunities पर DRDO सत्र में रक्षा उत्पादन से जुड़ी संभावनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भाग लिया। पावर एंड एनवायरमेंट सत्र में केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी श्री वीरेंद्र सिंह और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री पुष्पेंद्र सिंह ने उद्योगों के लिए ऊर्जा व पर्यावरण नीति पर विचार रखे। अंतिम दिन GST सत्र में श्री भूपेंद्र यादव और अन्य विशेषज्ञों ने GST की भूमिका और पारदर्शिता पर चर्चा की।

समापन समारोह-

19 सितम्बर को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुद्रा बैंक योजना और राजस्थान में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही जयपुर में 82 करोड़ की लागत से सिंगल सुपर फॉस्फेट संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी की। केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लघु उद्योगों को भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन बताते हुए इनके प्रोत्साहन पर जोर दिया। इस अवसर पर कई सांसद, विधायक और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे तथा सर्वश्रेष्ठ स्टॉल्स को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2016 केवल एक प्रदर्शनी नहीं रही, बल्कि यह MSME, स्टार्टअप, स्किल डवलपमेंट, रक्षा सहयोग और GST जैसी नीतियों को जोड़ने वाली एक सशक्त मंच भी सिद्ध हुई। इसने लघु उद्योगों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई और भविष्य में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया।







लघु उद्योग भारती ने चौथे इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र संभाग में राजकोट के NSIC मैदान में 26 से 29 अप्रैल, 2017 तक किया। यह आयोजन लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के औद्योगिक विकास, नए व्यापारिक अवसरों तथा उद्यमिता संवर्धन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था।

- आयोजन का उद्घाटन-

- मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ने 26 अप्रैल 2017 को किया गया।
- उद्घाटन समारोह में राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, कलेक्टर, किमश्नर तथा लघु उद्योग भारती के केंद्रीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
- मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापार और रोजगार के विस्तार हेतु गुजरात सरकार GIDC के आधुनिकीकरण व MSME क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है।

मुख्य घोषणाएँ एवं पहल-

- MSME आयुक्तालय की स्थापना— मुख्यमंत्री श्री रूपाणी ने गुजरात में MSME क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु एक स्वतंत्र MSME उद्योग आयुक्तालय की घोषणा की।
- बजट में आवंटन आगामी बजट (2018) में MSME विकास के लिए विशेष राशि आवंटित करने का वादा किया, जिसे बाद में पूरा भी किया गया।

उद्योग दर्शन @ राजकोट

- सरकारी सहयोग भारतीय रेलवे विभाग, पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड तथा गुजरात ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा विक्रेता पंजीकरण और विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सिडबी की पहल निवेश प्रबंधन और निर्यात संवर्धन पर विशेष

संगोष्ठियों का आयोजन सिडबी द्वारा किया गया।

- मेले की प्रमुख विशेषताएँ-

- स्टॉल्स लगभग 300 स्टॉल्स विभिन्न उद्योगों व कंपनियों द्वारा लगाए गए।
- भागीदारी गुजरात व भारत के विभिन्न भागों से
- आगंतुक चार दिनों में लगभग 20,000 से अधिक विजिटर्स प्रदर्शनी में आए। फेयर B2B और B2C दोनों प्रकार का था।



- आयोजित संगोष्ठियाँ व सेमिनार-

फेयर के दौरान विविध विषयों पर उपयोगी संगोष्ठियाँ और सेमिनार आयोजित किए गए, जिनमें विशेष रूप से निम्न प्रमुख रहे —

उद्योग उत्थान विशेषांक



- पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास
- औद्योगिक वित्त पोषण
- पश्चिम रेलवे विक्रेता विकास
- व्यापार में विश्व हिंदू समुदाय का योगदान
- पारिवारिक व्यवसाय का संवर्धन
- उद्यमिता और युवा अवसर
- ऋण गारंटी योजना
- वस्त्र उद्योग के नए आयाम
- महत्वपूर्ण वक्तव्य-
- उद्योग राज्य मंत्री श्री रोहितभाई पटेल ने औद्योगिक नीतियों व कल्पाणकारी योजनाओं को लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
- लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मित्तल ने सरकार के साथ हुए समझौतों की जानकारी साझा की।
- लघु उद्योग भारती (गुजरात) के अध्यक्ष श्री हितेंद्रभाई जोशी ने इसे "उद्योग का कुंभ" बताते हुए कहा कि देशभर के उद्यमियों का सहयोग इस मेले की सबसे बड़ी उपलब्धि है।



- आगंतुकों का उत्साह-
- आयोजन में विभिन्न संघठनों के पदाधिकारी, उद्योगपित, शिक्षाविद, छात्र और व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

- आम आगंतुकों, छोटे उद्यमियों और छात्रों के लिए यह आयोजन सीखने, समझने और नए अवसर खोजने का मंच साबित हुआ।
- प्रदर्शनी देखने आए आगंतुकों ने आयोजकों की सराहना करते हुए इसे एक बहुत ही उत्कृष्ट और सुव्यवस्थित आयोजन बताया।

उपलब्धियाँ और प्रभाव-

- नए अवसरों का सृजन MSME उद्यमियों को नए बाजारों, नीतियों और योजनाओं की जानकारी मिली।
- सरकारी—निजी सहयोग राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग की नई संभावनाएँ बनीं।
- विद्यार्थियों को लाभ कॉलेज के छात्रों को उद्यमिता और औद्योगिक क्षेत्र की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई।
- नवीन उत्पाद प्रदर्शन 300 से अधिक कंपनियों द्वारा नवीन तकनीक और उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जिनसे उद्योगकारों को नए विचार मिले।

राजकोट में आयोजित इण्डिया इण्डिस्ट्रियल फेयर-2017 लघु उद्योग भारती के गुजरात प्रदेश सौराष्ट्र संभाग की एक बहुत ही सराहनीय और ऐतिहासिक पहल रही। इस आयोजन ने न केवल MSME क्षेत्र को नई दिशा दी, बल्कि हजारों उद्यमियों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को उद्योग जगत से जोड़ने का कार्य किया।

चार दिवसीय इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि सरकार, संगठन और उद्योगपति मिलकर काम करें तो औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। इस प्रकार, यह आयोजन वास्तव में उद्योग जगत का एक महाकुंभ सिद्ध हुआ।









जयपुर के जेईसीसी में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2018 का शुभारंभ राजस्थान सरकार के गृहमंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने किया। उन्होंने युवाओं से नौकरी की बजाय स्टार्टअप अपनाकर उद्यमिता की राह चुनने का आह्वान किया। कटारिया ने कहा कि लघु उद्योग ही रोजगार सृजन और मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार हैं। उन्होंने आदिवासी अंचलों में लघु उपवन उपज को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों के बाय-प्रोडक्ट्स पर कार्य कर किसानों की दशा सुधारने की आवश्यकता बताई।

समारोह की अध्यक्षता राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने की। उन्होंने उद्योगों के लिए बिजली द्रांसिमशन में सुधार और रूफटॉप सोलर सिस्टम अपनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मित्तल ने नए उद्यमियों को बिजली पर सब्सिडी देने की मांग रखी। वहीं हरियाणा के श्रम व रोजगार मंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की औद्योगिक निवेश नीति—2015 और वन रूफ सिस्टम की जानकारी साझा की। रीको के सीएमडी श्री राजीव स्वरूप ने उद्यमियों को नोटबंदी व जीएसटी की चुनौतियों से उबरने और रीको नियमों को सरलीकृत कर राहत प्रदान करने की बात कही। उद्योग आयुक्त श्री कुंजीलाल मीणा, एसबीआई के सीजीएम श्री विजय रंजन, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र गुप्त सहित कई गणमान्य जनों ने विचार साझा किए।

उद्योग दर्शन @ जयपुर

उद्योग व निवेश पर चर्चा-

इस सत्र में विभिन्न प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों ने निवेश नीतियों और औद्योगिक विकास की दिशा पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री छगन मूंदड़ा, श्री एसपी मोहंती तथा अन्य अतिथियों ने उद्योगों को मजबूत बनाने में राज्यों की भूमिका पर चर्चा की।

अतिथियों का पारंपरिक सम्मान श्रीफल, शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। मंच संचालन सीए योगेश गौतम और श्री महेंद्र मिश्रा ने किया।

तकनीकी व सेमिनार सत्र-

फेयर के दौरान "मंत्रा ऑफ सक्सेस एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप"विषय पर विशेष सत्र आयोजित हुआ, जिसमें सफल उद्यमियों ने युवाओं से अपने अनुभव साझा किए। इससे नई पीढ़ी को स्टार्टअप और सामाजिक उद्यमिता की दिशा में प्रेरणा मिली। देशभर के उद्यमियों ने अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। मेले के समापन पर 8 सर्वश्रेष्ठ स्टॉल्स को सम्मानित भी किया गया। प्रदर्शनी ने उद्यमियों को न केवल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म दिया, बल्कि उन्हें अपनी पहचान बनाने का अवसर भी प्रदान किया।

समापन-सत्र

चार दिवसीय मेले का समापन केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री श्री सी.आर. चौधरी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और मुद्रा ऋण योजना रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी में 8%, मैन्युफैक्चरिंग में 45% और विदेशी व्यापार में 40% योगदान देता है, साथ ही 40% रोजगार भी प्रदान करता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोक परनामी ने जीएसटी को कर सुधारों में मील का पत्थर बताया। उन्होंने मुद्रा योजना के

उद्योग उत्थान विशेषांक



तहत करोड़ों लोगों को ऋण देकर स्वावलंबी बनाए जाने का उल्लेख किया।



आईआईएफ-2018 के नेशनल चेयरपर्सन श्री ओमप्रकाश मित्तल ने आयोजन को सफल बताते हुए इसे भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने की घोषणा की।

समापन समारोह में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री योगेश



गौतम, जोधपुर नगर निगम के महापौर श्री घनश्याम ओझा, राजस्थान के एसजीएसटी कमिश्नर श्री आलोक गुप्ता,



जयपुर शहर के सांसद श्री रामचरण बोहरा, आईआईएफ के संयोजक श्री महेंद्र खुराना, जोधपुर प्रांत के श्री राजेंद्र राठी सहित प्रदेशभर के पदाधिकारी व उद्यमी मौजूद थे। आखिरी दिन फेयर में बड़ी संख्या में विजिटर्स ने शिरकत की।







HF-2022 @ Guwahati



The Assam edition of IIF (Udyam-2022) has once again reaffirmed its reputation as one of the largest and most impactful industrial trade shows in India. Known for bringing together MSMEs from across the country, the 6th edition carried forward the legacy of promoting industries across multiple sectors including machine tools, handicrafts, handloom, agriculture, plastics, hardware, home décor, and food processing. With more than 427 stalls, 30,282 visitors, and spread over a sprawling area of 1,20,000 sq. ft, the fair provided a comprehensive business platform for importers, exporters, wholesalers, distributors, retailers, and startups.

Exhibition Infrastructure:

The organizers created a world-class exhibition environment with three fully air-conditioned halls measuring 26,400 sq. ft each. A separate 9,600 sq. ft hall with stage facilities was dedicated for inaugural and closing ceremonies, cultural events, and Udyami Sammelan.

Inaugural and Dignitaries' Presence:

The opening ceremony on 22nd April, 2022 was graced by Assam's Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Union MSME Minister Shri Narayan Rane, and Assam's Industries & Commerce Minister Shri Chandra Mohan Patowary. The fair also had the privilege of welcoming Defence Minister Shri Rajnath Singh on the second day, making the event even more prestigious. Their presence highlighted the importance of MSMEs in India's economic framework and emphasized the government's commitment to empowering small industries.

Institutional Support and Collaborations:

The fair was jointly organized with the Department of Industries, Commerce & Public Enterprise, Assam. The DICC mobilized participants from all districts and provided 68 stalls, promoting the "Vocal for Local" initiative. The MSME Ministry extended strong support with 104 stalls and financial backing. The Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) brought in 40 exhibitors showcasing regional handicrafts, while the National Small Industries Corporation (NSIC) contributed with 37 stalls. These collaborations made the fair a true convergence of government, industries, and entrepreneurship.

Seminars and Knowledge Sessions:

A distinctive highlight of Udyam 2022 was its nine high-value seminars, addressed by experts from diverse domains. The sessions covered crucial topics including Banking & Finance, Industrial Policy,

Tourism & Handicraft, Renewable Energy, Petroleum downstream industries, Agri-wood, Export Promotion, Waste Management, and Food Processing. Each seminar provided actionable insights and policy recommendations.

Key Recommendations:

Speakers like Dr. Samir Baruah and CA Purshottam Gaggar emphasized the need for banks to extend adequate financing to sunrise sectors, backed by specialized training for branch managers in the Northeast. They stressed the importance of financial



literacy drives, increasing forex branches, and rationalizing interest rates under CGTMSE. Recommendations also highlighted reforms in land policies to make tribal and industrial lands mortgageable, enabling smoother flow of credit in Assam and the Northeast.

Industrial Policy, Tourism & Renewable Energy Discussions:

Experts such as Shri Manoj Verma and Shri Prafulla Saikia suggested compulsory energy and water audits for industries and called for real reforms in Ease of Doing Business (EODB). They advocated capital incentive schemes similar to Gujarat to encourage MSME investments. In the tourism and handicraft session, speakers highlighted untapped opportunities in eco-tourism and the global demand for handicraft products. On renewable energy, the need for a specific solar policy, biogas plants, and decentralized energy solutions for rural Assam was underlined.

Agri-Wood, Petroleum, and Export Promotion Insights:

Sessions on agri-wood explored the scope of bamboo innovation and palm oil cultivation, emphasizing the requirement of a comprehensive Bamboo Policy. In petroleum, experts showcased how Assam could benefit from downstream industries with over 120

derivative products. The export seminar stressed on building awareness, more export centers, and stronger banking support for international trade from the Northeast.

Waste Management and Food Processing:

The waste management seminar focused on recycling opportunities in plastic, hazardous, and construction waste. Experts called for a Waste Recycling Incentive Policy to generate both employment and environmental sustainability. In food processing, speakers discussed spice industry potential, packaging innovations, and the need for better government-industry coordination to boost exports of fruits, vegetables, and spices from the region.

Special EPCH Seminar:

The EPCH organized a focused seminar on product development, design, and marketing opportunities in the post-COVID era. It highlighted the importance of digital marketing, social media, and global compliance requirements while also spreading awareness about government schemes for artisans and women entrepreneurs.

Udyami Sammelan and Cultural Showcase:

On 25th April, the Udyami Sammelan was graced by Union Minister Shri Somprakash, RSS Sah Sarkarwah Dr. Krishnagopal ji, and Assam's Industries Minister Shri Chandra Mohan Patowary. The cultural programs over three days showcased Northeast's vibrant rich heritage through folk music and dance.

Impact and Conclusion:

The IIF Udyam-2022 created an impactful platform for MSMEs across food processing, handicraft, agriculture, plastics, renewable energy, and allied sectors. It enabled exhibitors to connect with distributors, investors, and government agencies, while visitors gained a broader perspective on emerging industries.

The strong policy recommendations, collaborative spirit, and cultural integration made the fair a holistic experience. With its success, Udyam-2022 not only strengthened Assam's industrial ecosystem but also paved the way for greater MSME participation in India's economic growth.





वस्त्र नगरी के रूप में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका राजस्थान का भीलवाड़ा शहर सितंबर 2023 में एक बार फिर उद्योग जगत का केंद्र बना। इंडिया इंडिस्ट्रियल फेयर (IIF) का सातवां संस्करण 15 से 17 सितंबर तक आयोजित हुआ और तीन दिनों तक उद्योग, तकनीक और नवाचार की एक शानदार प्रदर्शनी ने आगंतुकों को आकर्षित किया। यह केवल एक औद्योगिक प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि यह उस ऊर्जा, कौशल और संकल्प का उत्सव था जिसने भारत को आत्मनिर्भरता और 'मेक इन इंडिया' के पथ पर अग्रसर किया है। ये सेक्टर विशेष पर आधारित पहली प्रदर्शनी भी रही।

आयोजन की मुख्य झलकियाँ-

उद्घाटन - तत्कालीन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने किया।

16 सितंबर - केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश का आभासी संबोधन।

टेक्निकल टेक्सटाइल पर सेमिनार, जिसमें श्री महेश मायेकर और श्री मनीष त्यागी ने विस्तृत और ज्ञानवर्धक जानकारी दी। समापन- टेक्सटाइल सेक्टर आधारित इस अभिनव प्रदर्शनी के 17 सितंबर को आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वर्चुअल संदेश रहा, जिसमें उन्होंने MSME सेक्टर को भारत की आर्थिक सफलता की रीढ़ बताया।

उद्योग दर्शन @ भीलवाड़ा

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में बताया कि स्किल यहां के उद्यमियों के डीएनए में है, और भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई नहीं रोक सकता।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा ने कहा कि संगठन के लिए अभी जो अनुकूल समय है वह लंबी तपस्या के बाद आया है, जिसमें लघु उद्योगों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।

फोयर का औद्योगिक महत्व-

- इस फेयर में देशभर से फाइबर, यार्न, फैब्रिक, गारमेंट्स, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और माइनिंग सेक्टर के प्रदर्शक जुटे।
- वीविंग, यार्न, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, वार्पिंग, फोल्डिंग जैसी नवीनतम मशीनरी प्रदर्शित हुई।
- मशीनों के लाइव डेमो ने दर्शकों को आकर्षित किया।
- एमएसएमई, पैकिंग मटेरियल, फैब्रिक टेस्टिंग और हिट सेटिंग जैसी तकनीकें भी मुख्य आकर्षण रहीं।



सहयोग और सहभागिता-

इस प्रदर्शनी को सफल बनाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिलोसा इंडस्ट्रीज़ सूरत, आरसीएम ग्रुप भीलवाड़ा, हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टील और भारत सरकार के MSME विभाग का विशेष सहयोग रहा।



तीन दिवसीय फेयर के आयोजन में भीलवाड़ा के पूर्व सांसद श्री सुभाष बहेड़िया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक नेटवर्क —2 श्री हेमंत करौलिया, लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव भाई प्रजापति एवं श्री ओपी मित्तल, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री योगेश गौतम, राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़, महामंत्री श्री योगेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री विमल किटहार एवं डॉ.संजय मिश्रा, चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष श्री पवन गोयल, महासचिव श्री प्रवीण गुप्ता, टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ी हुई हस्तियों सिहत कई सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति रही।

फेयर अध्यक्ष श्री महेश हुरकट और उनकी टीम ने इसे पूर्णतः कपड़ा उद्योग एवं मशीनरी को समर्पित रखने का संकल्प लिया और आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया।

तीन दिवसीय फेयर में भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा,

किशनगढ़, जयपुर, सूरत और अहमदाबाद जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों से लगभग 7000 से अधिक उद्यमी उद्योग दर्शन के लिए पहुंचे और इसे सराहा। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी से उन्हें अपने बिजनेंस को नई ऊंचाई और आकार देने के लिए बेहतर बी2बी प्लेटफार्म मिला है।

इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया गया जिसमें सभी एक्जीबिटर्स के साथ भीलवाड़ा कपड़ा उद्योग की जानकारी भी दी गई।

भीलवाड़ा में आयोजित इस फेयर में 95 एक्जीबिटर्स ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी से ये संदेश दे दिया कि भारत का एमएसएमई सेक्टर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां प्रदर्शित तकनीक और कौशल ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय उद्यमियों का विजन अब केवल घरेलू नहीं, बल्कि ग्लोबल है।

आत्मिनर्भर भारत के संकल्प को साकार करती इस प्रदर्शनी ने सभी उद्यमियों को प्रेरित किया और लघु उद्योगों के उत्थान के लिए नई दृष्टि भी प्रदान की। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि IIF-2023 ने टेक्सटाइल उद्योगों में तकनीकी टेक्सटाइल के महत्व, स्टार्टअप, लेटेस्ट मशीनरी सहित सभी पहलुओं को देखने—समझने की दिशा में एक सशक्त पहल की है।

फेयर कन्वीनर श्री गिरीश अग्रवाल ने बताया कि भारत उद्योग दर्शन प्रदर्शनी का तीन दिवसीय आयोजन बहुत सफल रहा जिसमें टीम भीलवाड़ा ने आयोजन के उच्च मानकों को स्थापित किया।







लघु उद्योग भारती के फ्लैगशिप कार्यक्रम इंडिया इंडिस्ट्रियल फेयर के 8वे संस्करण (IIF-2025) का सफल आयोजन उदयपुर में 9 से 13 जनवरी को हुआ। चार दिवसीय इस औद्योगिक मेले ने उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को एक ही मंच पर जोड़ते हुए उद्योग जगत को नई दिशा प्रदान की। डीपीएस मैदान, उदयपुर में आयोजित यह मेला न केवल लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए प्रेरणादायी साबित हुआ, बल्कि इसे राजस्थान और भारत के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना गया।



उद्घाटनः संगठन मंत्र और दीप प्रज्वलन-

10 जनवरी को मेले का उद्घाटन लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि "लघु उद्योगों की तपस्या से निकला अमृत भारत को विश्व में अग्रणी बनाएगा। "उन्होंने संगठन मंत्र "संगच्छध्वं संवदध्वं" का उच्चारण कर सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का संदेश दिया। दीप प्रज्वलन और भगवान विश्वकर्मा की आरती के साथ मेले की शुरुआत हुई। उदयपुर जिलाध्यक्ष श्री मनोज जोशी ने मेले की रूपरेखा प्रस्तुत की, वहीं संयोजक श्री तरुण दवे और सह—संयोजक श्री मुकेश सिन्हा ने अतिथियों का स्वागत किया।

उद्योग दर्शन @ उदयपुर



नवाचार और उद्यमिता के केंद्र चार डोम्स-

मेले का सबसे बड़ा आकर्षण इसके चार डोम्स रहे, जिन्हें भारतीय महापुरुषों के नाम दिए गए—

- 1. महाराणा प्रताप डोम
- 2. भगवान विश्वकर्मा डोम
- 3. भामाशाह डोम
- 4. अहिल्या बाई डोम

इन डोम्स में कुल 400 स्टॉल स्थापित किए गए, जिनमें 200 से अधिक उद्यमियों ने अपनी भागीदारी निभाई। मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, टेक्सटाइल और आयुर्वेदिक उत्पादों का व्यापक प्रदर्शन हुआ। विशेष रूप से अहिल्या बाई डोम में महिला उद्यमियों के हस्तनिर्मित वस्त्र, जूट बैग, हर्बल प्रोडक्ट्स और गृह—उपयोगी सामग्री ने दर्शकों को आकर्षित किया।



महिला उद्यमियों की सशक्त भागीदारी-

मेले में महिलाओं की सक्रिय उपस्थित इसकी एक खास विशेषता रही। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और महिला उद्यमियों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा — "आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे आयोजन उनके लिए नए अवसरों का द्वार खोलते हैं।" महिला उद्यमियों के बूथों पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि महिला शक्ति व्यापार जगत में भी तंजी से आगे बढ़ रही है।



चार दिनों तक चले इस मेले में 75,000 से अधिक आगंतुकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप्स को लेकर युवाओं का उत्साह देखने योग्य था। रविवार को मेले में सबसे अधिक भीड़ उमड़ी, जिसमें शहर के कई कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी भी शामिल रहे। मेले में लगे स्टॉल्स पर 15% से 55% तक की छूट दी गई, जिससे खरीदारी का माहोल और भी जीवंत बन गया।

प्रेरक विचार और अन्य खास झलकियां-

समापन समारोह में राजस्थान सरकार के जनजाति विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा — "भारत को 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इसमें उद्योग एवं उद्यमिता की निर्णायक भूमिका होगी।"

सांसद डॉ.मन्नालाल रावत ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर महिला उद्यमियों की सराहना की और इस आयोजन को युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा ने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के समर्पण को लघु उद्योग भारती की सबसे बड़ी ताकत बताया।

लघु उद्योग भारती के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालंड ने राज्य की नई ग्रीन एनर्जी पॉलिसी की जानकारी दी, जिसके अंतर्गत उद्योग अब 200% तक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे। यह घोषणा उद्यमियों के लिए एक बड़ा उत्साहवर्धक संदेश रही।



- कैलेंडर विमोचन उदयपुर इकाई की ओर से आगामी आयोजनों को दर्शाते हुए एक वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया गया।
- सुव्यवस्थित प्रबंधन पार्किंग, भोजन, और प्रचार-प्रसार की व्यवस्था मेला संयोजन टीम द्वारा बखूबी संभाली गई।



भविष्य की नयी दृष्टि के साथ समापन-

समापन अवसर पर लघु उद्योग भारती के प्रदेश महासचिव श्री योगेंद्र शर्मा ने इसे सफल आयोजन बताया और जानकारी दी कि अगले वर्ष यह मेला और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस बार के अनुभव से प्रेरित होकर 67 उद्यमियों ने अगले वर्ष के आयोजन में भागीदारी के लिए अग्रिम सहमति जताई।

11वे इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर—2025 ने यह सिद्ध कर दिया कि लघु उद्योग भारत की आर्थिक रीढ़ हैं। यह आयोजन "वोकल फॉर लोकल" की अवधारणा को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक ठोस कदम रहा। उदयपुर को आद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने की दृष्टि से यह मेला एक मील का पत्थर बन गया। इस आयोजन ने नवाचार, रोजगार और व्यापारिक सशक्तिकरण को एक साथ जोड़कर सफलता की नई ऊँचाइयों को छुआ।





लघु उद्योग भारती द्वारा इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का नवां एडिशन गुजरात के सौराष्ट्र संभाग में राजकोट में किया गया। 2 से 5 फरवरी, 2025 तक आयोजित इस चार दिवसीय प्रदर्शनी के लिए जर्मन हैंगर प्रकार के आठ विशाल वातानुकूलित, वॉटरप्रूफ और फायरप्रूफ डोम बनाए गए थे। इसमें भारतीय रेलवे के सभी विभाग, GeM (Governmente-Marketplace) और अन्य संस्थानों सहित 300 से अधिक औद्योगिक स्टॉल शामिल हुए।

कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां-

यह आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहली बार औद्योगिक प्रदर्शनी में भारतीय रेलवे के सभी विभागों ने भाग लिया। ळमड पंजीकरण ने भी रिकॉर्ड तोंड़ा, जिससे सूक्ष्म व लघु उद्यमों को बड़ा लाभ मिला। 300+ स्टॉल्स ने विक्रेताओं और खरीदारों को व्यापारिक अवसर उपलब्ध कराए और नेटवर्किंग का मजबूत मंच प्रदान किया।

प्रदर्शनी की प्रमुख झलकियां-



उद्योग दर्शन @ राजकोट

सरकारी विभागों के साथ निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी रही। आगंतुकों की सुविधा हेतु मोजन व नाश्ते का विशेष डोम बनाया गया। उद्धाटन, सेमिनार और समापन समारोह के लिए भी विशाल पंडाल लगाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राजकोट म्युनिसिपल किमश्नर के सहयोग से "जीरो वेस्ट मैनेजमेंट" स्टॉल लगाया गया। सभी स्टॉलधारकों और अतिथियों को स्मृति—चिह्न स्वरूप धातु पत्र से बना गुजरात का नक्शा व संस्था का लोगो भेंट किया गया।

विशिष्ट अतिथियों की उपस्थित-

आयोजन में गुजरात के कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर व किमश्नर सिंहत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, अन्य उद्योग संघों के पदाधिकारी और उद्योगपित भी शामिल हुए। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय महामंत्री श्री ओमप्रकाश गुप्ता और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष श्री जनक भाटिया ने मार्गदर्शन किया। सभी अतिथियों ने आयोजन की उत्कृष्टता की प्रशंसा की।



प्रबंधन और संगठन-

इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए चेयरमैन IIF-9 एवं उपाध्यक्ष सौराष्ट्र संभाग श्री गणेशभाई ठुंमर, श्री हंसराजभाई गजेरा और श्री जयभाई मावानी ने समन्वय और नेतृत्व किया। जामनगर व अन्य जिलों के साथ कर्णावती

संभाग का भी सहयोग रहा। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और प्रभारी सहित केंद्रीय पदाधिकारियों ने समय—समय पर मार्गदर्शन दिया। राजकोट कार्यालय की टीम ने स्टॉल बुकिंग, डिजाइन, ब्रांडिंग, साइट डेवलपमेंट और मीडिया प्रमोशन का कार्य कुशलता से किया। आयोजन का समन्वय श्री विजय पारखिया ने किया।



रेलवे और GeM की सहभागिता

भारतीय रेलवे के सभी विभागों की भागीदारी इस मेले की ऐतिहासिक उपलब्धि रही। रेलवे अधिकारियों ने प्रदर्शनी की स्वच्छता, सुरक्षा और भोजन व्यवस्था की सराहना की। GeM का रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ, जिससे उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़ने का बड़ा अवसर मिला। यह सहभागिता भविष्य में व्यापार को बढ़ावा देने का आधार बनेगी।



सहयोग और सहभागिता-

इस आयोजन को सफल बनाने में सेवा भारती संस्था सहित विभिन्न जिलों के सदस्यों का योगदान रहा। केंद्रीय कार्यालय के पदाधिकारी व कर्मचारी भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। खासकर रेलवे और GeM को शामिल करवाने में श्री प्रकाश चंद्र जी का प्रयास उल्लेखनीय रहा।

छोटे उद्यमियों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम आगंतुकों के लिए प्रवेश नि:शुल्क रखा गया। परिणामस्वरूप भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का लाभ उठाया। इससे नए और छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला तथा व्यापार बढ़ाने के अवसर प्राप्त हए।

आयोजन की विशेषता रही स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण, उत्कृष्ट प्रबंधन, रेलवे और GeM की भागीदारी तथा आगंतुकों की बड़ी संख्या। 2017 के बाद गुजरात में दूसरी बार ये औद्योगिक मेला राजकोट में आयोजित होना शहर के लिए गर्व की बात रही।



कुल मिलाकर, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2025 (IIF-9) राजकोट व्यापार, नवाचार और नेटवर्किंग का महाकुंभ सिद्ध हुआ। रेलवे और GeM की सहभागिता, रिकॉर्ड पंजीकरण, निजी व सरकारी क्षेत्र की सक्रियता ने इसे अविरमरणीय सफलता दिलाई। यह आयोजन लघु उद्योग भारती के संगठन, समर्पण और सामृहिक पुरुषार्थ का उत्कृष्ट उदाहरण है।







^{विश्व} आत्महत्या रोकथाम ^{दिवस}

10 सितम्बर, 2025

CHANGING THE NARRATIVE ON SUICIDE

आत्महत्या को रोका जा सकता है,

आइए ! संवाद प्रारंभ करें

मिथक

- आत्महत्या के बारे में खुलकर बात या चर्चा करने हो आत्महत्या की प्रवृति को बढ़ावा मिलता है।
- केवल मानसिक रुग्णता से ग्रसित लोग ही आत्महत्या करते हैं।
- अधिकांश आत्महत्याएं बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक होती है।

तथ्य

- आत्महत्या के बारे में खुलकर बात या चर्चा करने से व्यक्ति को आत्महत्या से जुड़े जोखिम कारकों को पहचानने में मदद मिलती है और सहायता के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में उचित जानकारी मिलती है।
- आत्महत्या का विचार गहरी नाखुशी का संकेत देता है, लेकिन जरूरी नहीं
 कि यह मामसिक विकार हो। कई बार मानशिक रोगों से ग्रस्त लोगों में
 आत्महत्या के विचार नहीं आते हैं।
- अधिकांश आत्महत्या अचानक नहीं होती है। हम जानकारी के अभाव में चेतावनी संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। इन्हें पहचानना अतिआवश्यक है। इससे समय रहते किसी व्यक्ति की जान बचायी जा सकती है।

समय रहते चेतावनी संकेतों की पहचान, भावनात्मक सहयोग और चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार से आत्महत्या के प्रयासों को रोका जा सकता है

याद रखें

- मदद मांगने में संकोच ना करें।
- उम्मीद तमाए रखें एवं मदद अवश्य लें।
- अपना समय-धन झोलाझाप, झाइ-फूंक, बाबा, तांत्रिक, ओझा, भोपा आदि में व्यर्थ नहीं करें।



मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं भावनात्मक सहयोग के लिए

24 घंटे उपलब्ध **रेलीमानस रोल फ्री हेल्पलाइन नं.** 14416 अथवा 1800-89-14416 पर संपर्क करें।

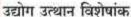


राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिरान

राष्ट्रीय मागसिक स्वास्य कार्यक्रम

चिकित्सा एवं स्थार्थ्य विभाग अर्छ्डेसी राजस्थान द्वारा प्रनिति में प्रसारित







South Gujarat April 9-10, 2026 Central Gujarat June 10-11, GUJARAT REGI NAL

Replicating the Successful Model of Vibrant Gujarat at the Regional Level

CONFERENCES The Government of Gujarat is now organizing four Vibrant Gujarat Regional Conferences in North Gujarat, Kutch and Saurashtra, South Gujarat and Central Gujarat, each serving as a gateway to accelerated regional growth, ahead of the next edition of the Vibrant Gujarat Global Summit. These regional conferences will be preceded by a one-day district-level program. The conferences aim to showcase the unique investment potential and strengths of each region, capitalize on opportunities and catalyze ground-level development.





(लघु उद्योग भारती के निःस्वार्य उद्यमी सदस्यों के ईमानदार प्रयासों का परिणाम है कि पाली मारवाड़ में सिर्फ कौशल के बूते बड़ी संख्या में महिलाओं ने आर्थिक सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी है ।)

बीते 5 वर्षों में सिलाई कौशल प्रकल्प में स्वरोजगार के लिए दी गई करीब 5700 सौ मशीनों ने पाली के औद्योगिक जगत में क्रांति कर दी है।



बड़ी पहल डॉ. संजय मिश्रा को-एडिटर, उद्योग टाइम्स dr.sanjay.jpr@gmail.com

राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 3 सौ किलोमीटर दूर मारवाड़ क्षेत्र में स्थित पाली शहर इन दिनों चर्चा में है। यहां लघु उद्योग भारती द्वारा स्वावलंबन एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में बीते पांच वर्षों से उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। कंप्यूटर, सिलाई, चूड़ी पर नगीने लगाने, मिटटी के कुल्हड़ बनाने, मेहंदी आर्ट और ब्यूटी पॉर्लर जैसे कौशल आधारित और कम लागत वाले व्यावसायिक कार्यों से यहां की हजारों महिलाओं को जोड़ा गया जो आज आर्थिक रूप से न केवल अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार के सफलतापूर्वक संचालन में अपना सक्रिय सहयोग कर रही हैं, बल्कि उनमें से कइयों ने तो इससे भी चार कदम आगे बढकर नियोक्ता के तौर पर अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने का बड़ा काम किया है। पाली क्षेत्र की मारवाडी उद्यमी महिलाओं की उद्यमिता और उनकी कामयाबी की वजह से ही इस स्वरोजगार के प्रकल्प को 'पाली मॉडल' का नाम तक दे दिया गया है। लिहाजा ये जानना तो लाजमी ही है कि आखिर स्वावलंबी भारत की मुहिम में ये छोटा-सा शहर इतना आगे क्यों निकल गया! आइये, जानते हैं सिलाई, चूड़ी, कुल्लड़ के साथ सौंदर्य-सज्जा एवं मेहंदी प्रकल्प की सफलता की कहानी इस ग्राउंड रिपोर्ट में।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एनआईसीडीपी) के तहत 28209 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से 12 नए औद्योगिक केंद्रों को मंजूरी दी गई जिसमें पाली के पावरफुल प्रोफाइल के मद्देनजर जोधपुर—पाली क्षेत्र का नाम भी सम्मिलित किया गया है जो भारत के वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

पाली में करीब 800 की संख्या में प्रोसेस हाउस और 2500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सक्रिय हैं जिनमें प्रतिदिन सवा करोड़ मीटर कपड़ा प्रोसेस होता है, और इस हिसाब से सालाना बिजनेस टर्नओवर करीब 15 हजार करोड़ रु. से अधिक चला जाता है।

1940 के दशक तक दुनियाभर में अपनी उत्कृष्ट मखमली लिली पोपलिन के लिए विख्यात पाली आज साड़ी फॉल, मैचिंग अस्तर, ब्लाउज पीस का हब बन चुका है। साथ ही दुपट्टे, पगड़ी और सलवार—कुर्ती के कपड़े और तैयार प्रोडक्ट के लिए भी बड़ा केंद्र है। डाईंग, प्रिंटिंग और फिनिश के साथ पिग्मेंट प्रिंट पाली की खास पहचान है।

कौशल विकास की आधारभूमि-

पाली में स्वरोजगार और स्वावलम्बन का कार्य शुरू होने के पीछं दो महत्वपूर्ण कारक रहे। पहला कोविड और दूसरा प्रवासी श्रमिक। पहले बात कोविड की करते हैं। तो बात उन दिनों की है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जनित वैश्विक महामारी कोविड-19 के खौफ के साथे में जी रही थी। और खौफ भी ऐसा कि सर्विस सेक्टर ने तो अपने कर्मियों की बिना किसी सूचना के छटनी कर दी थी और जो जॉब पर बचे भी रहे. उनकी सैलरी में मनमाने तरीके से कटौती कर दी गई। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात है, तो वहां भी कुछ को छोड़कर अधिकांश उत्पादों की मांग अप्रत्याशित रूप से गिरने के कारण बड़ी संख्या में या तो कुछ समय के लिए फैंक्ट्रियों को शट डाउन कर दिया गया या सीमित उत्पादन (कंट्रोल्ड प्रोडक्शन) कर अतिरिक्त कर्मचारियों को सीधे काम से हटा दिया गया। ये सिलसिला शुरू हुआ था निजी स्वामित्व वाली छोटी कंपनियों से, जो बाद में मध्यम और फिर बड़ी कंपनियों में भी देखने को मिला। मल्टीनेशनल कंपनियां भी कोविड के प्रकोप से नहीं बची थी। इस सबसे देशभर में लाखों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट गहराया हुआ था।

संयोग से उसी दौरान पाली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई थी जिसमें लघु





कोरोना वायरस के वक्त सिलाई प्रकल्प में स्वरोजगार के लिए स्थानीय प्रशिक्षित महिलाओं को मशीन वितरण कार्यक्रम

उद्योग भारती के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा एवं संघ के जोधपुर प्रांत कार्यवाह श्री श्याम मनोहर ने कोविड के बाद के परिदृश्य में लोगों के लिए रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास और स्वावलंबन विषय पर उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया। वास्तव में यहीं से कौशल केंद्र की स्थापना के विचार का बीजारोपण हुआ था। इस क्षेत्र में कौशल विकास की बड़ी जिम्मेदारी लघु उद्योग भारती को दी गई। औपचारिक रूप से इस प्रकल्प की शुरुआत वर्ष 2021 में जुन के महीने में कर दी गई।

अब बात प्रवासी श्रमिकों की भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली राजनीतिज्ञ आजम खान के इलाके रामपुर के रहने वाले 5 से 7 हजार मुसलमान युवक पाली के प्रोसेस हाउस में बहुत समय से काम कर रहे थे। लेकिन प्रवासी श्रमिकों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोविड के बदले हालात से टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर से कभी उबर भी पायेगी। उनके मन में अनिश्चितता और अनदेखा भय था जिससे उन्होंने एक बार किसी बात को लेकर ऐसा बवाल मचाया कि फिर वो थमा ही नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि जिन फैंक्ट्रियों में वे काम कर रहे थे, वहां का काम ही उप्प हो गया। इस घटना के बाद से बड़े उद्यमी भी सकते में आ गए और उन्होंने पहली बार स्थानीय लोगों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करने के बारे में गंभीरता से सोचा।

कौशल प्रकल्प के लिए टीम का गठन-



तात्कालिक परिस्थितियों में उद्योगों के लिए अनुकूल विषय होने के बावजूद ये कार्य कोई आसान नहीं था, क्योंकि कौशल के लिए एक ऐसे मॉडल को लागू करना जरूरी था जिससे दीर्घकालिक परिणाम मिल सके और उससे जुड़ने वाले प्रशिक्षणार्थी सतत रूप से उस कार्य को कर सकें। इसलिए एक शुरुआती कोर टीम का गठन किया गया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांत कार्यकारिणी सदस्य श्री कमल किशोर गोयल, लघु उद्योग भारती के प्रदेश संयुक्त सचिव एवं राजस्थान टैक्सटाइल हैंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन, पाली के अध्यक्ष श्री विनय बंब एवं राजस्थान विधानसभा में पाली का 6 बार प्रतिनिधित्व करने वाले लोकप्रिय जन प्रतिनिधि श्री ज्ञान चंद पारख शामिल थे।

श्री कमल किशोर गोयल और श्री विनय बम्ब ने इंडस्ट्री के साथ समन्वय का कार्य किया जिससे जिन लोगों को मशीन दी गई, उन्हें नियमित घर बैठे जॉब भी मिल सके। पूर्व और अभूतपूर्व विधायक श्री ज्ञानचंद पारख के जिम्मे था प्रकल्प में नई मशीनों की खरीद एवं उन्हें स्थानीय इच्छुक महिला को स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराना। इस टीम ने तीन दिशाओं में कार्य शुरू किया—

- नि:शुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था
- प्रशिक्षण के बाद मशीन की उपलब्धता
- इंडस्ट्री से नियमित जॉब की सुनिश्चितता

प्रशिक्षण के बाद साधन की उपलब्धता का तो महत्व है ही, इसे कौन नकारेगा! लेकिन जब इसे भी निःशुल्क या फ्री जैसा कुछ करने की कोशिश की जाती है, तो फिर वो सफल नहीं होता। इस बात को टीम ने भी माना कि सब कुछ फ्री करने से तो वो खैरात बांटने जैसा हो जाता है। हाँ, प्रशिक्षण तक निःशुल्क व्यवस्था की गई। लेकिन इसमें भी अच्छी बात ये रही कि सभी महिलाओं को बाजार मूल्य से कम कीमत में मशीन उपलब्ध करवाई गई। मशीन की जब बल्क डील की गई, तो अपेक्षाकृत वो सस्ते में आ गई। इसी तरह डाउन पेमेंट को भी टोकन अमाउंट ही रखा गया और शेष किश्तों के निर्धारण को भी आसान किया गया। कौशल टीम का मत था कि जिसको सिलाई सिखानी है, उसे स्वाभिमानी और स्वावलंबी भी तो बनाना है। उसे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि किसी के सहारे वो खडी हो रही हैं, बल्कि वो रोज अपने श्रम से उपार्जित धन से मासिक किस्त चुकाकर खुद में आत्मविश्वास पैदा करती हैं।

टीम के सदस्य और कपड़ा उद्योग से लम्बे समय से जुड़े हुए



श्री कमल किशोर गोयल कहते हैं कि टीम ने इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट किया। और इंडस्ट्री ही क्यों, पाली शहर और देहात दोनों क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क किया गया। अन्य संगठनों को भी साथ आने के लिए तैयार किया। उन्होंने



संगठन की ओर से कही बात को समझा और सहयोग किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और लघु उद्योग भारती जैसे प्रामाणिक संगठन जब किसी विषय पर आह्वान करते हैं, तो समाज से अच्छा समर्थन मिलता ही है।

कम्प्यूटर और सिलाई दोनों विषयों में कौशल केंद्र को शुरू करने के लिए पहले—पहल विद्या भारती ने अपना विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर उपलब्ध करवाया। उसके पश्चात यहां पर केशव गौशाला ने भी अपना स्थान इस कार्य के लिए सहर्ष दे दिया। पाली में सेवा समिति वृद्ध आश्रम का संचालन करती है, तो साथ ही वहां स्थाई सिलाई केंद्र में बालिकाएं भी इसे सीखती हैं; यहां से भी सिलाई प्रशिक्षण में सहयोग मिला। वर्तमान में कौशल केंद्र का कार्य लघु उद्योग भारती किराए के भवन में संचालित कर रहा है।

सामाजिक परिवर्तन के पैरोकार उद्यमियों ने कौशल-यज्ञ में दी आहूति -

सर्वप्रथम सिलाई सेंटर प्रारंभ करने के लिए स्थानीय उद्यमी एवं समाजसेवी श्री पुखराज लसोड ने लगभग ₹3 लाख की लागत की 15 विदेशी सिलाई मशीन केंद्र के लिए स्थायी तौर पर प्रदान की, जो आज भी प्रशिक्षण केंद्र में लगी हुई है। हालांकि बाद में इस प्रकल्प की जानकारी मिलने के बाद ऐसे और भी बड़े टेक्सटाइल उद्यमी सामने आये, जो निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए अपनी मशीनें और जगह दोनों देने के लिए तैयार हुए। श्री अमरचंद समदिख्या, श्री अचलचंद बालड, श्री केसरीमल छाजेड़ ने अपने संस्थानों में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर जॉब भी प्रदान किया।

लघु उद्योग भारती के कौशल केंद्र में सिलाई कौशल में सबसे पहले दसवीं पास अनु कुमावत ने आना शुरू किया, क्योंकि उसकी स्कूल के नजदीक ही ये केंद्र स्थित था। उसके बाद परिवार के हालातों को समझकर पुष्पा बंजारा ने भी कौशल केंद्र का रुख किया। उसके बाद तो हिना राजपुरोहित और फिर एक-एक करके पूरा बैच ही बन गया। पहले बैच में कौशल सीखने वाली कई बालिकाओं ने आगे चलकर अपना काम बढ़ा लिया और अब वे खुद भी सिखाती हैं।

इसी बीच में स्थानीय उद्योगों की मांग पर टैली के साथ कम्प्यूटर आधारित कुछ अन्य सिकल कोर्सेस शुक्त किये गए। नए कम्प्यूटर सिस्टम भी खरीदे गए। इन कोर्सेज में बालिकाओं के साथ युवक भी अच्छी संख्या में आने लगे और उन सबका प्लेसमेंट भी स्थानीय उद्योगों में आसानी से हो गया। बीते पांच वर्षों से संगठन के कार्यकर्ता आपसी सहयोग से संग्रह की गई घन राशि से करीब ₹25 लाख स्वरोजगार के लिए संचालित इस केंद्र पर खर्च कर चुके हैं।

महिलाओं के लिए कुछसीख कर आगे बढ़ना आसान नहीं-



अहुत सामाजिक कार्यकर्ता और इस पाली मॉडल के सूत्रधारों में से एक श्री ज्ञानचंद पारख मानते हैं कि हमने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी समाज में अधिकांश महिलाओं को काम करने के लिए आसानी से घर से बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जाती। फिर चाहे वो

किसी भी जाति—समुदाय या आय स्तर समूह से सम्बद्ध क्यों न हों। निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में बच्चों की परवरिश और आर्थिक चुनौतियों के कारण ही औरतें घर से बाहर श्रम करने के लिए निकलती हैं। ऐसी स्थिति को समझते हुए उद्यमियों ने पाली में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर बेहतर कार्य स्थितियां (विकेंग कंडीशंस) बनाई, जिससे उनमें फैक्ट्री तक जाने और वहां काम करने के लिए पहले से अधिक आत्मविश्वास पैदा हुआ।

घरों की दहलीज को पार कर सीखा कौशल-

श्री पारख बताते हैं कि इंडस्ट्री के प्रमुख उद्यमी गण विषय की बारीकी को समझते हुए आगे आये और स्थानीय मानव संसाधन को कौशल सिखाने के लिए सहर्ष तैयार हुए। केबी सिन्थेटिक्स के श्री अमरचंद समदिख्या ऐसे ही कुछ बड़े कारोबारियों में शामिल हैं जिन्होंने पाली के आसपास के ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को उनके घरों से फैक्ट्री लाने और शाम को वापस घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुहैया करवानी शुरू की और इसका परिणाम बहुत सार्थक रहा। अच्छी संख्या में महिलाएं घर से बाहर निकल कर सिलाई मशीन तक पहुँच गई। इनकी फैक्ट्री में करीब 600 महिलाएं अपने साथ अपना टिफिन लेकर आती और अलग—अलग तरह की मशीनों पर काम सीखती। महीने भर के लिए उनको 15 हजार रुपये मानदेय भी मिलता। आज वे सिलाई का कौशल सीख कर अब नियमित रूप से यहां काम कर रही हैं।



श्री समदिख्या बताते हैं कि चाइना खासतौर पर पिछले 20 वर्षों में ही डेवलप हुआ है, उसे जाकर देखा। यहां दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर भी देखा। वहां लेडीज काम करती हैं। हमें मालूम था कि पाली में महिलाओं को कारखानों में काम पर लाने में धैर्य और धन दोनों की

जरूरत है। भगवान ने हमें खाने को दिया है, और वो सबको मिलना चाहिए। हमने 18 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए सिलाई की ट्रेनिंग शुरू की। ईएसआई और पीएफ के साथ 15 हजार रु का मानदेय दिया, जो राजस्थान सरकार के मिनिमम वेजेज से अधिक ही है।आने वाले दिनों में कंपनी की 5 हजार मशीन और लगाने की योजना है।



छात्र—जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत संगठनों से प्रेरणा लेकर समाज जीवन में सक्रिय पाली के प्रतिष्ठित उद्यमी श्री प्रमोद लसोड़ ने भी कौशल प्रकल्प में बड़ा योगदान किया।

श्री लसोड़ ने अपनी कंपनी विनायक कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड में पांच सौ से अधिक महिलाओं को अपने संसाघनों से सिलाई का हुनर सिखाकर उन्हें रोजगार भी प्रदान किया।

मशीन और जॉब वर्क दोनों का किया प्रबंधन-

श्री पारख कहते हैं कि यहां की बालिकाओं और ग्रामीण मृहिणयों को जब सिलाई मशीन पर काम करने का कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर टीम का काम ख़त्म नहीं हुआ, बिल्क शुरू हुआ था। टीम के सामने दो ही विकल्प थे पहला — ऐसी सभी स्किल्ड फोर्स के लिए किसी भी कारखाने में नियमित नौकरी का प्रबंध किया जाये या दूसरा— जो महिलाएं रोज अपने घरों से कारखानों में काम करने में संकोच करती थीं या उनके लिए संभव नहीं था और वे अपने घर से ही काम करना चाहती थीं, ऐसी सभी महिलाओं को

दक्षिण भारत के उद्योग हमसे आगे, क्योंकि वहां महिलाएं पुरुषों के साथ काम करती हैं पाली के प्रगतिशील उद्यमी और वीतराग फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री पुखराज लसोड़ बताते हैं कि पाली में सारा कपड़ा बाहर से ही बन कर आता है। पहले



महिलाओं की भूमिका भी कारखानों और प्रोसेस हाउस में बहुत ही सीमित ही होती थी। प्रोसेसिंग में गीला कपड़ा दो से तीन बार बांस पर सुखाना पड़ता था और इस काम को करने के लिए गिनी-चुनी महिलाएं फैक्ट्री एरिया में आती थीं और ये काम काफी सालों से हो रहा था। श्री लसोड़ ने बताया कि दक्षिण भारत में महिलाएं पुरुषों के साथ काम करती हैं, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में महिलाएं बहुत संकोच करती हैं उनके साथ काम करने में। ये भी कारण रहा होगा। लेकिन लघु उद्योग भारती के कौशल प्रकल्प से हम सभी उद्यमी भी उत्साहित हैं। अब बीते दो वर्षों से महिलाएं यहाँ की करीब 50 फैक्टीज में सिलाई के काम के लिए आ रहीं हैं। ये अच्छा संकेत हैं। श्री लसोड़ आगे बताते हैं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में फ्लोर ही अलग से महिलाओं के लिए बना दिया। इस फ्लोर की एंट्री भी अलग, मास्टर भी महिला और मैनेजमेंट में भी महिला ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि काम को बढ़ा तो लें, लेकिन काम करने वाले कुशल लोग अच्छे शहरों में रहना पसंद करते हैं जिससे उनके बच्चों की शिक्षा अच्छे स्कूल, कॉलेज में हो सके। यहां अच्छे एजुकेशन संस्थान नहीं है। वे जब भी दिल्ली, गाजियाबाद और सूरत जैसे

उनके घर पर ही मशीन और रेगुलर जॉब वर्क दोनों का बंदोबस्त किया जाये, ये अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी थी।

शहरों से अनुभवी कार्मिक लाते हैं, तो वे टिकते नहीं।

साड़ी फॉल वर्क में पाली को बनाया नंबर वन -

कौशल की कोर टीम को ये जानकारी मिली कि देशभर में साडी फॉल का सर्वाधिक कार्य महाराष्ट्र के उल्हासनगर में हुआ करता था लम्बे समय से। इसकी कटिंग, सिलाई और



पैकिंग तीनों काम वहीं होते। और इसमें 99 फीसद कार्य मुस्लिम ही करते थे। एक तरह से इस काम पर उनका ही एकाधिकार सा हो गया था। टीम ने पाली में इस काम को स्थापित करने का संकल्प लिया और जापान की निर्मित 3 हजार मशीनें केवल फॉल लगाने के काम के लिए झोंक दी गई। आज परिणाम सबके सामने है, साड़ी फॉल का सारा काम यहीं पाली में संपन्न होने लगा। आरको, मैजिक, मोती पीको, समोसा जैसी स्पेशलाइज्ड वर्क की मशीनों पर 6सौ—7सी महिलाएं प्रशिक्षित हो गई हैं और काम इतना है कि समय पर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसलिए इन



अमेरिकन मशीनों को और अधिक संख्या में मंगाने की योजना बन रही है। इसी तरह जम्बो सेटल जैसी मशीनें भी भिवंडी से मंगवाई गईं जिससे शोल्डर (स्कूल बैग और लैपटोंप) बैग भी बनते हैं। ये काम भी पहले अधिकांशतः मुसलमानों के ही हिस्से में था।

मिला सतत मार्गदर्शन और भविष्य की दृष्टि-

स्थानीय उद्यमी और लघु उद्योग भारती के प्रदेश संयुक्त सिचव श्री विनय बंब बताते हैं कि पाली के इस कौशल प्रकल्प के बारे में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी समय—समय पर मार्गदर्शन करते



हैं। पाली-मारवाड़ क्षेत्र के लोगों के साथ उनका गहरा जुड़ाव रहा है, क्योंकि यहां वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रह चुके थे। उनकी दूरदर्शिता के साथ प्रकल्प भी आकार ले रहा है।



श्री प्रकाश चंद्र जी का मानना है कि कौशल ही विकास की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे कौशल को ही ख़ल्म किया था और वही परिस्थिति आज भी है कि बिना कौशल (स्किल्ड मैन पावर) हमारे उद्योग कैसे विश्व की प्रतिस्पर्धा में

खड़े रह सकते हैं? चीन को केवल कोसने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और सिर्फ सरकार के भरोसे कौशल विकास का बड़ा भी कार्य संभव नहीं। हमें अपने संसाधनों से, अपने समाज के लोगों को कौशल सिखा कर, अपने उद्योगों और



लघु उद्योग भारती, पाली द्वारा संचालित कौशल केंद्र का अवलोकन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मान्य श्री (डॉ.) कृष्ण गोपाल जी के साथ लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी आर्थिक रूप से पिछड़े समाज बंधुओं को संजीवनी देने का ये प्रकल्प और तेज करना होगा।

पाली प्रकल्प का किया प्रत्यक्ष दर्शन और अध्ययन

पाली के कौशल विकास प्रकल्प की पर्याप्त ख्याति फैलने के बाद उसका प्रत्यक्ष दर्शन, अध्ययन और अनुभव करने के लिए देशभर से प्रबुद्ध व्यक्तित्व पाली आये। इन विशिष्ट जन में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी श्री अजय पारीक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख श्री भारत भूषण जी, वरिष्ठ प्रचारक श्री दुर्गादास जी, राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम जी, श्रीवर्धन जी, जाने—माने चिंतक और शिक्षाविद डॉ. भगवती प्रकाश जी, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संघटक श्री सतीश कुमार जी, लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव भाई प्रजापति एवं श्री जितेंद्र गुप्त भी सम्मिलित हैं। इसके साथ ही उद्यमिता और कौशल पर शोध करने वाले स्कॉलर्स भी केस स्टडी के तौर पर पाली मॉडल को समझने के लिए यहां आते रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख श्री राजकुमार मताले भी मानते हैं कि देशभर में कौशल के लिए प्रशिक्षण तो कई जगह चलते हैं, लेकिन उन्हें जॉब प्रदान करने का काम केवल पाली में ही हो रहा है।



कौशल का प्रेरक प्रकल्प है 'पाली मॉडल'

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा भी मानते हैं कि कौशल विकास के क्षेत्र में राजस्थान का 'पाली मॉडल' निश्चित रूप से प्रेरणादायी है जो संसाधनों के कुशल प्रबंधन, अपेक्षित वर्ग की सक्रिय सहभागिता और उनके समुचित प्रशिक्षण एवं



स्वरोजगार और स्वावलम्बन का सुन्दर समन्वय है। श्री ओझा के अनुसार देश में तीव्र कौशल विकास की दरकार है और इसके लिए सभी अग्रणी औद्योगिक क्षेत्रों में 'पाली मॉडल' को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि तकनीक और कौशल की जुगलबंदी से सबसे बड़ा लाभ आख़िरकार उद्योगों को ही मिलना है।

'पाली मॉडल'की सफलता की कहानी

जिसको भी पाली की कौशल-कहानी के बारे में पता चलता है, तो स्वाभाविक है कि वो पूछता है कि आखिर 'पाली मॉडल' है क्या चीज? बहुत आसानी से नीचे दिए हुए पॉइंट्स से समझते हैं इसे।

- स्थानीय उत्पाद को काँशल से लिंक करना- पाली में लगभग 800 टैक्सटाइल प्रोसेसिंग इकाइयां हैं एवं लगभग ढाई हजार मैन्युफैक्चरर हैं। इसमें से कुछ अपनी फैक्ट्री में माल तैयार करके बाहर भेजते हैं एवं कुछ जॉब वर्क करवाते हैं। पाली में पिछले 6-7 साल में यहां पर सलवार-सूट, साड़ी फॉल, लेडीज ब्लाउज, कपड़ों के भीतर लगने वाले अस्तर, सरदारों की पगड़ी, दुपट्टे की सिलाई का कार्य बड़े पैमाने पर पहुँच गया है। पाली में बनने वाला अधिकांश माल पूरे भारत के मार्केट में जाता है। इसके अतिरिक्त नेपाल और साउध अफ्रीका में भी कुछ कपड़ा जाता है, लेकिन पाली से सीधा एक्सपोर्ट तो नहीं के बराबर है। यहां उद्योगों को कपड़ा सिलाई कौशल की जरूरत थी।
- नि:शुल्क कौशल कार्यक्रम से जरूरतमंद को लिंक करना-पाली के 30 से 60 किलोमीटर के दायरे में निम्न आय वर्ग के जरूरत वाले परिवारों को चिन्हित किया गया। और उन्हें निकटवर्ती कौशल केंद्र लाया गया या उनके आसपास अस्थाई केंद्र बनाकर उन्हें कौशल प्रदान किया। उद्यमियों से सिलाई कौशल में पारंगत महिलाओं को घर पर करने के लिए जॉब मिल गया। और जो फैक्ट्री

में जाकर काम कर सकती थीं, उन्होंने नौकरी कर ली।

- लाभार्थी को कौनसी मशीन वर्किंग के लिए दी जाती है?
 सिलाई प्रकल्प में 9 तरह की सिलाई करने के लिए प्रमुख रूप से 4 देशों— जापान, चीन, अमेरिका और वियतनाम से 7 कंपनियों की मशीनें खरीदीं गईं। चीन की जिमेक्स कम्पनी की मशीन सामान्य सिलाई, जापान की ब्रोदर कंपनी की मशीन साड़ी फॉल के लिए, ताइवान और चीन की जैक मशीन सिलाई, जंबोशटल बैग सिलाई और वॉकिंग फुट के लिए, ताइवान और चीन की मैसी मशीन जूते, लेदर और पीकू वर्क के लिए, चीन की लुकी मशीन इंटरलॉक, मैजिक, पीकू आरकों के लिए, अमेरिका की यूनियन स्पेशल आरकों के लिए और चीन की जुकी मशीन सिलाई, जंबोशटल बैग सिलाई और इंटरलॉक के लिए काम में आती हैं।
 - ये मशीनें 19 हजार से लेकर सवा लाख रुपये की कीमत की हैं। साड़ी फॉल के लिए जापान की ब्रोदर कंपनी की 2700 मशीनें खरीदीं गई। ये सेकंड हैंड ही होती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलती है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की 3000 मशीनें ब्रांड न्यू खरीदी गईं। इन सबमें सामान्य सिलाई के लिए जिमेक्स कंपनी का मॉडल सबसे ज्यादा लोग काम में लेते हैं और आजकल उसकी कीमत करीब 19 हजार रुपए है।
- लाभार्थी को कितनी किस्तों में मशीन की रकम जमा करनी होती है?

सामान्य सिलाई मशीनों में 3000 एडवांस एवं 700 की 20



किस्त रखी गई थी। लेकिन मशीन की कीमत में अंतर के आधार पर किस्त की राशि अलग भी हो जाती है। और उसको जमा करने का कुल समय भी। समय पर पूरी किस्तें जमा करवाने पर अंतिम किस्त को माफ भी कर दिया जाता है। अर्थात ये किस्त लामार्थी को प्रोत्साहन (इंसेंटिव) के रूप में प्रदान कर दी जाती है।

लाभार्थी तो किस्तों में मशीन खरीदता है, तो फिर वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कौन करता है?

पाली की कौशल विकास टीम ने लाभार्थियों को मशीन उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी भामाशाह से कोई दान या चंदे की राशि नहीं ली। हालांकि बहुत से स्थानीय उद्यमी इसमें धनराशि देना चाहते थे। मशीनों को खरीदने के लिए अच्छी-खासी रकम की भी जरूरत तो थी ही, जिससे मशीनों की खरीद में कभी विलम्ब न हो। तो उसके लिए एक अलग फार्मुला निकाल कर तय किया गया कि अधिकांश धनराशि कुछ निश्चित समय के लिए बिना ब्याज के ऋण के रूप में ली जाये। और फिर लाभार्थियों की चुकाई गई किस्तों से ये सायकल चलता रहे। देसी या विदेशी सभी सिलाई मशीनों की खरीद में लगने वाले धन (वर्किंग कैपिटल) की व्यवस्था श्री ज्ञान चंद पारख अपने परिवार और निकट के सगे-संबंधियों से ही करते हैं। जहाँ तक लाभार्थियों की ट्रेनिंग और अन्य मदों के खर्चों का सवाल है, तो उसके लिए सीधी व्यवस्था कुछ समाजसेवी अवश्य करते हैं, लेकिन उनसे भी कोई पैसा कैश में नहीं लिया जाता।

• लाभार्थी महिलाएं किस तरह का जॉब वर्क करती है-

इसमें सलवार-कुर्ती की सिलाई, साड़ी फॉल, गमछे, दुपट्टे एवं दुपट्टों पर विभिन्न प्रकार का कार्य, पीकू, बैग सिलाई जैसे अनेक सिलाई कार्य होते हैं इस जॉब वर्क से तैयार माल (फिनिश्ड गुड्स) लोकल, डोमेस्टिक रिटेल मार्केट में जाता है, या सीमित मात्रा में एक्सपोर्ट भी होता है।

प्रकल्प से जुड़ने के लिए क्या औपचारिकता है?

किसी भी लाभार्थी महिला को अगर प्रशिक्षण के बाद मशीन स्वरोजगार के लिए चाहिए, तो इसके लिए निर्धारित फॉर्म और स्टांप—पेपर पर शपथ—पत्र (एफिडेविट) भरना होता है किसी स्थानीय व्यक्ति की गारंटी के साथ। किस्तों पूरी नहीं हो, तब तक मशीन का मालिकाना हक लाभार्थी का नहीं रहेगा।

कुल कितनी लाभार्थी इस सिलाई प्रकल्प से जुड़ी हैं और उनकी औसत आय कितनी है ?

करीब 5700 मशीन लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई गई हैं और ये जॉब वर्क करती हैं। इनकी औसत आय 15 से 25 हजार मासिक है। परंतु ऐसी अनेक महिलाएं हैं, जिनकी अच्छी आय के कारण उन्होंने और मशीन खरीदी और वे मोहल्ले की अन्य महिलाओं और बालिकाओं को भी प्रशिक्षण भी देती हैं सिलाई के इस पूरे प्रकल्प से करीब दस हजार महिलाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडी हुई हैं।

• प्रकल्प की उपलब्धि

- लाभार्थी महिलाओं में कुछ ने 5 से 30-40 मशीन तक खरीद कर अपने 'खाते' (छोटे कारखाने) तैयार कर लिए हैं और नियोक्ता के रूप में अन्य महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही हैं।
- राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग ने एक लाख कैरी बैग इसी केंद्र से बनवाये।
- कई बार मॉल और बड़े मार्केट वालों ने थैली सिलाई के लिए एवं अन्य कई ब्रांड ने भी यहां कार्य करवाया है।
- प्रशिक्षित महिलाओं में से किसी ने अपना ब्रांड तो अभी नहीं खड़ा किया, परंतु छोटे—छोटे काम घरों में करके उनको मार्केट तक पहुँचाने का काम काफी महिलाएं करती हैं और अधिकांश महिलाएं पाली में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जॉब करती हैं।

सफलता की कहानी

पाली की हरेक बेटी को मास्टर बनाना है- हिना राजपुरोहित



करीब 8 वर्ष पहले ग्रेजुएट और कंप्यूटर में पीजीडीसीए कोर्स करने के बाद पाली की बेटी हिना ने स्थानीय युवितयों को कौशल से जोड़ने के लिए बहुत उत्साह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का केंद्र शुरू किया। पहले बैच की 30 युवितयों को 8 महीने में सिलाई

का कौर्स सिखाना था, लेकिन तीन महीने बाद तक ट्रेनिंग के लिए कोई फंड नहीं मिला। न उनके लिए कोई सर्टिफिकेशन की व्यवस्था ही थी। सवाल ये था कि आगे इसको जारी कैसे रखें। तभी किराने की थैली बनाने का ऑर्डर मिला। थोड़ी-सी इनकम हुई सभी को। तो पेरेंट्स ने अपनी बेटियों को भेजना जारी रखा। इसी दौरान लघ् उद्योग भारती की टीम के संपर्क में आई और यहीं से हिना की कौशल की नई यात्रा शुरू हुई। यहां से जुड़ने के बाद हिना ने 2 स्थानों पर करीब 35 मशीन खुद की लगा रखीं हैं जहां 250 महिलाएं काम करती हैं, और उन सभी को 15 से 20 हजार रुपए की मासिक आमदनी हो जाती है। इसके साथ ही कौशल सिखाने के लिए भंसाली गवर्नमेंट कॉलेज में 15 मशीनें और लगा रखी है, जहां 30 महिलाओं से अधिक सिलाई सीखती हैं। हिना बताती हैं कि काम की कोई कमी नहीं है यहां, बस करने वाला चाहिए। आज जब भी मशीन की जरूरत होती है, ज्ञानजी भाईसाब से ले आते हैं, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। आत्मविश्वास से लबरेज हिना कहती हैं कि उन्हें मशीन खरीदने के लिए गारंटर की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब वे खुद अन्य महिलाओं को मशीन खरीदवाने के लिए गारंटर बनती हैं।

हिना अपने कारखाने में सलवार—सूट, रोटी के रुमाल, नैपिकन, हैंड टॉवल, एप्रन, पिलो कवर, बेडशीट के इलास्टिक लगाने, ट्रैंबलिंग और फोल्डिंग बैग की सिलाई का कार्य करती हैं और लोकल एग्जीबिशन में हिस्सा भी लेती है। हिना का कहना है कि यहां की फैक्ट्री में हर दस मशीन पर एक मास्टर होता है जिसे औसतन करीब 40 हजार मासिक वेतन मिलता है। जबिक मशीनों पर काम करने वाली महिलाओं को अधिकतम 15 हजार ही। इसलिए उसकी कोशिश होगी कि उसके सेंटर से सिलाई सीखने वाली पाली की हरेक बेटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मास्टर बने।

सफलता की कहानी

लघु उद्योग भारती की टोली ने बदली लोगों की सोच-सुमनसैन



डबल एमए और बीएड की डिग्री करने के बाद भी पाली की बेटी सुमन सैन ने किसी सरकारी नौकरी की बजाय स्थानीय लड़कियों को कौशल सिखाने में जुट गई। वो 20 वर्षों से विविध कौशल से जुड़ी हुई हैं और अपने घर से ही पार्लर, मेहंदी और सिलाई का कार्य सिखाने लगी

थी। अपनी निजी संस्था बनाकर सुमन ने स्वावलंबन के कार्य

को आगे बढ़ाया। पाली के चार ट्रेनिंग सेंटर में वह हेड ट्रेनर के तौर पर काम कर रही हैं।

सुमन बताती हैं कि पहले सिलाई के लिए 90 दिनों की ट्रेनिंग करनी होती थी और उसके लिए भी वे कोई शुक्क नहीं लेती थी। मशीन हमारी होती थी और सीखने वाले को अपने साथ कपड़ा और धागा जरूर लाना पड़ता था। ये उस समय की बात है जब पाली की महिलाएं फैक्ट्री में काम करने नहीं जाती थीं। इसका कोई ठोस कारण उन्हें तो कहीं नहीं नजर आता। शायद संकोच और सुरक्षा का सवाल हो सकता है। लेकिन जब से लघु उद्योग भारती ने टोली बनाकर घर—घर संपर्क किया, तो लोगों ने सोच बदली और पिछले कई सालों के प्रयासों में वो अब फैक्ट्री भी जाने लगी है और अच्छी संख्या में।

क्या है भविष्य की योजना

- लघु उद्योग भारती द्वारा रीको से जमीन मिलने पर शीघ्र ही खुद का स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने की योजना है।
- लघु उद्योग भारती के डिजिटल प्लेटफार्म के बारे में भी चर्चा चल रही है जिससे आने वाले दिनों में पोर्टल के माध्यम से यहां के स्किल्ड मैनपॉवर के लिए ऑनलाइन जॉब बुक किया जा सकेगा।

सिलाई प्रकल्प में विशेष सहयोगी जन



सिलाई से सशक्तिकरण के प्रकल्प में आर्थिक अंशदान करने वाली श्रीमती शिवानी कोठारी स्वयं सफल उद्यमी हैं और जयपुर, राजकोट जैसे कई शहरों में अपना ज्वैलरी उद्योग संचालित करती हैं। वे मानती हैं कि महिलाएं कमजोर नहीं होती, बस उन्हें

उचित अवसर, समर्थन और सम्मान चाहिए।

इसी तरह पाली की श्रीमती लीना मेहता भी बिजनेस घराने

से सम्बद्ध हैं और वर्तमान में ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (यूएई) की मेट्रोपोलिटन सिटी शारजाह में रहती हैं। इन दोनों सहयोगियों की खास बात ये है कि ये सामाजिक उत्थान में हमेशा सहभागी और तत्पर रहती हैं और ये दोनों बहनें पाली के विधायक श्री ज्ञान चंद पारख के परिवार की सदस्य ही हैं।





पाली में कौशल विकास का काम शुरू जरूर लघु उद्योग मारती की पहल पर हुआ था, लेकिन ये कार्य बहुत बड़ा था इसलिए सभी समाजों के लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया और इसी का सुफल था वृद्ध आश्रम का संचालन करने वाली संस्था सेवा समिति के श्री प्रमोद जैथलिया भी

समर्पित भाव से कौशल के सभी प्रकल्पों से जुड़े। करीब एक हजार से अधिक बालिकाओं को समिति ने अपने प्रशिक्षक और मशीनों से प्रशिक्षित किया।

इसी तरह रोटरी क्लब पाली के अध्यक्ष श्री राजकुमार मेड़ितया के नाम का उल्लेख भी यहां आवश्यक है जो वर्ष में एक बार सिलाई प्रकल्प शिविर के आयोजन में प्रशिक्षण और अन्य सभी प्रबंधन में आर्थिक सहयोग करते हैं।



सिलाई प्रकल्प में विशेष सहयोगी

पाली की कोर टीम के अतिरिक्त कुछ और भी सहयोगी हैं जिन्होंने इस प्रकल्प को गतिशील बनाने में सहयोग किया है। इनमें स्वावलंबी भारत अभियान टीम के सदस्य श्री केसरीमल छाजेड़, लघु उद्योग भारती के जोधपुर अंचल के संयुक्त सचिव श्री राहुल मेहता एवं कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती नेहा मेहता, एलयूबी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री संदीप मेहता, श्री महेंद्र तातेड़, श्री संपत सकलेचा, श्री निलेश सेमलानी, श्री राजेश चौधरी, श्री महावीर चोपड़ा, श्री वरुण सिंघल, श्री लिलत मालू, श्री संदीप लसोड, श्री नरेंद्र गोलछा, श्री अंकित भंसाली, श्री विकास श्रीमाल, श्री वीरेंद्र बाहेती, श्री लालचंद लसोड, लघु उद्योग भारती महिला इकाई पाली की अध्यक्ष श्रीमती भारती गुप्ता, श्रीमती शीतल दाधीच, श्रीमती आशा भूतड़ा, श्रीमती अंजना सराफ, श्रीमती रेनू बम्ब, श्रीमती खुशबू दुबे एवं कार्यालय सहायक श्री रमेश बंजारा शामिल हैं।

पाली में जितना पोटेंशियल है, उतना परफॉर्मेंस क्यों नहीं नजर आता?

कहते हैं कि पाली के पानी में ही वो तासीर है जिसने वहां के बाशिंदों के भीतर उद्यमिता के बीज बो दिए। इसीलिए व्यापार—वाणिज्य में पाली का सदियों पुराना इतिहास रहा है। लेकिन पाली के आधुनिक औद्योगिक परिदृश्य की शुरुआत बांगड़ घराने की महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड से मान



सकते हैं। वर्ष 1918 में स्थापित इन मिलों को महाराजा उम्मेद द्वारा विश्व में अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन कॉटन का उत्पादन करने के लिए कमीशन किया गया था। साधारण शुरुआत ने जल्द ही विकास और रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया और 12 अगस्त 1939 को यह एक सार्वजनिक निगमित कंपनी बन गई थी लेकिन अब वो सब इतिहास बन कर रह गया है।

वास्तव में पाली के लोगों में इस बात की गहरी टीस है कि बड़ी संख्या में पाली के प्रवासी उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही पाली वस्त्र उद्योग का बड़ा हब बन चुका है, लेकिन उस हिसाब से इसका विकास नहीं हो सका। हालांकि भारत सरकार ने एनआईसीडीपी के अंतर्गत जोधपुर—पाली के एकीकृत विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया है जिससे देश के औद्योगिक परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करने और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए पाली भी पूरी तरह तैयार हो सके।

राजस्थान टैक्सटाइल हैंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन, पाली के



अध्यक्ष श्री विनय बंब के अनुसार पाली के प्रवासी दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रहते हैं। डायमंड, गोल्ड और अन्य कई उद्यमों में इनका प्रमुख स्थान हैं। कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने ऐसे ही प्रवासियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए चलाया है। लेकिन

लघु उद्योगों पर सरकार का फोकस कम है। सरकारें बदलती हैं, लेकिन अफसरों का अंदाज वही रहता है। वो नहीं बदलते।

- राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद रीको डायरेक्ट जमीन का अलॉटमेंट कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन नए व्यापार को जमाने में समय लगता है। इसलिए अलॉटमेंट के बाद केवल 2 वर्षों में बिजनेस को प्रोडक्शन में लाना संभव नहीं है।
- स्थानीय स्तर पर एनओसी देने के लिए डीआईसी के लोगों को ही अधिकार दिए जाएँ। इसके लिए उद्यमी और कहीं चक्कर क्यों लगाए।
- उद्योगों के लिए जमीन के मामले में अधिकारी खुद कई गुल्थियों में उलझे रहते हैं। लेकिन उद्यमियों की छवि खराब करने का काम करते हैं और उन्हें जमीनखोर साबित करने की कोशिश करते हैं।
- आज ओडीओपी की बात हो रही है हर तरफ। लेकिन पाली इतना बड़ा प्रोसेस हब होने के बावजूद यहां सारा का सारा कपड़ा बाहर से ही आ रहा है जिसमें महाराष्ट्र के भिवंडी, मालेगांव और इछलकरंजी, तमिलनाडु के तिरुपुर और सेलम के साथ मध्यप्रदेश का बुरहानपुर और गुजरात के सूरत का नाम खासतौर पर लिया जा सकता है। आखिर: पाली में ये कपड़ा क्यों नहीं बन रहा? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं करना चाहता। यहां कपड़ा बनने के लिए तीन चीजें चाहिए-यार्न, लेबर और बिजली। पहली दो में भी कई तकनीकी पेंच हैं, लेकिन तीसरी अर्थात बिजली की दर में सारा झमेला है। महाराष्ट्र में 3 से 4 रुपये प्रति युनिट खर्च आता है, तो राजस्थान में यही 11 से 12 रूपए तक चला

जाता है। ये बिजली ही सारा गणित बिगाड देती है।

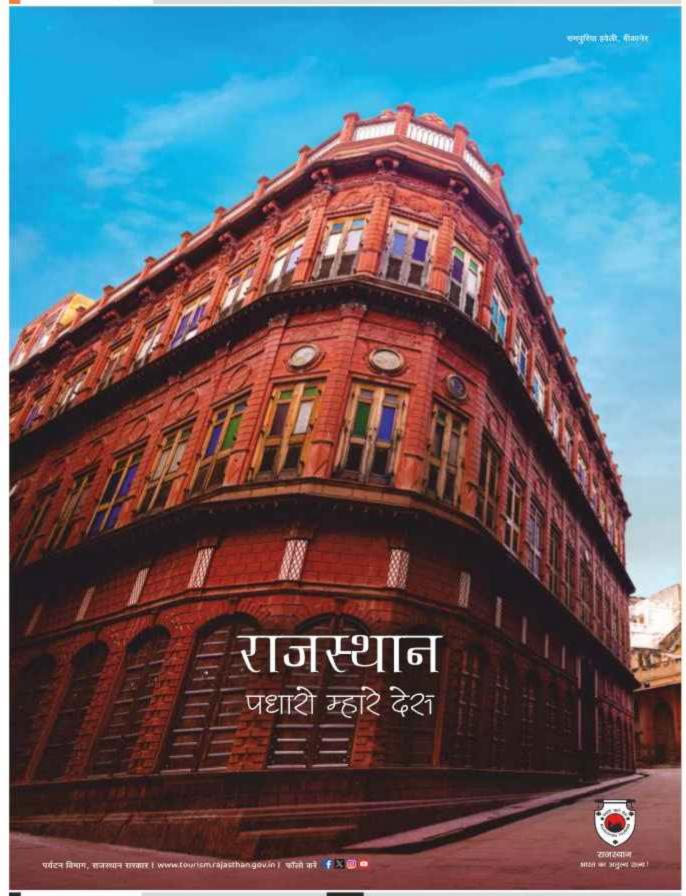
• बाली आदिवासी बेल्ट है अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई। यहां स्वादिष्ट सीताफल बहुतायत में होता है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यनिट नहीं होने के कारण काफी कम कीमत पर बेचना पडता है। इसलिए यहां के स्थानीय आदिवासियों आर्थिक सशक्तिकरण

लिए सीताफल के पल्प को प्रोसेस करने के लिए सरकार के माध्यम से ये प्रयास होना चाहिए।

- पाली में ड्राई वातावरण है, इसलिए यहाँ के खाखरा, पापड़, बड़ी, साबुन, शरबत, नमकीन, चूर्ण, सूखे आवंले आदि उत्पाद का उत्पादन अच्छी प्रकार हो सकता है।
- प्रदेश में सोलर से उत्पादन में कैप्टिव सीमा 200 प्रतिशत कर दी गई है, लेकिन जो सरप्लस पावर है, सरकार उसकी खरीद भी सुनिश्चित करे। समायोजित करे या बिलिंग में एडजस्ट करे।
- इसी तरह से पॉल्यूशन की बात है। पाली में सीईपीटी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) के संचालन के लिए अभी तक इंडस्ट्री सीधे तौर पर उत्तरदायी है। इंडस्ट्री एसोसिएशन की कमेटी ही इसे मॉनिटर करती है। जबकि ये कार्य किसी टेक्निकल एजेंसी से कराने की जरूरत है या सरकार खुद इसे करे। यानी अपनी एजेंसी रीको या डीआईसी के माध्यम से कराये।
- देशभर में वाटर ट्रीटमेंट के बारे में समान नीति (युनिफार्म पॉलिसी) बननी चाहिए। क्योंकि जहाँ नदियों, खाड़ी और समुद्र में ऐसे जल को रेस्क्यू किया जाता है, वहां की कॉस्टिंग में काफी अंतर होता है, जिसका असर प्रोडक्शन कॉस्ट पर भी आता है।
- सरकार स्किल सेंटर स्थापित कर स्थानीय लोगों को स्किल्ड करने का कार्य करे। स्किल के नाम पर सरकार का पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन स्किल्ड लोग नजर नहीं आते।









स्वावलंबन का संकल्प पाली का चूड़ी प्रकल्प

पाली अंचल में करीब 50 हजार महिलाएं चूड़ी पर नगीने लगाने का काम करती हैं। वर्ष 2020 तक पाली जिले में हिन्दू परिवारों की 60 और मुस्लिमों की 250 चूड़ी बनाने की इकाइयां थीं। लेकिन लघु उद्योग भारती के चूड़ी प्रकल्प की बदौलत आज हिन्दुओं की 650 चूड़ी यूनिट्स बन गई हैं।

चूड़ी उद्योग से न केवल महिलाओं को आर्थिक सम्बल मिला, बल्कि समावेशी समाज के निर्माण में भी बड़ी सफलता हासिल हुई है।

आत्मनिर्भर भारत @ पाली

चूड़ीगरों के हाथों में था चूड़ी उद्योग

सिलाई कौशल प्रकल्प के बाद पाली में अगर सबसे अधिक हलचल कहीं हुई है, तो वो है यहां का चूड़ी उद्योग। हालांकि चूड़ी उद्योग कोई आज का नहीं है, यहां मुसलमानों की चूड़ीगर बिरादरी इस घंघे में कई पीढ़ियों से लगी हुई है जो पैसे वाली कम्युनिटी मानी जाती है। जिसने करीब सौ साल पहले नारियल के खोल से चूड़ियां बनाना शुरू किया। और उसके बाद हाथी दांत की चूड़ियां भी बनने लगीं। हाथी दांत की चूड़ियां बेहद महंगी होती थीं, जो आम आवाम की पहुँच से बाहर की बात थी। इन चूड़ियों को राजे—महाराजे और बड़े सेठ—साहूकारों के घरानों की औरतें स्पेशल ऑर्डर पर बनवाती थीं। उस जमाने में ये रईस परिवारों में गिफ्ट यानी उपहार के रूप में भी दी जाती रही।

लेकिन आजादी से बाद हाथी दांत को इस कार्य में काम लेने पर प्रतिबंद लगा दिया गया। और फिर 1960 के दशक में प्लास्टिक दाने से बनी प्लेन चूड़ियों का चलन बढ़ गया। करीब 40-50 वर्षों तक प्लास्टिक की चूड़ियां ही यहां बनती रही।





पाली में बैंगल्स के प्रमुख व्यापारी और लघु उद्योग भारती के चूड़ी प्रकल्प के समन्वयक श्री नरपत सिंह सोलंकी बताते हैं कि वर्ष 2000 से प्लास्टिक की चूड़ियों पर लाख और उस पर नगीने लगाने का काम शुरू हुआ। ये यहां के चूड़ी उद्योग के

लिए टर्निंग पॉइंट था। अनेक रंगों और वैराइटी में उपलब्ध ये चूड़ियां महिलाओं में इतनी लोकप्रिय हुईं कि चूड़ी उद्योग में पाली और आसपास के गांवों के सँकड़ों परिवारों की अनुमानित 50 हजार महिलाएं अपने घरों से चूड़ियों पर नगीने लगाने का कार्य करने लगीं। लेकिन इस व्यापार पर पकड़ अधिकांश मुस्लिम समुदाय की ही बनी रही।

तकनीक ने बदली चूड़ी उद्योग की तस्वीर

तकनीक ने इस चूड़ी उद्योग को बदल कर रख दिया है।



चूड़ी काटते हुए कारीगर

पहले चूड़ी पर नगीने लगाने के लिए श्रम और समय दोनों अधिक लगता था। हाथ से लाइन बनाने का काम किया जाता था और आँखों पर भी बहुत अधिक जोर पड़ता था। इसी बात से परेशान होकर दो मुस्लिम व्यापारियों ने चीन से इसी काम के लिए मशीन खरीदी, जिसकी कीमत उस

समय 1.75 लाख रुपए थी। मशीन बहुत महंगी होने के बावजूद नगीने लगाने में कारगर साबित नहीं हो सकी।



तब लघु उद्योग भारती की टीम ने यहां स्थानीय मैंकेनिक श्री हंमराज मालवीय लोहार से वैक्यूम आधारित एक मशीन तैयार करवाई जिसकी कुल कीमत 51000 रुपए रखी गई, जो कि चाइनीज मशीन से बहुत सस्ती और उपयोगी सिद्ध हुई। आप केवल इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथों से जिस काम में

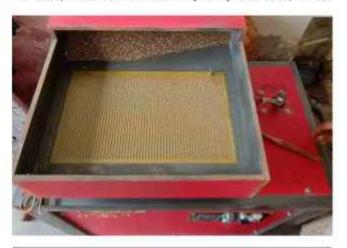
पहले 35 मिनट लगते थे, वहीं काम अब सिर्फ 35 सेकेण्ड में हो जाता है इस नवीन मशीन से। एक मशीन पर एक साथ दस से पंद्रह महिलाएं काम कर सकती हैं।

चूड़ी उद्योग का अर्थशास्त्र



चूड़ी पर नगीने लगाती महिलाएं

चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए सरकार ने इसे जीएसटी से मुक्त रखा। लेकिन इसके सभी रॉ मटेरियल पर जीएसटी लगता है। केमिकल पर 18%, स्क्रंप पर 18%, नगीनों पर 5%, कुंदन पर 5%, चूड़ी बॉक्स पर 18%, पाइप पर 18%, लाख भरने का मसाला ऐरोलाइट पर 18%, की दर



नगीने लगाने के लिए मशीन प्लास्टिक डाई में 60 लाइन 20—25 सेकेण्ड में बना देती हैं जिसे मार्बल या ग्रेनाइट के एक गुणा एक फीट के टुकड़े पर निकाल लिया जाता है जिससे करीब 70 चूड़ियां एक बार में तैयार हो जाती है। इसी तरह एक बार में 250 से 300 चूड़ियों पर नगीने चिपकाने के लिए ऐरोलाइट लगाया जाता है, जिस पर करीब आधे घंटे के भीतर नगीने लगाने पडते हैं।

से जीएसटी लगता है।

चूड़ी बनाने की फैक्ट्री केवल पाली में हैं लेकिन उस पर नगीने लगाने का काम पूरे पाली जिले भर में कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाता है। एक चूड़ी पर नगीने लगाने के लिए 40 पैसा मिलता है। इसमें नगीने को चिपकाने के लिए जो गम लगता है, उसकी कॉस्ट नगीने लगाने वाले के हिस्से में आती है। नगीना अभी केवल चीन से ही आयात होता है, इसका



मशीन से नगीनों की लगी हुई लाइन

विकल्प यहां के उद्यमी अभी खोज रहे हैं। मैन्युफक्यरर्स केवल चूड़ी और नगीना ये दोनों ही नगीने लगाने वालों के घरों तक पहुंचाते हैं और तैयार चूड़ियां वहां से मंगवा लेते हैं। नगीनों को लाइन में लगाने के लिए मशीन को कुछ सेकंड्स के लिए चलाना पड़ता है, उस दौरान बहुत ही मामूली—सी बिजली खर्च होती है। कई घरों में एक से अधिक मशीनों पर भी कार्य हो रहा है जहां कई अन्य महिलाओं को इस काम में लगाया जाता है, ऐसी जगहों पर 35 पैसा एक चूड़ी के लिए महिलाओं दो देकर खुद मशीन मालिक 5 पैसा प्रति चूड़ी का अपने पास रखता है। वैसे तो 5 पैसा बहुत कम प्रतीत होता है, लेकिन चूड़ियां यहाँ से वॉल्यूम में बनती है।

चूड़ी उद्योग का 'पाली मॉडल'



पाली के इंडस्ट्रियल एरिया में चूड़ी के लिए कई रंगों में पाइप तैयार करते हुए

कौशल टीम ने हिन्दू व्यवसायियों की बैठक ली। आसपास के गावों और बस्तियों में भी मशीन का डेमो दिया और महीने भर के लिए 7-8 स्थानों पर मशीन रखवा दीं ये कहकर कि काम नहीं चलने पर वे मशीन वापस दे सकते हैं और इस अवधि के लिए उनसे कोई शुल्क भी नहीं लिया जायेगा। इस पहल से बहुत से नए परिवार भी इस उद्योग से जुड़े।

पाली की कौशल टीम ने सिलाई मशीन की तरह चूड़ी पर नगीने लगाने वाली मशीन को भी मासिक किस्तों पर उपलब्ध करवाना शुरू किया। इस उद्योग से जुड़ने वाले किसी लाभार्थी को मशीन 11 हजार रुपए एडवांस के साथ 2 हजार रुपए की 20 किस्तों में दी जाती हैं। सिलाई की मशीन से नगीने लगाने की ये मशीन अपेक्षाकृत कुछ महंगी है। करोड़ों रुपए की बिना ब्याज की वर्किंग कैंपिटल इस प्रकल्प के लिए लग चुकी है जिसका प्रबंधन पूर्व विधायक श्री ज्ञानचंद पारख के करीबी परिवारजनों ने ही किया। लेकिन बात यहां केवल पैसे के प्रबंधन तक सीमित नहीं, पैसा लगाने वाले समाज से और लोग भी खड़े हो सकते हैं। पूर्व विधायक श्री पारख की रोजगार सृजन के नए विषयों की खोज—खबर लेने, उसका अध्ययन करने से लेकर, कम कीमत में तकनीकी रूप से बेहतर मशीन कैसे बन सकती है, और उस मशीन को बनाने के लिए भी आवश्यक मशीनों की किफायती खरीद में भी उनकी अहम भूमिका रही है।

अभी तक 737 मशीन इस कार्य के लिए किस्तों पर दे दी गई हैं। इस तरह से 8-9 हजार महिलाओं को इन मशीनों से सीधे रोजगार मिलता है। पहले जो महिला दिन में 100 से 150 रुपए प्रतिदिन की आय अर्जित करती थी, वही आज रू 500 से लेकर रू1500 प्रतिदिन तक कर रही है। इससे पाली के आसपास के गांवों में भी रोजगार का एक बहुत बड़ा कार्य खड़ा हो गया। पाली से महज 8 किलोमीटर दूरी पर हेमावास गाँव में 300 मशीने लगी हैं यानी लगभग हर घर पर एक मशीन।

सफलता की कहानी



चूड़ी उद्योग की आइकॉन मजला बंजारा

पाली के नया गांव की श्रीमती मजला बंजारा ने भी बाकी औरतों की तरह नगीने लगाने की मशीन किस्तों में ली। उसने महीने की निर्धारित किस्त एक हजार रुपए जमा कराये। लेकिन

जब दूसरा महीना खत्म होने के बाद वो किस्त जमा करने के लिए आई, तो उसने बाकी बचे 17 हजार रुपए एक साथ पूर्व विधायक श्री पारख को गिना दिए, तो वो अवाक रह गए। उन्होंने पूछा कि वो एक साथ शेष सारी किस्त कैसे जमा करा रही है? तब उसने बताया कि उसने इस मशीन से एक माह में एक लाख रुपये से अधिक की कमाई की है। उसने बताया कि उसके अलावा उसके अपने बेटे और बेटी ने स्कूल के समय के बाद में नगीने लगाने के काम में उसकी मदद की। और इस तरह उसने रिकॉर्ड टाइम में मशीन की पूरी कीमत



चुका दी। मजला ने साबित कर दिया कि कोई काम छोटा नहीं होता, उसे देखने का नजरिया ही छोटा होता है।

अपने इरादों से पहचान बनाई इंदिराकँबरने

सोजत रोड़ की रहने वाली इंदिरा

कंवर ने भी चुड़ियों पर नगीने की कतार बनाने वाली मशीनों से अच्छा-खासा मुनाफा कमा कर उदाहरण प्रस्तुत किया। इंदिरा प्लास्टिक की चुड़ियों को अपने घर से ही बेचने का छोटा-मोटा काम कर लेती थी। इंदिरा के पति गणपत लोडिंग टैक्सी चला कर परिवार का गुजारा करते थे, जिसमें पुरा नहीं पड़ता था। तीन साल पहले जब इंदिरा ने इन मशीनों के बारे में सुना, तो हिम्मत जुटा कर एक मशीन पर काम शुरू कर दिया। मिलनसार इंदिरा ने आस-पड़ौस और जान-पहचान की दूसरी औरतों को भी इस काम के बारे में बताया और करीब 30 औरतें उसके पास नियमित रूप से नगीने लगाने का काम करने लगी। और देखते हीं देखते इंदिरा ने एक और मशीन पर काम चालू कर दिया। दोनों मशीनों की सभी किस्तों को चुका कर छह महीनों में करीब चार लाख से अधिक की कमाई की, यानी उसका औसत रहा लगभग 40 हजार रुपये महीना। इंदिरा ने अपने इरादों से अपने आर्थिक हालातों को बदल दिया है, आज उसमें आत्मविश्वास है, और हैं आंखों में नए सपने।

नया गांव की सुशीला ने बदली किस्मत



सुशीला अपनी बेटी के साथ चूड़िया तैयार करते हुए

पाली शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में कई स्थानों पर ये मशीनें लगी हैं जैसे सुन्दर नगर, नया गावं, पुलिस लाइन आदि। नया गांव क्षेत्र में करीब 150 चूड़ी यूनिट्स लगी हुई हैं। यहीं सुशीला ने भी चूड़ी पर नगीने लगाने का काम 4 बरस पहले शुरू किया था। बारीक नगीनों को एक पंक्ति में लगाने में आंखों पर काफी दबाव पड़ता था। इसलिए मशीन 11 हजार के डाउन पेमेंट पर खरीदी और शेष राशि को आसान किश्तों में चुकाया। सुशीला बताती हैं कि वो इस मशीन के आने से बहुत खुश है क्योंकि इसमें नगीनों की लाइन बनाने में अब बहुत आसानी हो गई है जिससे वो अपनी बेटी और आस—पड़ौस की महिलाओं के साथ मिलकर ये काम करती हैं। सुशीला आगे बताती है कि मशीन आकार में छोटी है और कहीं भी इंस्टॉल की जा सकती है। सुशीला ने बताया कि वो घर के रोजमर्रा के काम निपटा के आसानी से ढाई हजार चूड़ियों पर नगीने लगा देती हैं जिससे महीने में 25 से 30 हजार रुपए कमा लेती है, और भुगतान भी तुरंत मिल जाता है।

अभिशप्त जीवन से निकल नई जिंदगी जी रही साटिया जातिकी महिलाएं

इसी तरह पारम्परिक तौर पर पीढ़ियों से देह व्यापार के घंधे में लिप्त साटिया जाति की महिलाओं के लिए भी पाली के चूड़ी उद्योग ने नई रौशनी दी है। लघु उद्योग भारती के उद्यमियों ने जब इन परिवारों से इस उद्योग से जुड़ने का आग्रह किया, तो धीरे—धीरे कई महिलाओं ने इसे अपना लिया और आज तो मंजर ही बदल गया। 52 मशीनें इन्हीं परिवारों में लगी हैं जिन पर काम कर रही महिलाओं ने उस नारकीय धंधे से अपने आप को बाहर निकाला और सौभाग्य

की प्रतीक चूड़ियों पर नगीने जड़ने का कार्य शुरू किया। चूड़ी उद्योग से न केवल महिलाओं को आर्थिक सम्बल मिला है, बल्कि समावेशी समाज के निर्माण में भी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। समाज की अन्य महिलाओं का इन साठिया जाति की महिलाओं से किसी भी तरह का मेलजोल तो बहुत दूर की बात थी, इनसे सहज संपर्क या संवाद भी असंभव जैसा था। इन चूड़ियों की मशीनों ने वो दीवार भी तोड़ दी है, और इन्हीं मशीनों की बदौलत उन्होंने सम्मानजनक जीवन जीना भी शुरू कर दिया है।





पाली में कुल्हड़ उद्योग ने जगाई नई उम्मीद

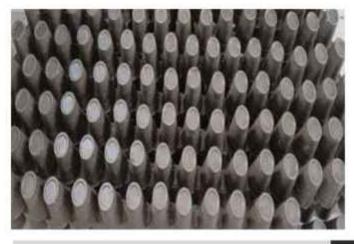
रेल मंत्रालय स्टेशनों पर कुल्लड़ों को अनिवार्य करके हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है। लेकिन इसके लिए सप्लाई लाइन तैयार करना भी जरूरी है। पाली जिले में प्रतिदिन 1 लाख कुल्लड़ बनाने की क्षमता को अगले तीन महीनों में 5 लाख तक ले जाया जायेगा।

स्वावलंबन @ पाली

पाली की कौशल विकास टीम ने स्वरोजगार के लिए सिलाई, चूड़ी के बाद तीसरे उद्यम के रूप में कुल्लड़ निर्माण को चुना। बदलती जीवन शैली और बढ़ते तनाव के बीच अपनी सेहत के प्रति लोगों की बढ़ती फिक्रमंदी, खान—पान के बदलते तौर—तरीकों, खासतौर पर मिटटी से बने बर्तनों में खाना पकाने और मिटटी के पात्र में पानी, चाय, कॉफी और लस्सी पीने की नयी आदतों ने कुल्हड़ को बाजार में अपनी जगह बनाने का अवसर तो दें ही दिया है।

कुल्लड़ उद्योग का 'पाली मॉडल'

पाली की कौशल विकास टीम ने कुल्हड़ बनाने की तीन मशीनों का सेट 3 लाख 51 हजार रुपए की कीमत में ऑफर किया। इसमें एडवांस 51 हजार रुपए और शेष राशि की आसान किस्तें ली जाती हैं। पहले तीन महीने तक कोई भी किस्त नहीं ली जाती। इसके साथ ही टायल बेसिस पर एक



महीने तक मशीन को रखा, जांचा -परखा जा सकता है और उसके बाद भी वापस लौटाया जा सकता है लेकिन आज तक किसी ने भी कोई भी मशीन (सिलाई, नगीने लगाने वाली और कुल्लड मेकिंग) वापस किसी ने नहीं लौटाई।

पूर्व विधायक श्री ज्ञानचंद पारख ने जानकारी दी कि अभी तक 20 मशीन सोजत, जुपेलाव, चेंडा देनाशनी, खेतावास क्षेत्रों में भेजी जा चुकी हैं और एक लाख कुल्लड़ प्रतिदिन उत्पादन कर रही हैं जिसे अगले तीन महीनों में 5 लाख कुल्लड़ तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक परिवार एक मशीन से एक लाख रुपए महीना कमा सकता है। परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करें, तो कोई अतिरिक्त लागत बहुत अधिक नहीं आती।

कुल्लड् का बढ़ता बाजार

कुल्लड़ होटल, रेस्तरां से लेकर कॉर्पोरेट घरानों में तो लोकप्रिय है ही, करवों में भी कांच, प्लास्टिक और पेपर के ग्लास के बजाय चाय की थड़ी पर भी अब कुल्लड़ नजर आने लगा है। कुल्लड़ की मांग कई संक्टर में हैं, लेकिन अकेला रेल मंत्रालय स्टेशनों पर कुल्लड़ों को अनिवार्य करके हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है। बीते दिनों इस बारे में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से अनौपचारिक चर्चा भी की थी। जिसके सुपरिणाम शीघ्र मिलने की संमावना है।

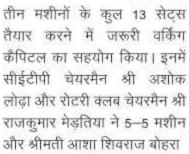
बाजार की समस्या नहीं है कुल्लड़ बेचने में। आजकल वही पुराना दौर लौट रहा है मिटटी की हांड़ी में कढ़ी, सब्जी बनाना। मिट्टी के तवे और कूकर बन और बिक रहे हैं। ये बड़ा बदलाव है।

कुल्लड् प्रकल्प के सहयोगी समाजसेवी



कुल्लड़ उद्योग में अन्य प्रकल्पों की बजाय कुछ महंगी मशीनें काम आती हैं। इसलिए इस प्रकल्प में स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को नयी मशीन बनवाकर उन्हें सींपने के कार्य में तीन स्थानीय उद्यमियों को भी जोड़ा गया। इन सहयोगियों ने

श्री राजकुमार मेडतिया कुल्ल ड निर्माण की





श्री अशोक लोढ़ा



ने 3 मशीनों के निर्माण में बिना ब्याज राशि का बंदोबस्त किया।

श्रीमती आशा एवं श्री शिवराज बोहरा

कैसे बनता है कुल्लड़



कुल्लड़ का रॉ मेटेरियल हैं काली चिकनी मिटटी, जो आसपास जोहड़ों आदि में बहुतायत में आसानी से मिल जाती है, नरेगा जैसी स्कीम में सरकार तो खुद तालाबों, पोखरों



आदि जल स्रोतों से मिट्टी हटवाती है। सिर्फ इसके भरने और उसके ट्रांसपोर्ट पर ही खर्च आता है या थोड़ा बहुत तब, जब इनको इनको कच्ची भट्टी में लकड़ी के सूखे बूटों को जलाकर पकाया जाता है। इससे पहले मिटटी की ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग कर उसे तैयार किया जाता है। कुल्लड़ भट्टी में पकाने के लिए करीब 5 हजार से अधिक एक साथ लगते हैं। मिटटी में कोई भी रंग नहीं डाला जाता, लेकिन पकने के बाद उसका रंग स्वतः गेरुआ हो जाता है।

कुल्लड बनाने में तीन मशीनों को काम में लिया जाता है पीएलसी मशीन, ग्राइंडिंग और मिक्सचर। सामान्यतः कुल्लड



तीन आकारों में तैयार किये जाते हैं जिसमें 60, 80 और 200 एमएल लिक्विड आ सकता है। बड़ा कुल्लड अक्सर लस्सी, दूध या शरबत में काम में लिया जाता है। खेतावास के नरपत सिंह ने बताया कि एक किलो मिटटी में करीब 35 चाय या कॉफी कुल्लड बन जाते हैं। और इस मशीन से एक घंटे में 700 कुल्लड तक बनाये जा सकते हैं। चाय और कॉफी कुल्लड 1.30 से 1.50 रुपए तक बिकता है, तो दूध और लस्सी कुल्लड़ 2.50 से 3.50 रुपए में। चेंडा में इस मशीन से कुल्लड़ तैयार करने वाले श्री नकाराम प्रजापत का कहना है कि मशीन में कई फीचर्स बड़े अच्छे हैं और इस मशीन से बनने वाले कुल्लड़ की अच्छी क्वालिटी और उचित दर के कारण वे बाजार के ऑर्डर पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं।

पाली का ब्यूटी पार्लर एवं मेहंदी कौशल प्रकल्प

सिर्फ रोजगार सूजन ही नहीं, बल्कि लव-जिहाद की विकृत मानसिकता की रोक की गारंटी भी

पाली के जागरूक स्थानीय समाज में शादी-विवाह और अन्य सभी मांगलिक कार्यों पर मेहंदी और सौंदर्य-सज्जा के कार्य में अब सिर्फ हिन्दू परिवारों की बेटियों का ही प्रवेश संभव है।

समाज जागरण @ पाली



पाली की कौशल विकास टीम ने स्वरोजगार एवं स्वावलंबन के लिए चौथा कौशल ब्यूटी पार्लर एवं मेहंदी को चुना। इस कौशल के चयन में स्वरोजगार तो निहित था ही, साथ में वो दंश भी था जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के उदात्त भाव के साथ सबके कल्याण की कामना करने वाले सनातनी समाज को दिया गया। मेहंदी, कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर, ब्यूटीशियन और न जाने कैसी—कैसी छद्म भूमिका में गैर सनातनी युवा हिन्दू परिवारों की बेटियों को लव जिहाद की पाशविकता का शिकार बनाते गए।

पहले तो ऐसी खबरें देश के महानगरों से कभी—कभार मीडिया में देखने—सुनने में आती, लेकिन फिर ये घटनाएं छोटे शहरों और कस्बों में भी आम होने लगी। इससे सनातनी परिवारों का न केवल मोटा पैसा समाज से बाहर अवांछित और गलत गतिविधियों में जाने लगा, बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत विधर्मियों को हिन्दुओं के घरों में रेकी करने के लिए बेरोकटोक आने—जाने का लाइसेंस भी मिल गया था।



सामूहिक शिविर में मेहंदी लगवाती सनातनी बहनें

चिंतन से हुआ मार्ग प्रशस्त

वर्ष 2021 में जब ये जानकारी में आया कि सनातन धर्म के मांगलिक पर्वों और अन्य अवसरों पर हाथों में मेहंदी लगाने का कार्य शहर के प्रमुख चौराहों पर शॉपिंग मॉल के बाहर यूपी और बंगाल के गैर सनातनी युवक करते हैं। तब तत्कालीन विधायक श्री ज्ञानचंद पारख ने इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक श्री कमल किशोर गोयल एवं सेवा समिति वृद्धाश्रम के संचालक श्री प्रमोद जैथलिया से की। इस महत्वपूर्ण चर्चा में ये निर्णय किया गया कि सनातनी लड़कियों को मेहंदी का औपचारिक प्रशिक्षण देकर हर हिन्दू परिवार तक उनका सीधा संपर्क करवाया जाये।

मेहंदी कौशल में पारंगत सनातनी बहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती ने हिन्दू संस्कृति से जुड़े मांगलिक अवसरों और तीज—त्योहारों पर पाली में मेहंदी आर्ट वर्क के बड़े कार्यक्रम आयोजित किये जिसमें हजारों महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगवाती हैं।

इस सौंदर्य सज्जा और मेहंदी प्रकल्प के निःशुल्क प्रशिक्षण में

आर्थिक सहयोग करने वाली अग्रणी संस्थाओं में पाली का रोटरी क्लब और सेवा समिति वृद्धाश्रम प्रमुख हैं।

इसके साथ ही इन प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था और समन्वय कार्य में सहयोग करने वालों में विश्व हिंदू परिषद के पाली जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र माक्षर, श्री मानवेंद्र सिंह भाटी, राजश्री पब्लिक स्कूल के व्यवस्थापक श्री राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, अग्रवाल पंचायत के अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता, समाजसेवी श्री सुनील पोद्दार, अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती जोली गुप्ता, माहेश्वरी समाज की अध्यक्ष श्रीमती शांति कासट और श्रीमती सुमन सेन शामिल हैं।

इसके साथ अन्य सहयोगी संस्थाओं में महिला जन सहयोग वेलफेयर सोसाइटी, संस्कार केंद्र स्कूल, विश्वकर्मा मंदिर, दुर्गा वाहिनी एवं मातृशक्ति, नारी शक्ति मंडल हाउसिंग बोर्ड, दाधीच ब्राह्मण समाज, सेन समाज, एवं कुमावत समाज शामिल हैं।

और हुई एक अभिनव शुरुआत

और फिर सेवा समिति वृद्धाश्रम में तत्काल प्रशिक्षण शिविर लगा कर करीब 150 लड़िकयों को मेहंदी एवं ब्यूटी पॉर्लर में प्रशिक्षित किया। यहीं से मेहंदी और ब्यूटी पार्लर कौशल के 45 दिवसों के औपचारिक प्रशिक्षण की विधिवत शुरुआत हो गई। वर्ष में इस कौशल के प्रशिक्षण शिविरों का कैलेंडर बना। शिविरों का ये क्रम अनवरत रूप से चल रहा है जिसमें प्रशिक्षण के दौरान काम में लिए जाने वाले सभी सौंदर्य प्रसाधन भी नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं। शिविर में प्रशिक्षण पूरा करने वाली सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाते हैं।



पाली के सर्व समाज की प्रबुद्ध महिलाओं के सम्मेलन में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी एवं स्थानीय विधायक श्री ज्ञान चंद पारख

प्रकल्प का प्रभाव

मेहंदी और ब्यूटी पार्लर कौशल में प्रशिक्षित पहले बैच के तैयार होते ही रक्षाबंधन के पूर्व पाली के समस्त जातीय महिला संगठनों और सामाजिक संगठनों की महिला पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित कर लघु उद्योग भारती के इस प्रकल्प के उद्देश्य के बारे में बताया गया तथा उनको साथ लेकर शहर को पांच भागों में बांटकर बाजार से कम दर पर सामूहिक मेहंदी लगाने के शिविर आयोजित शुरू किये गए।

इन शिविरों के आयोजन से सर्व समाज में बहुत बड़ा बदलाव देखने में आया और पाली की अधिकांश महिलाओं ने गैर सनातनी युवकों की बजाय अपने शिविरों में हिन्दू बेटियों से अपने हाथों में मेहंदी लगवाई। वर्ष 2022 से निरंतर रक्षाबंधन, तीज —त्यौहार और उप छठ के उपलक्ष पर प्रबुद्ध महिलाओं की मीटिंग आयोजित कर इस अभियान को सफल करने के लिए संगठन निरंतर प्रयासरत है।

व्हाट्सएप्प से पकड़ी प्रकल्प ने गति



अभी तक ब्यूटी पार्लर में 250 एवं मेहंदी में 500 से भी अधिक हिन्दू युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन सभी प्रशिक्षित युवतियों के नाम, मोबाइल नम्बर और उनकी कॉलोनी के नाम की जानकारी डिजिटल सूची को सभी समाजों की अग्रणी महिलाओं

को व्हाट्सएप्प के माध्यम से साझा कर दी गई। इसका सुखद परिणाम ये हुआ कि स्थानीय परिवार किसी भी मांगलिक कार्य पर सौंदर्य—सज्जा और मेहंदी के लिए अब स्वतः ही उनसे संपर्क कर लेते हैं।

इस प्रकल्प से जुड़ी राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की पूर्व अतिरिक्त निदेशक और भारत विकास परिषद, पाली की अध्यक्ष श्रीमती नूतन बाला कपिला ने बताया कि ब्यूटी पार्लर एवं मेहंदी कौशल की बदौलत पाली की सैकड़ों हिन्दू बेटियों को स्वरोजगार का न केवल एक नया प्लेटफार्म मिल सका, बल्कि वे आज अच्छी आय अर्जित कर सम्मानजनक जीवन जी रही हैं।



steel packaging solution

for export and domestic logistics

fabricated metal assemblies





KAIZEN

With Best Compliments

Aseem Chawla Director

Kaizen Metal Forming Private Limited committed to continual improvement

BH 707-708, 7th Floor, Puri 81st High Street Business Hub, Sector 81, Greater Faridabad 121002, Haryana

info@kaizenmetal.com

www.kaizenmetal.com

+91 9711298250

SARASWATI GROUP OF COMPANIES





Polycarbonate Sheets



Stewaroon St. 9, 2nd Floor, Januara Apartments, MH-21, Kharar-Kurali Road Khangur, Kharar, Moradi (Punjab) | TeL: 97/82-925982, 536592 Foliow ss.: Sarapwali Agra Life Science (C. O. O.)





Phone No 01762 535901



Do you have a Question? info@saraswatiplastotech.com



LANE-4, PHASE-1, SIDCO INDUSTRIAL COMPLEX, BARG BRAHMNA, JAMMU-181133



OUR PRODUCTS

We only purchase raw materials from established, respected suppliers to ensure our products meet the highest quality standards. Our packaging is made from sustainable resources most of which are either compostable or recyclable.

- Regular Cartons
- Folding Cartons
- Litho-Laminated Multi Coloured Cartons
- Point of Sales Displays
- Big size Boxes
- Self Assembly Boxes
- Die Cut Boxes
- Fittings & Inserts
- Wood Replacement Boxes
- Corrugated Pallet
- Specialized Coated Boxes
- Complete Packaging
- Solutions for Export

OUR LOCATIONS

Corrugation Plants

Plant 1: IIB, Udhyog Vihar, Greater Noida, Uttar Pradesh 201306 Plant 2: Village Bir Pillasi, Nalagarh, Solan, Himachai Pradesh 173205 Plant 3: 900 Rosewood Drive Sricity, Chittor, Andhra Pradesh 5175541 Plant 4:135 sector 24, Faridabad, Haryana 121005

Corrugation Board Converting Plants

Plant: 275, 276, Sector 24, Faridabad, Haryana Plant 2:5, Sipcot industrial Area, Cheyyar, Tamiinadu Printing & Folding Box Division

Plant 1: 135 sector 24, Faridabad, Haryana 121005

Plant 2: 900 Rosewood Drive Sricity, Chittor, Andhra Pradesh 517554



(An IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015)

Manufactures of Automotive Components & Engineering Services

"DATA GROUP" is a trusted manufacturer of Vent Caps, e-PTFE Membranes, Nylon Cable Ties, Plastic Moulded Parts, Battery Child Parts and more. With over 25 years of expertise, we also provide reliable Engineering & R & D services, ensuring world-class quality, timely delivery and innovative solutions for Automotive OEMs."

Our Group Comapnies

- * SHH INDUSTRIES PVT. LTD. * SANJAY ELECTRICALS
- * TIRUPATI INDUSTRIES + D G CORPORATE INDIA MFG. PVT. LTD.
- * XINGDAO-HK PVT. LTD.

CORPORATE OFFICE:- PLOT-101, SARASWATI VIHAR, BAW REWARI-123401, HARYANA

FACTORY ADDRESS:- PLOT NO-275, 141, 145, 71A, 145, SEC-3, 9 & 7 HSIDC GROWTH CENTER, BAWAL-123501 HAR

With best compliments from:



RAJSHREE INDUSTRIES

(AN ISO 9001 : 2015 Co.)

Manufacturers of :

ALL TYPES OF FUEL LINES, HIGH PRESSURE HOSES, PIPE FABRICATION, SHEET METAL PARTS & AUTOMOTIVE MUFFLER HANGER PARTS

Plot No. 5, Ram Singh Road, Village Bajri, Dabua Pali Road, Faridabad-I21004 (Haryana) Tel./Fax: 0129-2481951, Plot No.: 733/69, IMT Faridabad-I21004

Tel.: 0129-2427884; Cell: 9810053587 E-mail: info@rajshreeindustries.com, rkchawla33@gmail.com www.indiamart.com/rajshree-industries

Contact: +91 9996823975 Support@greenkadam.com

payment pao!



turant pickup aur turant

App Store

Google Play





Important Activities-

- 31st May, 2023- LUB's J&K Team met Mayor JMC Shri Rajinder Sharma and apprise him about concern related to illegal import of polythene.
- 28th June, 2023- J&K Team submitted Memorandum to comm/secy I&C Department at Srinagar.
- LUB J&K organized an internship for students (B.Com. Final year) at Nature Fresh Foods about Hygienic Manufacturing.
- 6th Dec, 2023- Team LUB J&K handling over a memorandum to CS Shri Atal Duloo at Jammu.
- 6th March 2024- J&K Team holds Strategic meet to boost MSME sector with RSS Prant Pracharak Shri Rupesh Kumar.
- 5th April 2024- J&K Team convened a significant Working Committee which was chaired by National Secretary Smt. Anju Bajaj & National VP Shri Arvind Dhumal.
- 4th August, 2024- LUB Praises LG administration for pro-people policy on uncultivated land (Gair Mumkin Khad).
- 23th Aug, 2024- LUB Team meets Union Minister

- Shri Piyush Goyal and urged for investment package expansion.
- 10th June, 2025- LUB urges immediate policy reforms to protect J&K industrial sector.
- LUB's National VP Shri Arvind Dhumal, National Secretary Smt. Anju Bajaj announced New Team.
- 17th July, 2025- LUB J&K delegation led by National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji met J&K CS Shri Atal Duloo.
- 23th July, 2025- J&K Team headed by National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji met Union Home Secy. to discuss MSME issues in J&K.
- 13th June 2025- J&K Team organized a Workshop on Business Growth with Smt. Sanmeet Kaur.



- J&K Unit had a meeting with LG Shri Manoj Sinha regarding the development of Industry & Tourism.
- LUB's Team met Past President ICAI Shri Chandra Wadhva at Industry Association office regarding Industrial Issues at Gangyal Jammu.



Achievements-

- 23rd July, 2025- Kathua Unit formed with 15 memberships were received on the spot.
- 17th July, 2025- J&K Unit held an introductory seminar for industrialists of Kmr at Srinagar, 4 memberships were received.
- Director, IIM Jammu Shri B.S. Sahay and LUB's J&K President Shri Parveen Pargal felicitated the artists who performed at "Mahotsav 9-10 Dec. 2023" Jammu.
- 10[®] May 2024- A seminar was organised at Sher-e-Kashmir University of Agriculture Science & Tech. of Jammu. LUB's President addressed the new entrepreneurs.
- 14^a July 2025- President Shri Parveen Pargal, Gen. Sec. Shri Aagam Jain, VP Shri Ankit Gupta, Members Shri Rajesh Jain & Shri Anil Suri had an interaction with students in the Orientation Program of MBA batch at IIM Jammu.
- Team J&K participated in the India-UAE Investor meet with entrepreneurs from various emirates and the JK Govt at Srinagar,

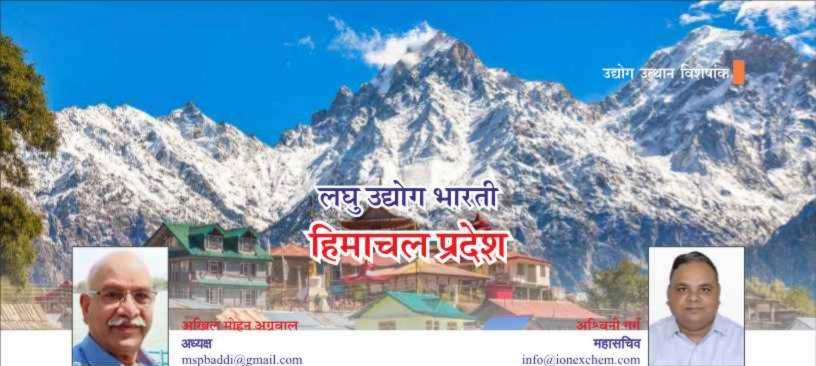
Future Agenda (2025-2027) -

After the abrogation of Article 370 and 35A, many new opportunities have opened-up for investment and growth. But the industries are facing serious challenges like delays in land allotment, pending incentives, SGST refund issues, and lack of purchase preference. Hence, Team J&K team has prepared a two-year action plan.



Industrial Package & Policy Support.

- Push for extension of New Central Sector Scheme (NCSS) till September, 2027 with increased Scheme Fund from ₹28,400 crore to ₹1 lakh crore.
- Ensure that pending applications (720+) and MSMEs get their share of incentives.
- Get the pending turnover incentives (2021–22, 2022–23, 2023–24) released.
- Make sure SGST refunds are not stopped because of minor delays.
- Clear all old payments of government departments and PSUs (like SICOP).
- Get a Procurement Policy with at least 20% purchase preference for local industry.
- Support to MSMEs & Startups
- Form Industrial Estate Teams in every district to solve local problems.
- Organize workshops on GST, Finance, Compliance, and Schemes.
- Connect MSMEs directly with banks, big companies, and government departments.
- Double the Membership in the next 2 years.
- Hold monthly estate meetings and quarterly district-level conventions.
- Launch a Member Connect Program with regular updates and training.
- Start a digital portal for all members.
- Attracting Investment & Growth.
- Work to bring in ₹5 lakh crore new investments in J&K.
- Organize Industrial & Tourism Conclaves in Jammu, Srinagar and Delhi.
- Develop Sector-based Clusters- like Textile in Kathua, Food Processing in Jammu, Tourism in Pir Panjal.
- Start B2B connect programs linking small industries with large ones.
- Push for an IT Park in Jammu and new private universities in the UT.
- Promote Jammu as a separate tourism hub.
- Highlighted districts for special tourism-Kathua for heritage, Bhaderwah for Nature and Poonch and Rajouri for adventure.
- Create Raika Leopard Reserve for eco-tourism.





वर्ष 2023-25 का विस्तृत एवं संवर्धित प्रतिवेदन

पिछले दो वर्षों में लघु उद्योग भारती, हिमाचल प्रदेश ने संगठन की दृष्टि से न केवल अपने वार्षिक कार्यक्रमों को समय पर और प्रभावी ढंग से आयोजित किया, बल्कि संगठन ने अपने कार्यक्षेत्र को भी व्यापक बनाया है। राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों – बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, दवनी, काला अंब, परवाणु और पालमपुर में संगठन की पूर्ण इकाइयाँ तथा नगरोटा बगवां, संसारपुर टेरेस व् पौंटा साहिब में संयोजक इकाइयाँ दिन—प्रतिदिन सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

इस अवधि में संगठन ने उद्योग हितैषी वातावरण बनाने, सदस्य उद्यमियों के साथ सतत संवाद कायम रखने, और प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई नीतिगत व व्यवहारिक कदम उठाए हैं।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ / कार्यक्रम-

 नियमित मासिक बैठकें- प्रत्येक इकाई में मासिक बैठकें आयोजित कर स्थानीय स्तर की समस्याओं का संज्ञान लिया जाता है और उनके त्वरित समाधान के प्रयास किए जाते हैं। इन बैठकों में सदस्यता नवीनीकरण के साथ नए सदस्यों को भी जोड़ा गया।

- क्षेत्र-विशेष गोलमेज वार्ता- 'उद्योग-मित्र' संवाद के माध्यम से अलग-अलग सेक्टरों के उद्यमियों के साथ नीतिगत मुद्दों, उद्योगों की चुनौतियों और तकनीकी उन्नयन पर विस्तृत चर्चा कर उनके हल के लिए सम्बद्ध अधिकारियों के समक्ष रखा जाता है।
- स्थापना दिवस (15 अप्रैल) यह दिवस पूरे प्रदेश में एकता और सम्मान का प्रतीक बन गया है। इस अवसर पर संस्थापक सदस्यों, वरिष्ठ उद्यमियों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवियों, संस्थाओं और MSME विभाग के अधिकारियों का सम्मान किया गया साथ ही सामुदायिक सेवा की नई पहल भी शुरू की गई। इस वर्ष संगठन के स्थापना दिवस पर शिमला लोकसभा सांसद श्री सुरेश कश्यप और MSME के उपनिदेशक की उपस्थिति में औद्योगिक मंथन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के सदस्य सपरिवार उपस्थित रहे।



- परिवार मिलन समारोह हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष परिवार मिलन समारोह उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में सभी सदस्य परिवार सहित भाग लेते हैं। बद्दी में यह कार्यक्रम रखा गया।
- विश्वकर्मा दिवस- प्रदेश की सभी इकाईओं में 17 सितम्बर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। इस दिन सभी सदस्य अपने अपने उद्योगों में विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना करते हैं, उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित करते हैं ताकि उनका मनोबल बढे।
- सामाजिक व आपदा-संवेदी कार्य- कठिन मौसम, प्राकृतिक आपदाओं और विशेष परिस्थितियों में संगठन ने उद्योग और समाज के बीच सेतु का कार्य किया। संगठन उद्योग हित के साथ सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमाचल में त्रासदी या महामारी के समय लघु उद्योग भारती ने सेवा भाव से आगे आकर अपना योगदान किया। इस वर्ष भी हिमाचल में भारी बारिश से भयंकर त्रासदी आयी, जिससे गाँव के गाँव उजड़ गए और लोग बेघर हो गए। संगठन ने आगे आकर उनकी भरपूर सहायता की। जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री, तिरपाल, कम्बल और वस्त्र मुहैया करवाए।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ-

- समयबद्ध और अनुशासित कार्यक्रम- वार्षिक, त्रैमासिक और विशेष आयोजनों का समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ आयोजन किया, जिसमें उद्यमियों की सहभागिता लगातार बढ़ी।
- समस्या-निवारण तंत्र- इकाई स्तर पर उठाए गए मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए समर्पित तंत्र का विकास किया, जिससे उद्यमियों का भरोसा संगठन पर और मजबूत हुआ।
- नीतिगत संवाद- MSME और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ गहन संवाद और नीति सुझावों के



- माध्यम से उद्योग—जगत के हितों का प्रभावी प्रतिनिधित्व किया।
- सहयोग और एकता- 'विचार—मिलन' जैसे आयोजनों से उद्योगपतियों में आपसी सहयोग, अनुभव साझा करने और सामूहिक प्रगति की भावना को बल मिला।



आगामी समय के लिए दृष्टि-

- संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण- प्रत्येक जिले में इकाइयों का विस्तार और कन्वीनर—क्लस्टरों को अधिक सशक्त बनाना और ग्रामीण एवं अर्ध—शहरी क्षेत्रों में संगठन की पहुँच को और व्यापक करना।
- नियमित सेक्टर-विशेष चर्चा- उद्योग—विशेष विषयों पर त्रैमासिक गोलमेज बैठकों में कानूनी अनुपालन, बाजार प्रवृत्तियाँ, तकनीकी नवाचार, उद्योग हित और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषय शामिल करना।
- महिला और युवा विंग का विस्तार- उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु लक्षित प्रशिक्षण, मेंटरशिप और सफलता की कहानियों को साझा करना।
- डिजिटल समन्वय- शिकायत और सुझाव प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बैठक कैलेंडर और दस्तावेजों पर ई—फीडबैक प्रणाली लागू कराना होगा।
- कौशल विकास और बाजार जोड़- उत्पाद की गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात तैयारी पर विशेष वर्कशॉप; क्लस्टर—आधारित B2B कार्यक्रमों के माध्यम से बाजार में अवसर प्रदान करना ।
- वार्षिक 'विचार-मिलन' को राज्य का प्रमुख फ्लैगशिप आयोजन बनाना, जिसमें नीति—निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और निवेशकों की सहभागिता हो।



Important Activities & Programs:

Over the past two years, LUB's Punjab State Unit has worked with renewed vigour to strengthen MSMEs ecosystem. Our programs have been focused on industrial revival, skill enhancement, technology adoption, and community service. Key highlights include:

1. "100 Days - 100 Technologies Program":

A joint visit with 50 members from Punjab & Delhi teams to CSIO, Chandigarh was organised. Participants visited laboratories, observed advanced technologies, and explored ways these innovations could benefit industry operations and competitiveness.

2. Swayamsiddha Exhibition at Jalandhar:

- 60 women entrepreneurs showcased their products in the exhibition held on November, 2024.
- The main unit hosted 14 industrial stalls from state members, promoting B2B interaction & visibility for local industries.
- Swayamsiddha (August'25) Organised by the Women Wing, bringing women-led enterprises to the forefront.

3. Collaboration with HT Ropar:

A MoU for collaboration was signed to promote industrial growth and technology adoption on 31" July, 2025. Two Punjab team members were appointed as pan-India representatives to disseminate IIT Ropar's technologies and maintain active communication between industry & academia.

4. Strengthening of Unit Teams:

- On 7th March 2025, the Ludhiana team was revived, adding 30 new members to date.
- In 2024, the Bathinda team was also revived and now has 70 active members.

5. North Zone Conclave Participation:

On 26th March 2025, a 50-member delegation from Punjab participated in the North Zone Conclave at Ambala, representing the state's industrial interests at the zonal level.

6. Formation of New Punjab State Team:

In June 2025, a new state team of LUB Punjab was constituted with dedicated members on various positions. This reorganisation marked a new chapter for LUB Punjab, ensuring strong leadership and a focused approach towards industrial growth and member engagement.

7. Community Service Initiatives:

Multiple Blood Donation camps and Tree Plantation Drives were organised to strengthen LUB's commitment to social responsibility alongside industrial advocacy.

8. Regular Cultural and Networking Events:

Six major events, including Unit-wise Sathapna Diwas Celebrations, Vishwakarma Jayanti celebrations and Pariwar Milan, have been held regularly, fostering unity among members and reinforcing cultural traditions within the industrial community.

These activities have ensured that the LUB Punjab remains a proactive platform for problem-solving, representation, and growth.

Important Achievements

Revival of Monthly Meetings:

A key organisational achievement has been the revival of monthly meetings across the state. Such meetings ensure the active participation, communication, and timely resolution of industry concerns.

Revival & Upliftment of Screw Industry:

The Punjab screw industry, which was on the verge of closure due to intense and unfair foreign competition, witnessed a significant revival owing to LUB Punjab Team efforts. Through continuous representations and follow-ups, we succeeded in securing the imposition of import duties on Chinese products and making BIS certification mandatory. This intervention not only safeguarded the interests of local manufacturers but also uplifted the industry's growth prospects and restored industrial confidence.

Women's Entrepreneurship through Swayamsiddha:

The Swayamsiddha exhibition became a milestone event for women's empowerment in Punjab. By offering a platform for women entrepreneurs to exhibit and market their products, it significantly contributed to their economic upliftment and visibility in the industrial ecosystem.

Projections for the Coming Years:

At LUB Punjab, our vision for the future is rooted in the belief that MSMEs are the backbone of the Indian economy. Strengthening MSMEs will directly strengthen India's economic power. Our forthcoming initiatives will focus on:

- Increasing membership to create a stronger, united voice for Punjab's industrial sector.
- * Social and economic upliftment of workers, their

- families, and the lower-income segments of society.
- Providing a breathing space for micro units, enabling them to recover, sustain, and expand.
- Employment generation through industrial growth and innovation.
- Creating stronger communication channels between the Punjab State team and the LUB Head Office for timely issue resolution.
- Regular B2B engagement, including displaying member products at every meeting to promote intra-industry trade.

Challenges & Proposed Solutions -

Punjab's micro industries face critical challenges inadequate state government schemes, poor
infrastructure (roads, water supply, street lighting, and
sewage), and the absence of micro-industry-focused
support despite being heavy taxpayers. Many units are
failing under these constraints.

To address this, we will:

- Conduct regular meetings with the Head Office to present state-level concerns effectively.
- Maximise benefits from networking and policy dialogues in our meetings.
- Organise more frequent events for both industrial problem-solving and business promotion.

Projection-

We foresee MSMEs in Punjab achieving sustained growth through our interventions. Micro industries currently on the verge of closure can be revived, leading to increased employment, economic stability, and upliftment of the common man. A stronger MSME sector means a stronger Punjab - and ultimately, a stronger India.







<mark>अवी भसीन</mark> अध्यक्ष avi.bhasin@gmail.com

<mark>मनीष निगम</mark> **महासचिव** scientific_works@yahoo.com



लघु उद्योग भारती चंडीगढ़ (यूटी) इकाई निरंतर प्रयासरत रही है कि चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMES) के लिए सकारात्मक, सरल और व्यावहारिक नीतियाँ बने। जुलाई, 2023 से टीम चंडीगढ़ ने नए उत्साह और कार्य-शैली के साथ क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर करने व समाधान तक पहुंचाने के लिए कई उल्लेखनीय कदम उठाए।

चंडीगढ़ इकाई का विश्वास रहा है कि जब तक नीति स्तर पर छोटे उद्योगों की आवाज मजबूती से नहीं रखी जाएगी, तब तक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना अधूरी रह जाएगी। इसी सोच को आधार बनाकर, हमारे संगठन ने प्रशासक, सलाहकार, मुख्य अभियंता, इंडिस्ट्रयल किमश्नर से लेकर शहरी नियोजन विभाग, पुलिस विभाग, ट्रैफिक विंग, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक हर प्रशासनिक विभाग के साथ सार्थक संवाद किया।

प्रमुख प्रयास-

ऑनलाइन म्युटेशन सिस्टम लागू कराना-

एलयूबी चंडीगढ़ की पहल पर संपत्ति के पंजीकरण के दो दिन के भीतर म्युटेशन की सुविधा शुरू की गई। इससे उद्यमियों को अत्यधिक राहत मिली।

FAR (Floor Area Ratio) के लिए नीति परिवर्तन की मांग-

2 कनाल तक के छोटे औद्योगिक प्लॉट्स पर ऊपरी मंजिलों की अनुमति हेतु शासन से लगातार पत्राचार और बैठकें आयोजित की गईं। यह प्रस्ताव MSME की उत्पादन व रोजगार क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Car Service Stations को उद्योग मान्यता दिलाने की मांग-

टीम चंडीगढ़ ने MSME कोड 45 के अंतर्गत ऑटोमोबाइल सर्विस, पार्ट्स व एक्सेसरीज़ को मान्यता दिलाने की मांग की, ताकि इनका संचालन औद्योगिक क्षेत्र में जारी रह सके। संपर्क और संवाद से किया समन्वय और समाधान—

- एलयूबी चंडीगढ़ इकाई की साझेदारी और सक्रियता ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों जैसे चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन, इलेक्ट्रिकल मार्केट एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल शेंड वेलफेयर एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल यूथ एसोसिएशन आदि को एक मंच पर लाकर उनकी मांगों को सामूहिक रूप से उठाया। इस संगठनात्मक एकता से प्रशासन पर सकारात्मक दबाव बना और कई मुद्दों पर ठोस कार्रवाई हुई।
- ट्रैफिक ऑफिसर के साथ दीपावली जैसे त्योहारों पर सड़क अतिक्रमण, पार्किंग अव्यवस्था व ट्रैफिक जाम की समस्याओं को सुलझाने हेतु व्यावहारिक समाधान किया।
- प्रदूषण नियंत्रण विभाग के साथ संवाद से पर्यावरणीय नियमों में उद्यमियों को राहत देने हेतु नए निर्देशों की शुरुआत हुई।
- एलयूबी चंडीगढ़ टीम ने पुलिस प्रशासन व उद्यमियों के बीच सार्थक संवाद स्थापित किया।
- MSME सेक्टर के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ ऋण सुविधा पर कार्यशाला आयोजित की गई।

टीम चंडीगढ़ लघु उद्योगों की आत्मनिर्भरता, सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ तत्पर रहेगी।

With Best Compliments - Lub J&K



We Analyze, You Trust.

A Complete Testing House - Food, Drug and Environment First Testing Lab in J&K





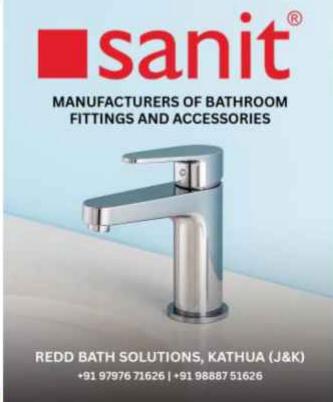








SIDCO Industrial Complex, EPIP, Kartholi, Bari Brahmana-181133 J&K. Phone: 9872923100





STRENGTHENING WORLD

MANUFACTURER OF SECRON POLYSTER INDUSTRIAL YARN (IDY)

Product Range :-

- 1000 Denier to 6000 Denier
- Above 9.0 gpd with super high tenacity
- Low Shrinkage
- Color Yarn

Applications :-

Conveyor Belts

- Technical Fabrics
- Seat Belts
- Geo-Textile
- Geo Grids
- Ropes

Contact Info :-

Kishan Goyal

Director +91 7404240009

Gopal Goyal Director +91 7404240005

Company Address :- Plot No. 14, 15, 16, SICOP Industrial Area, Govindar, Kathua, Jammu

E-mail: sgindustryinfo@gmail.com

112





• महत्वपूर्ण कार्य एवं कार्यक्रम(2023-25)



- उत्तराखंड एक हिमालय की पहाड़ियों से घिरा प्रदेश हैं
 जो हमेशा प्राकृतिक आपदाओं और अग्नि जैसी
 समस्याओं से पीड़ित रहता है इन समस्याओं को देखते
 हुए ही संगठन ने अग्नि एवं आपदा के समय में उद्यमियों,
 सरकार और प्रशासन के सहयोग हेतु लघु उद्योग भारती
 हरिद्वार जिला इकाई ने आपदा प्रहरी प्रकल्प बनाया
 जिसका शुभारंभ अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री घनश्याम
 ओझा और उत्तराखंड के प्रांत प्रचारक श्री (डॉ.) शैलेंद्र ने
 किया जो अपनी तरह का पूरे भारतवर्ष में एक ही प्रकल्प है।
- उत्तराखंड प्रदेश इकाई ने महत्वपूर्ण अवसरों जैसे लघु उद्योग भारतीय स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस, डैंडम दिवस, शहीद दिवस के अवसर पर 9 बार रक्तदान शिविर आयोजित किये जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इससे संगठन के प्रति समाज में आत्मीय भाव पैदा हुआ।

- लघु उद्योग भारती उत्तराखंड में इस अवधि में 4 नई इकाइयां स्थापित की गई जिसमें 1 प्रदेश महिला इकाई भी शामिल है.वर्तमान में संगठन का कार्य प्रदेश के सभी 13 जनपदों तक पहुंच गया है।
- सिंगल यूज प्लास्टिक अधिनियम के द्वारा उत्तराखंड राज्य में बहुत सारी इकाइयां बंद होने के कगार पर आ गई थी, तब संगठन ने हाई कोर्ट जाकर उद्योगों का संरक्षण किया और केंद्रीय अधिकारियों से संपर्क कर समाधान हेतु कार्य किया।
- उत्तराखंड राज्य में अचानक न्यूनतम मजदूरी 30 परसेंट से ज्यादा बढ़ाने से लघु उद्योग बहुत प्रभावित हुए और राज्य सरकार के अधिकारियों से वार्ता सफल नहीं हुई, तो इस विषय पर भी हाईकोर्ट जाकर सरकार के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त किया।
- 16वें वित्त आयोग के शिष्टमंडल से लघु उद्योग भारती ने वार्ता कर केंद्र सरकार से प्रदेश के विकास के लिए अधिक धनराशि की मांग की। इस कार्य के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव ने लघु उद्योग भारती के सदस्यों का आभार जताया।
- प्रदेश इकाई ने केंद्र और राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिए घर उपलब्ध करवाने में मदद की।
- केंद्र सरकार द्वारा VAT समाप्त करके जीएसटी कराधान प्रणाली लागू की गई तो कई इकाइयां जिनमें फार्म–16

के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। अच्छी—खासी पेनल्टी के नोटिस प्राप्त हुए थे, जिसमें उत्तराखंड संगठन ने राज्य सरकार के साथ संवाद कर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करवाई।



- छोटे उद्योगों के निर्माण में जमीन एक बड़ी समस्या होती है और जब बात भूखंड पर भवन निर्माण की होती है तो उसमें फिर FAR एक बड़ी समस्या आती है इस पर भी सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हुई और अब 55% की जगह 70% तक स्वीकृत करा लिया है जिससे छोटे और मझोले उद्योगों के लिए बड़ी सुविधा हुई है।
- स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत कार्य करते हुए ऐसे क्षेत्रों में जहां पर संसाधनों की बड़ी कमी थी और उद्यम भी नहीं थे लेकिन जनमानस की अपेक्षा थी तो लघु उद्योग भारती परिवार में युवा एवं महिला उद्यमिता पर विशेष कार्य करते हुए 600 से ज्यादा महिलाओं को उन्नत प्रशिक्षण दिलवाया और स्थानीय स्तर पर वहां रोजगारपरक सेंटर स्थापित करवाए जिनमें इन सभी महिलाओं को काम उपलब्ध कराया गया। साथ ही ऐसे युवा जो कार्य सीख कर अपना उद्यम स्थापित करना चाहते थे, उन्हें राज्य सरकार के सहयोग से प्रशिक्षण दिलवा कर उनके छोटे—छोटे उद्यम स्थापित करवाए जिससे न केवल वह अपना घर परिवार चला रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवाओं को भी काम दे पा रहे हैं।
- गुणवत्ता के नए मानक स्थापित करने के लिए उन्नत प्रशिक्षण और कौशल के नए आयामों को सिखाने के लिए NSTI और NAPS जैसे केंद्रीय विभागों से अनेक इकाइयों में प्रशिक्षण दिलवाया। इसके फलस्वरूप बहुत—सी यूनिट्स की उत्पादकता बढ़ी है।
- कई इकाइयों की सब्सिडी लंबे समय से पेंडिंग थी, उनके

- लिए भी सरकार से वार्ता कर जारी करवाई।
- असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को ESI, EPF जैसी सामाजिक सुरक्षा नहीं प्राप्त होती। ऐसे लोगों के लिए कई बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के साथ समन्वय कर उनके परिवार का मुक्त स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उन्हें मुफ्त दवाएं प्रदान की गई।
- लघु उद्योग भारती परिवार ने पेड़ लगाने, जल और ऊर्जा बचाने जैसे राष्ट्र उपयोगी विषयों पर कार्य किया।
- Trade मार्जिन कैप पर लघु उद्योग भारती की फार्मा विंग ने प्रिंसिपल सेक्रटरी भारत सरकार के समष्क रिपेर्नस्टेशन में उत्तराखंड का नेत्रत्व किया।
- Revise शेड्यूल एम पर हरिद्वार में आयोजित कार्यशाला में भारत के मुख्य औषधि नियत्रक डॉ रघुवंषी जी के साथ लघु उद्योग भारती उत्तराखण्ड फार्मा आयाम के सदस्य।
- हरिद्वार जिले के तीन विधानसभा के विधायक व तत्कालीन संसद के साथ हरद्वार उद्योगिक क्षेत्रों की समस्यों के लिए उद्यमियों संघ बैठक।

आगामी वर्ष

- आगामी वर्ष में राष्ट्रीय सतर की उद्योगीइक पार्दशनी का आयोज न करना। उद्योगों के लिए कुशल मैनपावर के लिए उत्तराखण्ड में प्रदेश स्तर का कौशल विकास केन्द्र का निर्माण हेतो भूमि / भवन उपलब्ध करना
- नई व छोटे उद्यमियों के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए कार्यशाला का अयजोंन ।
- युवाओं में नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए कार्यशाला का अयजोंन व नए उद्यमों को स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डेटाबैंक क्रिएट करना । जिसे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में लोग उद्योग स्थापित कर सके ।
- प्रोजेक्ट वायबिलिटी स्टडी व इंडस्ट्री ऑटोमिशन के लियो एजेंसियों का चयन व एम ओ यू साइन करना ताकि एल यू बी के सदस्य इसका लाभ उढ़ा सके।





Laghu Udyog Bharati Haryama State



Shubh Adesh Mittal President systems108@yahoo.com







Important Programs & Achievements:

Regional Conclave of North India:

LUB's Haryana state successfully organized the Regional Conclave of North India on 26th March, 2025 at Ambala, bringing together more than 250 delegates from various northern States of Haryana, Punjab, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Delhi and Chandigarh. The event was graced by Shri Rao Narbir Singh, Minister for Industries & Commerce, Govt. of Haryana, who attended as the Chief Guest and encouraged industrialists to voice their concerns, assuring quick resolutions through efficient mechanisms like the single window system. The conclave featured exhibitions by CSIO Chandigarh,

showcasing innovative products with ready technical know-how for industry adoption. Delegates were benefitted with fruitful sessions on MSME financing, technology upgradation, export opportunities, and the 'Vocal for Local' initiative.

Regularisation of Non-confirming Industrial Area:

There are thousands of MSME units are situated at various cities in Haryana such as Faridabad, Panipat, Yamunanagar, Ambala which are termed as non-confirming industrial area. These units were setup long ago on agricultural land and later these areas became industrial area due to congregation of small industrial units in these areas. These units were registered at

उद्योग उत्थान विशेषांक

various government departments such as GST/ESI/PF etc. but government agencies are refusing to give industrial license to these units on the pretext of same being situated at non-confirming areas. LUB Haryana has been raising the issue with Government since last many years and the issue was raised at pre-budget consultation in the month of February,2025 and after continuous follow ups, the Haryana Government on August, 2025, has finally passed the legislation Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure-Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Amendment Act, 2025, allowing non confirming units to come together and avail the scheme to become a approved industrial unit.

Petition against Steep Rise in Electricity Charges:

The electricity board of Haryana has increased fixed electricity charges by 76% w.e.f April'2025 vide Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) order in Petition No. 66 & 67 of 2024-Annexure A "Schedule of Tariff and Charges" dated 28/03/2025. The steep rise in the fixed charges was exorbitant and burdensome for industries operating in the state. LUB Haryana protested this rise and met with various Government Officials and contacted other industrial associations of the state as well. Finally, LUB Haryana has along with other associations filed a Review Petition at Haryana Electricity Regulatory Commission for the the increases electricity charges.

Release of Faridabad & Ballabgarh Directory:

During the General Body Meeting at HUDA Convention Centre, Faridabad, the LUB Faridabad & Ballabgarh Directory (Udyog Nirdeshika) was formally released on 28th March, 2025. The publication aims to provide comprehensive information about member industries, serving as a valuable reference for networking, collaborations, and promotion of MSMEs in the region.

Policy & Electricity Issues Addressed with HERC:

LUB's Yamunanagar District Unit, along with the Bharwala-Panchkula and Karnal Units, organized a significant meeting during the visit of National Organizing Secretary Shri Prakash Chandra Ji on 14th July, 2025. The session was presided over by State



President Shri Shubh Adesh Mittal and attended by several dignitaries.

National Economic Group Meeting at LUB's Headquarters, Rewari:

A National Economic Group meeting was organized at LUB's Headquarters, Rewari, in association with Swadeshi Jagran Manch on 20th May 2025. The meeting focused on the role of MSMEs in making India self-reliant. Eminent dignitaries including Dr. Krishna Gopal Ji addressed the gathering and highlighted the importance of indigenous industry, technology, water conservation, renewable energy, and Industry 4.0 in strengthening India's economy. Distinguished participants were honored for their contributions. The program saw wide participation from industry leaders, academicians, and policymakers.

Celebrated 300th Birth Anniversary of Lokmata Ahilva Devi Holkar:

A seminar on the occasion of the 300th birth anniversary of Lokmata Ahilya Devi Holkar was organized at Rewari on 26th Feb. 2025. The program included a special exhibition and literature on the life of Maharani Ahilya Devi Holkar Ji. The keynote speaker was Shri Surendra Pal, Prant Pracharak, RSS. The event was presided over by Padma Shri Smt. Neema Malik, former Chairperson, of the Petroleum Conservation Research Association (PCRA). The chief guest was Dr. Anchal Jain, CEO PMI Electro Mobility Pvt. Ltd. The event was further graced by special guests Smt. Anupama Anjali Add.Dy. Commissioner, Rewari, Smt. Sweety Boora International Women Boxer, and Smt. Banarsi Devi Progressive Farmer.

Demonstration against Bangladesh:

LUB's Faridabad unit organized a Rosh Pradarshan (Protest Demonstration) at Central Park against the unjust actions and policies of Bangladesh impacting national and regional interests on 10th Dec. 2024. Members gathered to raise their voice in solidarity, highlighting concerns over cross-border issues and emphasizing the need for strong diplomatic and industrial safeguards.

International Yoga Day Celebration:

LUB's District Faridabad, in collaboration with Jan Sahyog Welfare Association, organized a special Yoga Camp on the occasion of International Yoga Day on 21st June, 2024. The event highlighted the theme "Do Yoga, Stay Healthy", emphasizing the importance of yoga in maintaining physical and mental well-being.

Cyclothon on World Environment Day:

LUB's Faridabad members joined hands with various local organizations to organize a Cyclothon on World Environment Day on 5th June, 2024. The event promoted eco-friendly practices, sustainable lifestyles, and the importance of reducing carbon emissions for a healthier planet.

Special Interaction at HERC:

LUB's Haryana in association with YJCC1 Yamunanagar, hosted Shri Mukesh Garg, Member, Haryana State Electricity Regulatory Commission, at Yamunanagar on 22nd May, 2024. The event provided an important platform for industries to raise electricity-related concerns. In addition to industrial issues, the meeting also highlighted the significance of voting, encouraging entrepreneurs and participants to recognize their civic duty and the role of each vote in strengthening democracy.

30"Foundation Day & Executive Meeting:

LUB's Faridabad and Ballabgarh unit, celebrated its 30th Foundation Day with a special event and the 3th Executive Meeting with the presence of Shri Gangashankar Mishra and Shri Vinod Kumar from RSS on 24th April 2024. The theme of the meeting was "Lokmat Paricharcha in the light of Democratic Festival", focusing on strengthening democratic values and active citizen participation.

Workshop on Delayed Payments to MSMEs:

LUB's Faridabad unit organized a workshop addressing the issue of delayed payments on 26th Feb. 2024. Shri B.R. Bhatia, Independent Director, HSIIDC, attended as Special Guest and shared valuable insights with entrepreneurs on resolving such disputes.



Expansion of Ambala Unit with Two New Chapters:

During 2023-24, LUB's Ambala Unit expanded by establishing two new units at Mandhor and Dhulkot. This addition reflected the growing trust of the local industrial community in LUB and enhanced its reach for addressing grassroots-level MSME concerns effectively.

Udhyami Samwad on Swavalambi Bharat Abhiyan

LUB's Faridabad members attended an Udyami Samwad in the presence of Shri Satish Kumar, Rashtriya Seh Sangathak-Swadeshi Jagran Manch on 4th Oct. 2023. Discussions centered on building a self-reliant India and empowering small entrepreneurs through the Swavalambi Bharat Abhiyan.

Workshop on National Apprenticeship Awareness:

LUB's members of Sonipat unit participated in a workshop on National Apprenticeship Awareness on 5th Sept. 2023. The program highlighted government schemes, incentives for industries, and the importance of apprenticeships in bridging the skill gap for MSMEs.

LUB Haryana State Executive Meet:

LUB's Haryana State unit organized its executive meeting at Sewa Saadhna evm Gram Vikas Kendra, Samalkha, Panipat on 17th August 2023. State leaders and unit representatives reviewed ongoing initiatives, strengthened coordination, and planned strategies for industrial outreach and advocacy.

Construction of Flood Prevention System for Ambala Cantt. Industrial Area:

Following devastating floods caused by the Tangri river in July 2023, which impacted nearly 130 units of Ambala Cantt. Industrial Area and caused losses of around ₹500 crore, LUB's Ambala Unit took proactive

उद्योग उत्थान विशेषांक

steps for prevention. Under the guidance of Minister Shri Anil Vij, members met with MD HSIIDC, Irrigation and Forest Departments, and Chief Minister Shri Naib Singh Saini. Their efforts resulted in HSIIDC floating a tender for the construction of an RCC concrete wall around the periphery of the Industrial Area, a significant victory towards flood protection.

• Tree Plantation Drive in Association with RWA: LUB's Faridabad in association with RWA Sector-16, organized a tree plantation drive on 22nd July, 2023. Members and residents actively participated in planting saplings, reinforcing the importance of green surroundings and environmental sustainability for healthier communities.

Awareness Camp on PMFME Scheme

Faridabad, LUB members participated in an awareness camp on the Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) scheme on 22nd June, 2023. The camp provided valuable insights on credit, technology, and skill development opportunities for food processing entrepreneurs.

Formal Inauguration of Ballabgarh Unit

The formal inauguration of the Ballabgarh Unit of LUB was held on 27th May 2023, where newly appointed members took oath to serve the mission of strengthening MSMEs.

Small Entrepreneurs' Conference held @ Rewari:

LUB's District Rewari, organized the Laghu Udyami Sammelan with the support of Canara Bank and Tivoli, which was graced by eminent dignitaries including Shri Pavan Jindal, Shri Rakesh Chand, and Shri Shubham Bhardwaj along with several industrialists, bankers, and entrepreneurs. The event aimed at promoting small industries and encouraging entrepreneurship in the region. Distinguished speakers addressed the gathering on opportunities and challenges for small businesses and highlighted the role of financial institutions in supporting industrial growth.

Haryana - Vision for next 2 years

- Membership Drive: Within next 2 years, we will have our units in all the industrial states/districts in Haryana and set a target of 2500 members by the year 2026.
- Building Skill Training Centre in 3

Districts: LUB Haryana has resolved to acquire land and construct Skill Centre in at least 3 districts in next 2 years. First one at Faridabad, Second at Karnal and Third at Yamuna Nagar.

Regularization of MSME Units situated in non-conforming areas:

LUB Haryana on a mission mode will monitor the progress of converting non-confirming units to confirming units in the State for the next 2 years and will ensure that the justice is delivered to these units.

Measures for countering GRAP (Pollution) restrictions for industries in NCR Region:

Every year due to GRAP regulations, industries in NCR Region faces lockouts. Electricity supplies are not regularly provided to the industries situated in NCR region, hence, industries face discontinued operations in the months of October to February every year. Diesel generators are also prohibited by the Green Tribunal during this period of the year, therefore, occurring huge losses to the industries.

LUB Haryana will has suggested to explore a mechanism like vehicle pollution check certificate to be introduced for generators run by industries, so that those confirming to the pollution standards can run during the GRAP measures/ above period. This will also give employment to many, as Certification Provider. The state unit will work towards implementation of such policy in next 1-2 years.

• Inland Container Depot on Dedicated Freight Corridor: The Dedicated Freight Corridor Railway Line runs through 70 Kms in the state of Haryana covering Yamuna Nagar District and there is demand from industry to establish an Inland Container Depot at Yamuna Nagar on this line.

LUB Haryana has set a target that it will co-ordinate with Railway Ministry/Central Government to establish an Inland Container Depot at Yamana Nagar within a next 2 years.

г	_	_	-		۱
	_1	E	-11		
	_	-	_	_	



Important Programs & Activities:

The last two years have been a journey of growth, struggle, and remarkable progress for LUB's Delhi State. What makes this journey special is that it reflects not just policies or programs, but the aspirations and determination of thousands of entrepreneurs who form the backbone of our city's economy. Together, we have taken steps that have not only solved long-standing issues but also opened doors to a stronger, more confident future for MSMEs in Delhi.

Removing Long-Standing Hurdles:

One of the proudest moments for all of us was when Delhi LUB's persistent efforts led to the removal of the MCD Factory Licence requirement. For years, entrepreneurs had been struggling with this unnecessary rule that added layers of paperwork and delays. It was a daily frustration for those already running their units in approved industrial areas. Finally, with consistent dialogue and representation, this demand was accepted by the government. The relief was immediate, and thousands of units operate with greater freedom and fewer compliance worries.

Alongside this, our continuous meetings with ministers, senior officials, and regulators have made sure that the real issues of small industries are heard. Whether it was concerns about GST, rigid BIS standards, environmental clearances, or even the sealing drives, Delhi LUB has been standing shoulder to shoulder with entrepreneurs, voicing their challenges, and pushing for practical solutions.



Bringing Innovation & Skills to the Ground:

We also know that for MSMEs to thrive, it's not enough to only fight for policy changes, innovation and skills are equally important. That's why our collaboration with the Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) was so meaningful. Through the program "100 Technologies 100 Days", small industries gained access to ready-to-use CSIR-developed technologies that could directly improve their production processes. At the same time, by working with National Skill Development Corporation (NSDC), Industrial Training Institutes (ITIs), and universities, we opened new pathways for skill development.

उद्योग उत्थान विशेषांक

- Workshop with IIM Mumbai gave MSMEs practical insights on fundraising, government schemes, GST strategies & digital marketing.
- An engaging session on Succession Planning EDII Ahmedabad prepared entrepreneurs to sustain their legacies through family business transitions.
- Internship Program with Zakir Husain College not only offered students hands-on exposure to MSMEs but also brought fresh energy into our ecosystem. Prizes and mentoring by senior members created a lasting impact on the next generation of entrepreneurs.

Building on this, we also initiated apprenticeship programs with NSIC, enabling young trainees to connect directly with industries and gain real-world exposure.

Delhi Teams visited ITIs, ensuring that training programs remain relevant and industry-linked. Taking entrepreneurship awareness, a step further, Team Delhi visited schools to deliver lectures on entrepreneurship, inspiring young minds to consider self-reliance and innovation as career paths. Many young people now see MSMEs not just as small factories, but as places where modern skills and opportunities for growth exist.

- Delhi State collaborated with NSDC to discuss two landmark initiatives for the Bawana Industrial Area:
- Skill Survey of MSMEs to map current and future manpower requirements.
- Setting up a Skill Development Centre, which will provide industry-relevant training and ensure MSMEs have access to skilled manpower.

This marks a turning point in aligning education and training directly with industry needs.

Learning, Sharing and Growing Together

Over these years, our workshops and seminars have become spaces where entrepreneurs can learn, exchange ideas, and prepare for the future. Topics like GeM Procurement, Intellectual Property Rights, Succession Planning, BIS Standards, and Sustainable Manufacturing may sound technical, but for our members, they became tools to secure their business and move forward with confidence.

In association with the Ministry of MSME, Govt. of

India, we successfully conducted a National Workshop on Procurement & Marketing Support Schemes (PMS). The workshop empowered entrepreneurs with knowledge of:

- GeM registration & Public Procurement
- E-commerce Opportunities through ONDC
- Export Marketing Strategies
- NSIC Schemes and Financial Assistance

We were also fortunate to host international visitors like the University of Pennsylvania team, whose interactions gave us fresh perspectives on how MSMEs around the world are tackling similar challenges. These exchanges reassured us that our small steps in Delhi are part of a much larger journey of industrial growth and innovation.

Building Awareness for Sustainability and Social Responsibility

We believe MSMEs have a responsibility not just towards business growth but also towards society and the environment. As part of our LIFE (Lifestyle for Environment) initiative, members pledged to switch off extra electricity every Saturday afternoon for two hours, a small yet powerful step towards sustainable energy usage.

Similarly, a massive plantation drive was organized, where over 1,000 saplings were planted, reinforcing our commitment to a greener future. These programs reflect our belief that entrepreneurship and social responsibility must go hand in hand.

Madipur Footwear Cluster - A Story of Resilience

When the Madipur cluster formally joined hands with LUB, it was struggling with multiple challenges. Today, it has grown into a family of more than 100 footwear entrepreneurs who stand stronger than ever. Together, with the support of Delhi LUB, they have achieved:

- Relief from BIS regulations for units with turnover up to ₹50 crore.
- A forward-looking MoU with Atal Innovation Centre to bring in new ideas and technologies for digital marketing and creation of an e-commerce platform.
- Protection against sealing actions that threatened livelihoods.

- Access to Household Factory Licences, giving legal recognition and peace of mind.
- Ongoing efforts to secure relocation into formal industrial areas at subsidized rates, ensuring a more sustainable future.

The Madipur Cluster today is more than just a group of factories, it is a living example of how unity, guidance, and persistence can transform challenges into milestones. It gives hope not just to Delhi, but to clusters across India.

Initiating Udyog Nagar's Transformation into a Green Smart Cluster

One of the most significant milestones in recent years has been the initiation of the Udyog Nagar Green Smart Cluster Project, which will directly benefit over 275 MSMEs and serve as a benchmark for industrial modernization across Delhi.

The project is designed around sustainable and future-ready growth, with interventions such as:

- Common rainwater harvesting and zero-liquid discharge systems
- Solar-powered infrastructure and rooftop solar installations for units
- Centralized ESG data systems with Rail Tel as a technical partner
- State-of-the-art fire prevention and cluster safety networks
- A dedicated Skill Development Centre in partnership with NSDC
- Adoption of energy-efficient machinery and technology upgrades at the unit level

With all stakeholders aligned, from industry associations and financing institutions to technical partners and entrepreneurs, the Udyog Nagar Green Smart Cluster project is poised to become a Light House Model for all Industrial Clusters in Delhi, demonstrating how MSMEs can achieve sustainability, digitalization, and competitiveness in tandem.

Looking Ahead with Confidence:

 As we move forward, our vision is both ambitious and grounded. We are preparing for a large membership drive to bring more entrepreneurs into the LUB network, because we know that our strength lies in our collective voice.

- In Madipur, we plan to establish a dedicated testing laboratory within the cluster, enabling local manufacturers to obtain the necessary certifications at their doorstep.
- In collaboration with CSIR-NIScPR, we are working to extend technology and entrepreneurship support to rural areas, helping artisans and small-town manufacturers connect with bigger markets.
- Most importantly, the coming year will mark a historic milestone for Delhi LUB, we are preparing to host the biggest exhibition ever organized in LUB's history, a pan-India showcase of MSME strength, innovation, and resilience. This megaevent will not only highlight the diversity and capabilities of our entrepreneurs but also create unparalleled opportunities for networking, collaborations, and business growth at a national level.

Our agenda will continue to focus on improving the ease of doing business, simplifying compliance, upgrading industrial infrastructure, rationalizing electricity tariffs, and ensuring GST processes become smoother.

A Shared Mission

Looking back at the last two years, what stands out is not just the policies that changed or the clusters that were strengthened, but the collective spirit of Delhi's entrepreneurs. Every achievement has been the result of shared effort, of entrepreneurs who refused to give up, of teams that worked tirelessly, and of an association that truly belongs to its members.

Delhi Laghu Udyog Bharati's mission is clear: to empower small industries, nurture innovation, and create a space where entrepreneurship can flourish without unnecessary hurdles. With unity and determination, we are building not just a stronger industrial sector for Delhi, but also contributing to the vision of a self-reliant India.







विशेष उपलब्धियाँ (12 अप्रैल, 2025 मुम्बई बैठक तक)

राजस्थान प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सिक्रयता और उपलब्धियों में सदैव अग्रणी रहा है। प्रदेश में तीन संभाग — जयपुर, जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ कार्यरत हैं जिनके अंतर्गत कुल 173 पूर्ण इकाइयाँ (सामान्य इकाई 152 व महिला इकाई 21) और 12151 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। इकाइयों और सदस्य संख्या में राजस्थान का यह वर्चस्व लघु उद्योग भारती के संगठनात्मक बल और समर्पण का परिणाम है। इस उपलब्धि का श्रेय शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन एवं प्रदेश, संभाग, इकाई पदाधिकारियों और समर्पित कार्यकर्ताओं को जाता है। सभी ने उद्योगों के हितार्थ समस्याओं का अध्ययन कर निरंतर समाधान हेतु सरकार और प्रशासन के समक्ष प्रभावी सुझाव रखे, परिणामस्वरूप अनेक कार्य संपन्न हुए और संगठन का विस्तार होता चला गया।

उद्योग संरक्षण व नीतिगत निर्णय-

- प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग संरक्षण आयातित कच्चे माल पर केंद्र सरकार से एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगवाकर स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया।
- भूजल दोहन सरलीकरण- केन्द्र सरकार को सुझाब देकर
 10,000 लीटर प्रतिदिन तक जल दोहन करने वाले उद्योगों को अनुमति लेने से मुक्त कर केवल सूचना देने की प्रक्रिया तक सीमित किया गया। राजस्थान सरकार सहित कई राज्य सरकारों ने अलग से राज्य भू—जल बोर्ड का गठन किया हैं।
- ईट भट्टा उद्योग- राजस्थान सरकार को सुझाव देकर वर्तमान तकनीक को जिग-जैक तकनीक में बदलने की समय सीमा 16 माह बढ़वाई गई, जिससे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित अनेक जिलों के उद्योगों को राहत मिली।
- औद्योगिक भूमि कर समाप्त- राजस्थान सरकार को सुझाव देकर 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि रखने वाले उद्यमियों पर रू2 प्रति वर्ग मीटर लगने वाला कर हटवाया।
- औद्योगिक भू-रूपांतरण में छूट- राजस्थान सरकार को सुझाव देकर रीको औद्योगिक क्षेत्र से लगती 1 किमी परिधि में औद्योगिक भूमि रूपांतरण के लिए एनओसी लेने की अनिवार्यता समाप्त कर छूट प्रदान की गई।

- पर्यावरण स्वीकृति में सरलता- राजस्थान सरकार को सुझाव देकर 2 लाख लीटर प्रतिदिन तक अपशिष्ट जल निकालने वाले उद्योगों को अब क्षेत्रीय अधिकारी स्तर पर ही एनओसी प्राप्त करने की सुविधा दी गई। इससे टेक्सटाइल इकाइयों को विशेष राहत मिली।
- ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था- राजस्थान सरकार से संवाद स्थापित करने पर अब भूमि की रिजस्ट्री होते ही जमाबंदी में म्यूटेशन की ऑनलाइन प्रविष्टि स्वतः हो जाती है।
- सौर ऊर्जा प्रोत्साहन- राजस्थान सरकार द्वारा पहले 500 किलोवाट तक का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की अनुमति थी लेकिन संगठन के प्रयासों से अब राजस्थान सरकार ने 1000 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है।
- कैप्टिव पावर सीमा वृद्धि राजस्थान सरकार द्वारा पहले उद्योग अपनी जरूरत पूर्ति के लिए अपने विद्युत कनेक्शन की क्षमता से 100: कैप्टिव पावर प्लांट लगा सकते थे। लेकिन संगठन के प्रयासों से उसे बढ़ाकर अब 200: तक कर दिया गया है।
- खनिज उद्योगों को राहत- खनन से जुड़े उद्योगों के टीपी (Transit Permit) संबंधी समस्या बहुत बड़ी थी जिससे संगठन ने मुक्ति दिलवाई।
- पाली, बालोतरा व जोधपुर क्षेत्र के औद्योगिक में अपशिष्ट जल की बड़ी समस्या हैं। इसके समाधान के लिए राजस्थान सरकार से निरतंर सम्पर्क कर सुझाव देने पर इस औद्योगिक अपशिष्ट जल को ट्रीट कर पाइपलाइन द्वारा गुजरात के कच्छ के समुद्र में डाले जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है।

सरकार का नीति-निर्माण में सहयोग-



- लघु उद्योग भारती के सुझावों पर राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़ी अनेक नई नीतियाँ घोषित कीं-
- ऊर्जा विभाग- इन्ट्रीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी (Integrated Clean Energy Policy)
- खनिज विभाग- नई खनिज नीति एवं एम-सँड (M-Sand Policy)
- उद्योग विभाग- एमएसएमई पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशनल पॉलिसी, वन डिस्ट्रिक-वन प्रोडेक्ट पॉलिसी, कलस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी, रिप्स-2024 पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी।
- 4. आईटी विभाग- AVGC XR Policy (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics & Extended Reality)
- 5. पर्यटनविभाग: Tourism Unit Policy

कौशल विकास प्रशिक्षण एवं कार्यालय भवन

- जयपुर व जोधपुर में कौशल विकास केंद्र भवन का निर्माण एवं संचालन।
- बालोतरा में प्रथम इकाई स्तर पर कार्यालय भवन का निर्माण और लोकार्पण।
- वर्तमान में आठ स्थानों जयपुर, अलवर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बीकानेर, भीलवाड़ा और श्रीडूंगरगढ़ में कौशल विकास केंद्र संचालित हैं।
- अजमेर में भवन का निर्माण कार्य जारी है।
- प्रदेश के नौ नए स्थानों पर कौशल विकास केंद्र निर्माण हेतु भूखंड आवंटन की प्रक्रिया जारी हैं — अलवर, भिवाड़ी, बीकानेर, पाली, जालौर, बालोतरा, भीलवाड़ा, कोटा व ब्यावर।

मेले, प्रदर्शनियां एवं निवेश प्रोत्साहन

1. इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-

- भीलवाड़ा और उदयपुर में सफल आयोजन।
- भिवाडी (जयपुर संभाग) में आगामी IIF का आयोजन
 19-21 सितम्बर, 2025 को होगा।

2. महिला उद्यमिता प्रोत्साहन-

 महिला इकाइयों द्वारा स्वयंसिद्धा मेले / प्रदर्शनियां (होली, दीपावली, राखी आदि त्योहारों से पूर्व) का आयोजन किया जाता हैं। विगत 2 वर्षों में लगभग 40 मेले आयोजित किये हैं।

3. इंडिया स्टोन मार्ट 2026-

राजस्थान सरकार द्वारा अन्तराष्ट्रीय स्तर की पत्थर उद्योग प्रदर्शनी प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2026 के लिए इस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के आयोजन की जिम्मेदारी लघु उद्योग भारती को दी गई हैं। इसे सफल बनाने हेतु संगठन की विशेष टीम देश व विदेश में क्रेता — विक्रेताओं से संपर्क कर इस प्रदर्शनी में आने का आह्वान कर रही हैं। इसके लिए अब तक प्रदेश के अनेक स्टोन मार्केट जैसे किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, कोटा आदि में कार्यक्रम कर चुकी हैं। इसी प्रकार स्टोन व्यवसाय के प्रमुख 6 देशों की यात्रा भी कर चुकी है।

पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव

जोधपुर में राजस्थान सरकार की सहभागिता से प्रतिवर्ष होने वाले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तिशिल्प उत्सव—2024 एवं 2025 का सफल आयोजन लघु उद्योग भारती ने किया। इसमें लगभग 800 स्टॉल और प्रतिदिन एक लाख से अधिक आगंतुकों की उपस्थिति रही। संगठन ने पूर्व आयोजकों की तुलना में लाभ अर्जित कर राज्य सरकार को सौंपा। इस सफलता से प्रभावित होकर राजस्थान सरकार ने इस उत्सव की 2029 तक आयोजन की जिम्मेदारी लघु उद्योग भारती को दी।

5. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024

जिला प्रशासन के साथ मिलकर जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट मीट का सफल आयोजन लघु उद्योग भारती की सभी जिला स्तरीय स्थानीय इकाइयों के सहयोग से की गई।

-एमएसएमई कॉन्क्लेब (जयपुर, 11 दिसंबर, 2024) राजस्थान सरकार के प्रदेश स्तरीय इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी लघु उद्योग भारती को दी गई थी। हमारे संगठन ने प्रदेश स्तर पर अपने नेटवर्क के प्रयासों से 5000 से अधिक उद्यमियों की भागीदारी के साथ यह आयोजन संपन्न किया।

सीएसआईआर से तकनीकी स्थानांतरण-

वैज्ञानिक एवं आँद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और लघु उद्योग भारती के एमओयू के अंतर्गत प्रदेश के उद्यमियों ने भी अनेक तकनीक ट्रांसफर की।

संगठनात्मक गतिविधियाँ-

 संगठन की रीति—नीति की जानकारी देने व कार्यकर्ता विकास हेतु तीनों संभागों में अलग अलग अभ्यास—वर्ग एवं उद्यमी—सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता हैं।

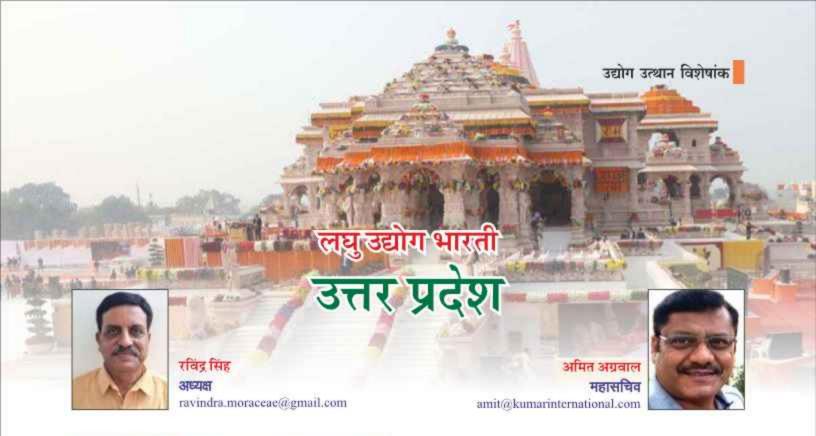


 औद्योगिक समस्याओं के समाधान हेतु संगठन के पदाधिकारियों की छः विभागीय समितियां (उद्योग, रीको, विद्युत, पर्यावरण, जीएसटी व वित्त, श्रमं) बनाकर इकाई और संभाग से प्राप्त उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता हैं। इसी प्रकार 22 उत्पाद समूह गठित कर समस्या समाधान का प्रयास किया जाता है।

राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व:

- रेलवे मंडल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति ।
- प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय औद्योगिक विवाद निवारण की सभी समितियों में संगठन के दो—दो प्रतिनिधि।
- राजस्थान से राष्ट्रीय स्तर पर दिये जाने वाले नेशनल एमएसएमई अवार्ड हेतु उद्योगों के चयन में लगातार 2023 और 2024 में प्रतिनिधित्व किया हैं। इसमें
- कुल 35 पुरस्कार— मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंटरप्राइजेज और स्पेशल कैटेगरी में दिये जाते हैं।
- प्रथम पुरस्कार रू3 लाख, द्वितीय रू2 लाख, तृतीय रू
 1 लाख एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

लघु उद्योग भारती, राजस्थान ने न केवल संगठनात्मक मजबूती दिखाई है बल्कि उद्योगों के संरक्षण, नीति निर्माण और उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी ऐतिहासिक योगदान दिया है। बीते वर्षों में प्रदेश स्तर पर लिए गए निर्णयों और उपलब्धियों ने राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। आने वाले समय में भी संगठन उद्योगों की समस्याओं के समाधान, नई संभावनाओं के विकास और उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।





सांगठनिक ढांचा एवं विस्तार-

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से विकासशील प्रदेश है। सरकार के द्वारा प्रदेश में उद्योग प्रोत्साहन व नये पूंजी निवेश हेतु विशिष्ट प्रयास किये जा रहे हैं। उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न नीतियों के प्रतिपादन के साथ अवस्थापना सुविधाओं के लिये परियोजनाओं को चिन्हित कर कार्य किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं जिनमें लघु उद्योग भारती 6 संभागों— अवध, कानपुर, मेरढ, काशी, गोरखपुर व ब्रज के साथ 70 जिलों में सक्रिय हैं। वर्तमान में 111 इकाइयों के साथ 6200 सदस्य जुड़े हुए हैं। वर्तमान में लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर व आगरा में पूर्ण महिला इकाईयां हैं, तथा अन्य संभागों में भी महिला इकाई के गठन के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर उत्पाद समूह व विभिन्न आयामों का गठन किया गया है जिसको जिला स्तर तक संबंध करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

महत्वपूर्ण गतिविधियां एवं कार्यक्रम-

- उद्योगों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत सोलर एनर्जी के प्रयोग के प्रोत्साहन के विषय में इकाई स्तर पर सेमिनार का आयोजन किया गया तथा प्रदेश सरकार से उद्योगों में सोलर प्लांट स्थापित किये जाने हेतु अनुदान की मांग की गई।
- 2 अगस्त, 2025 को अयोध्या में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक व औद्योगिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- लखनऊ इकाई ने 21 अगस्त, 2025 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये वित्तीय सहायता विषय पर बैंक जोनल हेड व प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित की।
- 22 अगस्त, 2025 को झांसी में औद्योगिक सेमिनार का आयोजन किया गया।
- 6 सितंबर, 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), भारत सरकार के संस्थान डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर के साथ एमएसएमई कॉन्क्लेव लखनऊ में आयोजित किया गया।
- संगठन ने सामाजिक व अन्य सेवा कार्यों में वृक्षारोपण, हेल्थ कैम्प, टीबी मरीजों की देखभाल व पोषण, गौशाला

उद्योग उत्थान विशेषांक

का निर्माण व गरीब बच्चों की शिक्षा को एक वर्ष के लिये अंगीकृत किये जाने जैसे कार्य भी प्रदेश की इकाइयों ने किये हैं।

- वाराणसी में अखिल भारतीय कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई।
- आगरा में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में औद्योगिक महासम्मेलन आयोजित किया गया।
- वर्ष 2024 में मेरठ, फतेहपुर, शाहजहांपुर, आगरा, लखनऊ शहरों में औद्योगिक सेमिनार आयोजित किये गए।

विशोष उपलब्धियां-

- CSIR के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के संबंध में 28 अगस्त, 2024 को लखनऊ में बैठक व संस्थान भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें प्रदेश के 40 उद्यमियों द्वारा सहभागिता की गयी।
- 4 सितम्बर, 2024 को रुड़की भ्रमण में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 80 उद्यमियों ने सहभागिता की।
- सरकार के सहयोग से संगठन ने उद्योगों के संरक्षण और उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में निरंतर कार्य किया है। प्रदेश की 18 मंडलीय फेसिलिटेशन काउंसिल में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित हैं।
- उद्योगों को संगठन के प्रयास से नेट मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
- लघु उद्योग भारती के प्रयासों से उद्योगों के लिये FAR बढ़ाया जाना व बिलिंडग कंस्ट्रक्शन बाईलाज का प्रतिपादन कराया गया।
- नवीन उद्योगों की स्थापना, स्टार्टअप, स्थापित उद्योगों को वित्तीय सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) के साथ प्रदेश स्तर पर एमओयू किया

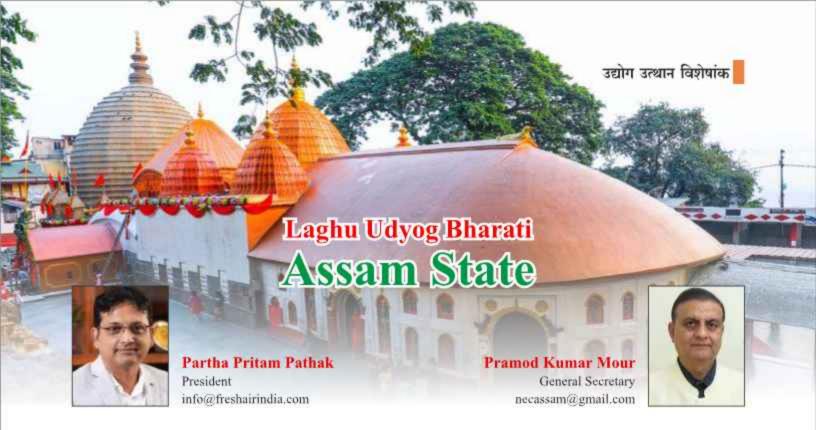
- गया। सिडबी ने संगठन के कार्यालयों में बिजनेस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति भी की है।
- नवयुवकों को कौशल विकास, उद्यमिता एवं स्वरोजगार के लिये प्रोत्साहन हेतु सहारनपुर इकाई द्वारा इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी रुड़की व ग्रेटर नोएडा इकाई द्वारा शारदा यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।
- 12 जनवरी, 2025 को लखनऊ में प्रादेशिक सम्मेलन (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड) व उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें उत्तराखंड के साथ प्रदेश के 800 उद्यमियों ने भाग लिया।

भविष्य की दृष्टि

वर्ष 2025-27 के लिये प्रदेश की नयी कार्यकारिणी का गठन हो गया है इसके साथ ही आगामी वर्षों की कार्ययोजना निर्धारित की गयी हैं-

- संगठन में आपसी समन्वय और परामर्श के साथ उद्योगों की समस्याओं का आकलन कर उनके निराकरण हेतु प्रयास करना।
- आगामी वर्षों में संगठन के विस्तार के साथ जिला स्तरीय इकाईयों को सक्रिय और क्रियाशील करते हुए जागरूक करना है।
- संगठन को कृषि आधारित व अन्य ग्रामीण उद्योगों एवं हस्तशिल्पकारों से जुड़ाव का भी लक्ष्य है।
- उद्यमिता प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के विश्वविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोंजी आदि तकनीकी संस्थानों को संगठन के साथ जोड़ते हुये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उत्पादों की गुणवत्ता पर भी कार्य किया जाना है।
- प्रदेश के जिन क्षेत्रों में औद्योगिक भूमि का अभाव है उनमें सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना।







Important Activities & Programs:

- A cultural program was organised on 3rd May, 2025 to honour Shri Nukaga Fukushiro, Speaker of the House of Representatives, Japan. The event celebrated Indo-Japanese friendship and was marked by vibrant cultural performances showcasing the rich heritage of Assam.
- The Sthapna Diwas of the organisation was celebrated on 24th April, 2025 at Guwahati. Distinguished guests included Shri Lakshman S-IAS, Dr. B. Kalyan Chakravarthy-IAS, and Dr. Arup Kumar Mishra, who shared insightful perspectives on sustainable development and institutional growth.
- A workshop on the Plastic Waste Management Rules and Single-Use Plastic Ban was held on 24th

- April, 2025 jointly organised by LUB Purvottar Prant and Pollution Control Board Assam (PCBA). The event was part of PCBA's Golden Jubilee Celebration and aimed at spreading awareness and promoting best practices in waste management.
- World Environment Day Celebration on 5th June 2025, was observed at Fresh Air, Panikhaiti with active community participation.
 - Environmentalists and dignitaries addressed the gathering, urging collective action for environmental conservation.
- A Regional Workshop on Ease of Doing Business & Timely Payments to MSMEs was conducted on 25th April, 2025 at the Multi-purpose Cultural Complex, Guwahati. Officials and industry representatives discussed policy improvements and challenges faced by MSMEs.



उद्योग उत्थान विशेषांक



- 'Jal Hai to Jeevan Hai' an Awareness Program was organised by LUB to spread awareness about water conservation and the vital importance of water resources. It emphasized sustainable water management practices across sectors.
- The formation ceremony of LUB Purvottar Prant New Karyakarta and Mahila Samiti was conducted on 13th June, 2025. The event aimed to strengthen organisational structure and empower women leadership in the region.

Achievements:

In February, participated in Advantage Assam 2.0



as an MSME partner to showcase member businesses.

- Team LUB participated in a MoU Exchange Ceremony at Srimanta Sankardev Kalakshetra with Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, strengthening industrial and developmental cooperation on 18th May, 2025.
- LUB's members attended the Capacity Building Program on Energy Efficiency with APDCL and GreenTree Global under BEE's initiative, focusing

- on industrial energy optimization, motor efficiency, and cost savings on 17th June, 2025.
- LUB's Jorhat unit organized a
 Tally Seminar and Workshop with
 experts, providing practical
 insights into accounting, latest
 Tally features, and professional
 skill development on 7th August,
 2025.

Future Agenda

IIF 2025: The 13th India
Industrial Fair-Udyam-2025 will
be held from 30th Oct. to 2th Nov. at Khanapara
Field, Guwahati, under the Patronage of the Chief
Minister Assam & Industry Minister with senior
central cabinet ministers expected to attend. The
fair will feature 480+ stalls, 50,000+ visitors, and
B2B/B2C/B2G meetings.

Industry-Academia Collaboration:

LUB plans tie-ups with IIT Guwahati for technology transfer, innovation, and skill development to strengthen MSMEs and local industries.



 Gram Silpi Empowerment: LUB will focus on upskilling traditional artisans (gramsilpis), providing dedicated marketplaces, enhancing productivity, craftsmanship, and income, while also promoting sustainable practices and women leadership through Mahila Samiti initiatives.





Important Activities & Programs:

LUB's Gujarat Pradesh has successfully organized a wide range of impactful programs, meetings, and exhibitions across the state over the past two years.

Regular monthly meetings at Unit & District levels & weekly meetings at the state office (Karnavati). In addition, Pravas (outreach visits) and membership drives were actively undertaken by designated committee members to strengthen organizational reach and connect with grassroots stakeholders.

Furthermore, regular interactions, and representations were held with the Chief Minister, State Ministers, and senior government officials at the Secretary level. These efforts have resulted in several amicable and constructive outcomes for the MSME community.

Major Conferences & Meetings:

- Regional Meeting, Vadodara (Sept. 2024)
 Attended by 400 members with CM Shri
 Bhupendrabhai Patel, focusing on Panch
 Parivartan and MSME Policy Guidance.
- Pradesh Abhyas Varg, Palanpur (Nov. 2024) -Two-day study camp with 120 participants highlighting Eight Pillars Concept and LUB-Agro University R&D collaboration.
- Executive Committee Meetings (Valsad, Kathwada, Mani Nagar, 2025) - Over 500 members participated, with focus on Sangh coordination and Panch Parivartan.

Exhibitions & Fairs:

- India Industrial Fair (IIF-2025) at Rajkot (February-2025)- 200 exhibitors, 75,000+ visitors, Indian Railways & Defence stalls, seminars on GeM and procurement.
- Kalanubhaya Exhibition at Ahmedabad (March-

April-2025)-Women entrepreneurs showcased products across 40 stalls.

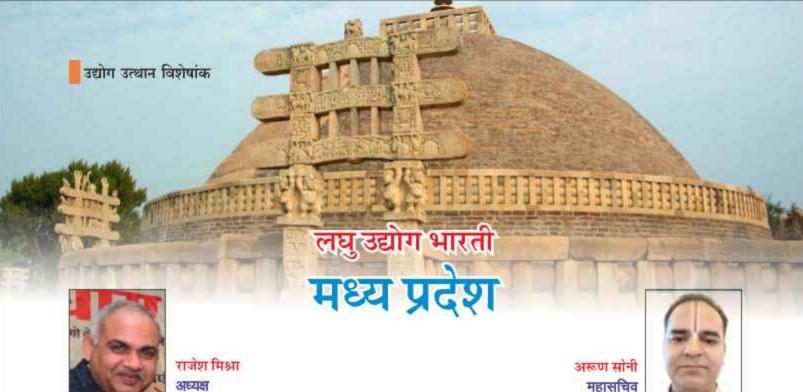
 Defence Sector Seminar & Exhibition, Gandhinagar (August-2025) - 250 participants, with DRDO, HAL, TATA, L&T showcasing Atmanirbhar Bharat opportunities in defence production.

Special Programs & Outreach:

- Foundation Day (Jan 2025) Celebrated across 27 districts with social service activities including blood donation, tree plantation, and health camps.
- Chintan Goshthi & Gyan Satra (Feb-March-2025) - Leadership guidance for 100+ office bearers on organizational growth and employment generation.
- Sneh Milan (Bharuch, January-2025) 550 members attended the fellowship program.
- FDA Rules Awareness Seminar (Vapi, Mar 2025)
 100+ industries guided on Schedule-M compliance and government incentive schemes.
- Vadodara Vibhag Karyakarta Prashikshan Varg (August-2025) - 45 participants trained; launch of "GST Clinic" for resolving tax-related queries.

Key Impact

- Participation of over 1,20,000 people including MSME owners, industrialists, academicians, women entrepreneurs & policymakers.
- Strengthened collaboration with government departments, universities, and defense sector organizations.
- Enhanced policy awareness, organizational training, MSME networking, and grassroots leadership across Gujarat.





aryawart yantriky@yahoo.com

प्रमुख उपलब्धियाँ (2023-25)

- RBI संशोधन— CGTMSE योजना में Foreclosure Charge कम, MSME लोन प्रकरण अब ऑनलाइन पोर्टल से।
- 9 अप्रैल 2023ः संगठन के इतिहास में पहली बार 11 इकाइयों का गठन।
- प्रदेश सरकार अधिसूचना नई औद्योगिक इकाइयों में 3 साल तक निरीक्षण से छूट।
- गृह विभाग निर्णय धारा 304 (105 BNS) के स्थान पर 304 । (106 BNS) लागू।
- नई MSME नीति सोलर सब्सिडी का प्रावधान।
- सितम्बर 2023— 1 करोड़ से अधिक निवेश वाले OIL उद्योग MSME नीति में शामिल।
- दिसम्बर 2023— 20 शासकीय ITI में 100 कार्यकर्ता नामांकित।
- कोरोना काल राहत— सरकारी सप्लाई में देरी पर

arun.sonishrijee@gmail.com

पेनाल्टी माफी, अवधि 31 मार्च 2024 तक।

- मार्च 2024 निवेश अनुदान प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेत् निर्देश।
- जुलाई 2024— WDRA प्रतिभूति राशि 3% से घटाकर 1%।
- DBT सुविधा— निवेश अनुदान राशि अब सीधे बैंक खातों में।
- उद्योग संवर्धन बोर्ड- प्रत्येक जिले में गठन एवं अनिवार्य बैठक का आदेश।
- 2100 करोड सब्सिडी— DBT के माध्यम से जारी।
- FIRE NOC राहत— दंड अधिरोपण में 31 दिसम्बर 2025 तक छूट।
- जून 2025- प्रदेश के बाहर से आने वाली तुअर पर मंडी टैक्स छूट, दाल मिलों को राहत।

संगठन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- MSEFC Award 2024 मध्यप्रदेश फैसिलिटेशन काउंसिल को सर्वाधिक प्रकरण निपटाने हेतु सम्मान।
- ताइवान से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ आयात—निर्यात पर लघु उद्योग भारती प्रदेश कार्यालय में परिचर्चा संपन्न कराई।
- लघु उद्योग भारती महिला इकाई की सदस्यों ने रक्षाबंधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को रक्षा—सूत्र बांधा।

- 06 अगस्त, 2024— देवास में म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं MSME मंत्री श्री चैतन्य कश्यप के साथ अखिल भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में ऑल इंडिया इंडिस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु प्रदेश और बाहर से 4000 से अधिक लोगों ने रिजिस्ट्रेशन किया था।
- 25 अप्रैल MSME विभाग द्वारा रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत कोयंबदूर एवं तिरुपुर उद्यमियों को इंडस्ट्रियल विजिट करवाई गई।
- 29 अप्रैल-भोपाल में स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय "LEAP' ई-पोर्टल लॉनिंचग कार्यक्रम में 383 उद्यमियों की उपस्थित रही। इस अवसर पर सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डैडम मंत्री श्री चैतन्य कश्यप एवं कौशल विकास मंत्री श्री गोतम टेटवाल सहित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ताराचंद गोयल की उपस्थिति रही।
- 27 जून रतलाम में मध्यप्रदेश शासन द्वारा रीजनल कॉन्क्लेव के आयोजन में इंडस्ट्रियल पार्टनर के रूप में लघु उद्योग भारती को प्रमुख स्थान दिया गया।
- लघु उद्योग भारती द्वारा एमएसएमई विभाग के साथ मिलकर अप्रैल से जुलाई माह के बीच 51 कार्यशालाएं संपन्न कराई गई जिसमें 3547 पुरुष 1525 महिला उद्यमियों को एमएसएमई पॉलिसी, ZED, LEAN जैसे विषयों की जानकारी से लाभान्वित किया गया।
- MSME मंत्रालय की PMS योजना के अंतर्गत देवास में 05-07 अगस्त, 2024 स्वयंसिद्धा प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें लगभग 50 स्टाल लगाए गए एवं तीन दिवस में 26,50,470/- रुपए की बिक्री एवं आर्डर महिलाओ

को प्राप्त हुए।

 MSME मंत्रालय की PMS योजना के अंतर्गत इंदौर में 24-27 जुलाई, 2025 स्वयंसिद्धा प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें लगभग 80 स्टाल लगाए गए। इस अवधि में 36,35,180 / - रुपए की बिक्री एवं आर्डर प्राप्त हए।

संगठन की वर्ष 2025-27 के लिए योजना



- संगठन प्रदेश की आईटीआई (ITI) के विद्यार्थियों को उद्योगों के साथ जोड़ने पर कार्य करेगा जिससे विद्याथियों को रोजगार प्राप्त हो सके एवं उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी।
- प्रदेश के 55 जिलों में महिला कार्य को बढ़ाना एवं महिला इकाई का विस्तार।
- मध्यप्रदेश शासन एवं विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर सम्पूर्ण प्रदेश में ZED, LEAN, BIS, वेंडर डेवलपमेंट आदि उपयोगी कार्यशालाओं की श्रृंखला का विस्तार करना।
- प्रदेश के सभी सदस्यों को नवीन टेक्नोलॉजी से जोड़ना और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद समूह को सशक्त बनाना।





महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं गतिविधियां (2023-25)-



- महिला इकाई का गठन- लघु उद्योग भारती, झारखण्ड द्वारा महिला इकाई का गठन राज्यपाल श्री सी.पी। राधाकृष्णन एवं पूर्व राज्यसभा सांसद श्री महेश पोद्दार की उपस्थिति में 2 जून, 2023 को किया गया।
- ग्राम शिल्पी ग्राम उद्योग/स्वरोजगार- स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत लघु उद्योग भारती, झारखण्ड प्रदेश अवस्थित सभी इकाइयां स्वदेशी जागरण मंच के साथ उनके कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है।
- उद्यमिता विकास- जमशेदपुर में ऑटो क्लस्टर के माध्यम से जनजातीय एवं अन्य युवाओं को विभिन्न वस्तुओं के निर्माण हेतु प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था प्रदान कर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है।

उल्लेखनीय कार्य-

 झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा की गई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में अप्रत्याशित वृद्धि के विरूद्ध

- झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रांची में 25 मार्च, 2025 को संगठन की ओर से तार्किक विरोध प्रस्तुत किया गया।
- पीएसयू को आपूर्ति आदेश में दिये गये एलडी क्लॉज़ के प्रावधान का सभी उपक्रम एमएसएमई के विरूद्ध नाजायज फायदा उठाते हैं। जिसके विरूद्ध संगठन ने केंद्र के एमएसएमई विभाग के मंत्री को भी पत्र लिखा है।
- आपूर्ति किये गये सामानों का विलंबित भुगतान—केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा तो अब एमएसएमई के बिलों का भुगतान निर्धारित समय पर किया जा रहा है। सिर्फ एलडी क्लॉज का दुरुपयोग कर ही भुगतान में विलंब किया जा रहा है। परंतु राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अभी भी आपूर्ति आदेश के बिलों के भुगतान में असाधारण विलंब किया जा रहा है।
- राज्य की नगरपालिकाओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाईयों से होल्डिंग टैक्स वसूलने हेतु समाचार—पत्रों में समाचार प्रकाशित कर उद्यमियों को तनाय—ग्रस्त करने की प्रवृत्ति पर संगठन ने संज्ञान लिया। औद्योगिक इकाइयां जियाडा को भूमि का लगान, किरायाएयं मरम्मत, रखरखाव का सारा निर्धारित वार्षिक शुल्क नियमित रूप से चुकाती है।
- सेवा कार्य— प्रदेश की सभी इकाइयां अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं मातृ संगढन से जुड़े अन्य अनुषांगिक संस्थाओं के साथ मिलकर विकलांगों एवं अन्य जनजातीय तथा असहाय लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं।



- 30 नवम्बर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक कुल प्रदेश में 48 नये सदस्य बनाये गये ।
- विश्वकर्मा पूजा प्रदेश के सभी औद्योगिक परिसरों में धूमधाम से मनाई गई। लगभग 500 से अधिक कारखानों में विश्वकर्मा पूजा संपन्न हुई।
- जिला स्तरीय अभ्यास वर्ग 13 नवंबर, 2024 को रांची तथा 2 जनवरी, 2025 को जमशेदपुर में आयोजित किया गया।
- उत्पाद समूह का संयोजक इंजी. श्री कृष्ण नंदन सिंह को नियुक्त किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में बांस से बने उत्पादों के लिए बाजार लघु उद्योग भारती के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। टीम के अन्य सदस्यों में श्री मनोज बागडी, श्री अनूप अग्रवाल, श्री दशरथ उपाध्याय तथा श्री सुबोध सिंह हैं।
- उद्यमिता विकास के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में तीर-धनुष बड़े पैमाने पर बनाये जाते हैं जिसकी अत्यधिक मांग रहती हैं। कच्चा माल बांस और रस्सी इत्यादि उपलब्ध कराके दुमका और पश्चिम सिंहभूम के जनजातीय लोगों को रोजगार में लगाया गया। करीब 50-60 जनजातीय युवकों को आजीविका चलाने में सहायता दी गई और वे इस कार्य को सफलतापूर्वक चला रहे हैं।
- उद्यमिता विकास के अंतर्गत ही आदित्यपुर में एक क्लस्टर के माध्यम से प्रतिमाह 30 युवकों को एयर कंडीशनर रिपेयरिंग का कोर्स कराया जाता है और वे सभी युवक जनजातीय और स्थानीय रहते हैं। इसी सेवा केंद्र के माध्यम से प्लंबर और मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य भी बेरोजगार युवाओं को सिखाया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करके युवा स्वरोजगार में लग जाते हैं। सेंट्रल सर्वर पर लेखा स्थिति तथा अन्य विवरण हार्ड कॉपी में उपलब्ध है।
- एनएबीएल ने लघु उद्योग भारती आदित्यपुर के सहयोग से 25-28 मार्च, 2023 को कार्यशाला आयोजित कर उद्यमियों को एनएबीएल लैब के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर एनएबीएल के एक्रिडेशन अधिकारी श्री मिथिलेश कुमार, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव श्री इंदर कुमार अग्रवाल, एसिया के महासचिव श्री प्रवीण

- गुटगुटिया, आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के प्रबंध निदेशक श्री एसएन ठाकुर उपस्थित थे।
- मशीन रखरखाव और व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण— सिडबी क्लस्टरइंटरवेंशन प्रोग्राम (सीआईपी) के तहत आदित्यपुर में फोर्जिंग और फाउंड्री एमएसएमई केलिए नि:शुल्क प्रशिक्षण 25 से 28 मार्च, 2025 को आयोजित किया। शेलकेयर प्राइवेट लिमिटेंड के सहयोग से आयोजितइस प्रशिक्षण में मशीन रखरखाव, कार्यस्थल सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन को शामिल किया जिससे एमएसएमई को उत्पादकता और सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिल सके।



- बी2बी एक्सपो / जमशेदपुर— आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर, लघु उद्योग भारती, एसिया और इंडोमैक बिजनेस सोल्युशन्स के सहयोग से 6 से 8 फरवरी, 2025 तक बी2बी इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इंजीनियरिंग एक्सपो आयोजित किया गया।
- औद्योगिक क्षेत्र एवं नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं की जानकारी और समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एपी सिंह शामिल हुए। आदित्यपुर जियाडा कार्यालय में आयोजित बैठक में क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सरायकेला उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ल, प्रशिक्षु आईएएस श्री रजत कुमार, जियाडा के क्षेत्रीय उपनिदेशक श्री दिनेश रंजन, आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक श्री रिव प्रकाश एवं औद्योगिक संगठन के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
- 11 जनवरी, 2025 को लघु उद्योग भारती, झारखण्ड तथा स्थानीय संगठन एशिया के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 536 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया।
- नई कार्यकारिणी गठन— रांची में 18 जून, 2025 को नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन रक्षा राज्यमंत्री श्री संजय सेठ की उपस्थिति में किया गया।
- CAIT, LUB & JDA के द्वारा संयुक्त रूप से विदेशी कंपनियों का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाओं के संदेश के पोस्टर का विमोचन किया गया।



Important Activities & Programs:

Meeting with CM Rajasthan:

An important meeting was arranged with Shri Bhajan Lal Sharma, Chief Minister, Rajasthan and his team for Development of MSME Sector & Investment at Kolkata.



Udvami Sammelan-2025: Rising East:

It was held at National Library, Kolkata on 28th June, 2025. About 750+ Industrialists & Entrepreneurs attended the Sammelan. The Railway Ministry has already initiated projects based on the same such as investment of ₹ 125 Cr for expansion of Loco Shed at North Bengal and another investment of ₹ 256.35 Cr for inception of a railway workshop at Alipurduar near the Chicken Neck. There are other projects connecting various parts of West Bengal are also considered based on COD.

Discussion on State of Industry:

An important discussion held at Kolkata on GST, Land Allotment, Subsidy Banking & other burning issues facing by our members in the adverse environment of State on 11th August 2024.

Mehendi Workshop:

About 200 participants attended this workshop held at Siliguri wherein development of self-help group program initiated successfully. Heena & Tattoo workshops are being conducted under the aegis of LUB North Bengal.

Workshop-Development of Jute Cluster:

It was held at Thakur Nagar, North 24 Parganas on 29th October 2023.

- Gram Shilpi Anusthan at Canning: Gramin Krishi-o-Shilp Kala Mela organized by Jelerhat Ghola Mitali Sangha Baruipur in association with Laghu Udyog Bharati.
- Ghar Ghar Diya Program & Medical Camp: A health check-up camp was organized for workers with the support of ESI, Export on 5th October, 2024.
- Promotion & Awareness Program initiated by members during Vendor Meet.
- Exhibition on Skill Development organised at Haripal on 31" October, 2023.
- · Knowledge Sharing Program organized by



Rubber Board of India in association with LUB WB at Nagrakata on 6th march, 2024.

- Abhyash Varg was conducted at the National Library, Kolkata on 8th May, 2024. More than 90 members were present.
 - Officials of Central Pollution Board gave an insight about controlling the Industrial Pollution. LUB's members initiated a Plantation Drive and more than 50 fruit trees in the campus of National Library.
- MSME Day was celebrated in the presence of Shri Gautam Poddar Asst. Director, MSME DFO Kolkata on 27th June, 2024.
- Gramin Kutir Shilp Mela was also organised in association with Satgachi Ramkrishna Mission at Berahampore-Beldanga.
- Vendor Meet Program was organised with Power Grid Corporation of India on 14th March, 2024 at Kolkata.
- An Interactive Session was held at Siliguri related to GST Audit, Nepal Tea, FASSAI, Tea Board and other industrial on 10th May, 2024.

Important Achievements:

 Major Impact on the MSME Sector after the Udyami Sammelan





- Proper training and hand holding for the entrepreneurs
- Focus on Cluster Management
- Development of Members with Innovated Items

Future Agenda:

- Organise a Regional Convention
- Development of Clusters
- Augmentation of Facilities @ Baruipur Surgical Cluster
- Skill Development Centers with Support of Port & Railways
- Monthly Workshops with Govt. of India agencies
- Technology upgradation with IIT, NIT & IIEST's Support



- Special Drive for Artisans Support
- Technical Excursion Industrial Tour to other Prant
- Udyami Sammelan in association with Port & Steel Ministry
- Knowledge Sharing Development of Portal / Training Platform
- Effectiveness & Commercialization of Developed R&D-Innovated Products





Laghu Udyog Bharati Maharashtra State



Amit Ghaisas President ayghaisas@gmail.com

Harish Hande General Secretary harishhande 11@gmail.com





Activities & Policy Interventions:

Over the past year, LUB's Maharashtra Pradesh has consolidated its role as a credible voice of MSMEs in the State. Through regional conventions, direct policy interventions, and consistent dialogue with government authorities, the organisation has not only strengthened its membership base but also achieved tangible policy impact.

Statewide Conventions & Engagement with Policymakers:

LUB Maharashtra organised Adhiveshans across all major regions-Konkan, Pune, Marathwada, Nashik, and Vidarbha. Each convention saw enthusiastic participation from entrepreneurs, industry representatives, and senior government officials. The Mumbai Adhiveshan was particularly noteworthy, with five State Cabinet Ministers, the then Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis, Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman, and Union MoS for Finance Dr. Bhagwat Karad in attendance. Their presence and active engagement reaffirmed the recognition that LUB commands as a policy influencer for the MSME sector.

Policy Advocacy and Achievements Rationalisation of GST for Agro-Processing:

A major policy achievement was the successful representation made before the Directorate General of GST on behalf of agro-processing industries in Vidarbha and Marathwada. These units were initially burdened with 12% GST instead of the rightful 5%. LUB argued, with supporting data and legal interpretation, that the definition of "packaging" for wholesale B2B markets needed correction. The outcome was a rationalisation of GST rates to 5%-a relief that directly benefits thousands of small-scale agro processors, improves competitiveness, and ensures fair treatment for rural entrepreneurs.

Retrospective Implementation of MPCB Orders:

Another important intervention concerned the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB). LUB firmly opposed the retrospective implementation of certain government resolutions. Shri Devendra Fadnavis, then Dy. CM endorsed this position, agreeing that retrospective application of environmental regulations unfairly penalises compliant MSMEs. This acknowledgement was a step forward in creating a balanced regulatory framework.

Strengthening Membership:

Despite several industry-specific associations operating in urban hubs like Mumbai and Pune, LUB Maharashtra has expanded its base meaningfully. Membership rose from 3,900 to 4,500, reflecting both the organisation's credibility and the trust reposed by entrepreneurs. This growth is the result of dedicated outreach and the consistent demonstration of value through advocacy, grievance redressal, and policy engagement.

Recommendations for the Draft-Maharashtra Industrial Policy-2025:

Building on grassroots feedback from our members, LUB Maharashtra submitted a comprehensive set of recommendations for the Draft Industrial Policy with some key following components-

- Ease of Doing Business in Practice
- Affordable Access to Land & Infra
- Financial Ecosystem and Incentives
- Sectoral Priorities
- Environment and Compliance

Importantly, these recommendations submitted by LUB Maharashtra have been formally taken into consideration at the government level during the ongoing process of finalising the Maharashtra Industrial Policy 2025. This reflects the organisation's ability to influence the policy framework and ensure that the voice of small industries is heard in the corridors of power.

LUB Maharashtra has emerged as a strong and responsible representative of MSMEs, balancing advocacy with constructive policy recommendations.

As we look ahead, our focus will remain on enabling a truly business-friendly environment where small industries can innovate, grow, and contribute to Maharashtra's economic leadership. The fact that our recommendations are now under government consideration underscores our effectiveness as a bridge between entrepreneurs and policymakers.

Agenda for the Next Two Years:

To further strengthen the voice of MSMEs, LUB Maharashtra will focus on the following agenda:

Schemes to be Studied:

- Udyog Mitra (Zilla, Regional, and State Level Committees)
- · ZUM, RUM, SUM meetings and their effectiveness
- Ease of Doing Business especially through MAITRI single window facilitation system

Acts to be Studied:

 Electricity Act, MIDC Act & MAITRI Single Window Framework, Legal Metrology Act & Environmental Protection Act

Issues for Follow-up with Govt. Department Industry Ministry:

- Availability of Industrial Space
- · Coordination of Services in MIDC

Energy Ministry:

- Availability and Quality of Electricity
- · Rationalization of Electricity Tariffs
- New Industrial Connections

Environment Ministry:

- Environmental Clearances
- MPCB Consents



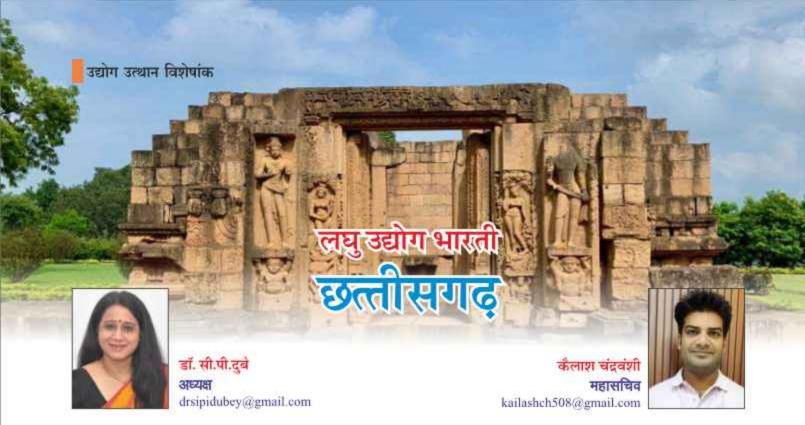
Government Policies for Study:

- Maharashtra Industrial Policy
- · MSMC Policy (Maharashtra Small & Medium
- · Cluster Development Policy)
- · Textile Policy
- Maharashtra State Women's Entrepreneurship Policy

Organizational Growth Targets:

- Increase membership strength to 10,000 within the next two years.
- Establish LUB units in every district of Maharashtra to ensure wider grassroots presence.







- 8 नए जिलों में 8 नयी इकाइयां गठित की गई जिसमें बेमेतरा, कबीरधाम, बस्तर, सरगुजा, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर—चांपा और बिलासपुर शामिल है।
- निम्न आय वर्ग की महिलाओं में उद्यमिता और आजीविका कौशल से जोड़ने के लिए रुई बाती, सिलाई और पेपर बैंग बनाने का प्रशिक्षण बेमेतरा, उठाई, उमरपोटी, हाउसिंग बोर्ड, मरोदा, खुर्सीपार, धमधा, तालपुरी, नेवई भाठा इत्यादि में सफलतापूर्वक प्रदान किया गया। सभी स्थानों पर कुल मिलाकर 400 महिलाएं सम्मिलित हुईं।
- 19 मार्च, 2024 को महिला उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी की गरिमामयी उपस्थिति में 300 से अधिक महिलाओं की भागीदारी रही।

- 2 दिसंबर, 2023 को पारिवारिक मिलन के रूप में राजनांदगाव में दीपावली त्यौहार मनाया गया, जिसमें लगभग सभी सदस्य सम्मिलित हुए। उद्यमियों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सपरिवार बढ़—चढ़ कर हिस्सा लिया।
- 22 जनवरी, 2024 को श्री राम जी के अयोध्या पुनरागमन पर, बाल राम एवं सीता के साथ सुंदरकांड का आयोजन किया गया।
- 16 जुलाई, 2024 को जगदलपुर, जिला बस्तर इकाई का गठन भाजपा अध्यक्ष श्री किरण देव की उपस्थिति में किया गया।
- 14 अगस्त, 2024— विवेकानंद यूथ सर्कल के साथ मिलकर रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज में "अखंड भारत दिवस" मनाया जिसमें 500 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए।





- 12 सितम्बर, 2024 को जगदलपुर, जिला बस्तर में, MSME के सहयोग से NMDC के लिए 'वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम' में प्रदेश भर के उद्यमियों का कार्यक्रम के दौरान ही रजिस्ट्रेशन किया गया एवं छोटे स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता दी गई।
- 18 अक्टूबर, 2024 को मध्य क्षेत्रीय सम्मलेन का आयोजन छत्तीसगढ़ ने किया, जिसमें 4 प्रान्त (मध्य,



मालवा, महाकौशल, छत्तीसगढ़) के लगभग 500 उद्यमी सम्मिलित हुए।

- उद्यमी सम्मलेन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र जी एवं उद्योग से सम्बंधित अधिकारी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दो मुख्य घोषणाएं कीं—
 - (i) छत्तीसगढ़ प्रदेश में पृथक डैडम् मंत्रालय का गठन।
 - (ii) लघु उद्योग भारती को कौशल विकास केंद्र बनाने **जनारती** हेतु भूमि का आवंटन। सम्बद
- छत्तीसगढ़ की मुख्य उपज चावल से जुड़े प्रदेश में
 3000 से अधिक उद्योग हैं। चावल उद्यमियों की कस्टम मिलिंग की एक बहुत बड़ी राशि पूर्व सरकार की नीतियों के कारण उन्हें कभी नहीं दी गई और दो वर्ष पश्चात् सरकार बदलने के बाद इसने एक जटिल

- समस्या का रूप धारण कर लिया। प्रदेश के परेशान कुछ उद्यमियों ने तो अपने उद्योग ही बंद कर दिए।
- दो सरकारों के बीच जन्मी इस नीतिगत समस्या को हल करने का जिम्मा लघु उद्योग भारती ने लिया और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के साथ तीन बैठकें की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश सिंघानिया, महामंत्री डॉ. (श्रीमती) सीपी दुवे और कोषाध्यक्ष श्री दीपक उपाध्याय उपस्थित रहे। गहन चर्चा के बाद बची हुयी कुछ राशि उद्यमियों को आर्थिक सहायता के रूप में मिल गई, और वे अपना उद्योग नियमित रूप से चला पाने में सक्षम हो सके।
- शासन के आग्रह पर औद्योगिक नीति बनाने में लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री पुरुषोत्तम पटेल, उपाध्यक्ष श्री ईश्वर पटेल, श्री किशोर पटेल तथा श्री योगेश पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
- 9 नवम्बर, 2024 को पारिवारिक मिलन के रूप, राजनांदगाव के फॉर्म हाउस में दीपावली त्यौहार मनाया गया।
- लघु उद्योग भारती के प्रयासों से मंडी शुक्क संबंधी समस्या पूरी तरह हल हो गई।
- MSME विभाग के साथ पैकेजिंग विषय पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में 250 से अधिक उद्यमियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग के अतिरिक्त अन्य उपायों पर चर्चा की गई। इस आयोजन में प्रदेश सह–सचिव श्री कैलाश चंद्रवंशी एवं कोषाध्यक्ष श्री दीपकउपाध्याय की मुख्य भूमिका रही।
- DGFT के साथ मिलकर राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद आदि जिलों में एक्सपोर्टप्रमोशन कार्यक्रम आयोजित किये।



Laghu Udyog Bharati Goa State



Pallavi Salgaocar
President
pallavisalgaocar@gmail.com







Important Activities:

The new team has been actively engaged in advocating for and supporting the MSME sector in Goa.

- Goa MSME Adhiveshan 2.0 (November 2024): Participation of over 300 MSMEs. This event focused on the opportunities and challenges for MSMEs in Goa.
- Goa Vikas Manthan (December 15, 2024): An initiative by SPARC Pune, contributing to discussions on the state's development. Also submitted a draft of MSME Policy suggestions.
- Meeting with IPB & DITC: The team met with the Investment Promotion Board (IPB) and the Department of Industries, Trade and Commerce (DITC) to discuss matters pertinent to the industrial sector.
- Interaction with the 16th Finance Commission (January 9-10, 2025): LUB Goa represented the MSME sector, presenting key issues and suggestions.

- MSME Knowledge Series (January 18, 2025): A
 Workshop was organised to educate members
 about AI Tips, GEM Portal, CSTMSE Scheme,
 TREDS Platform, Export Opportunities &
 Packaging aimed at improving productivity.
- MoU with World Trade Centre (WTC) Goa: To promote global trade opportunities for local businesses, LUB Goa signed a MoU with WTC Goa.
- Meeting with Goa Industrial Development Corporation (GIDC): The team held the meeting to discuss infra. and development related issues for industries.
- Business Growth Summit (8th April 2025): In collaboration with the Saraswat Chamber of Commerce and The Goa Chamber of Commerce & Industry, a summit on "Spirituality for Success &



Business Growth" was organised.

- Basic Nursing Course: LUB Goa, in association with Oorja Training & Research Academy, facilitated an introductory nursing course for 23 women from South Goa, promoting skill development and employment.
- MoU with Pernem College (April 10, 2025): An MoU was signed with SSA Government College of Arts and Commerce, Pernem, for entrepreneurial development, witnessed by the Director of Higher Education.



- Celebration of LUB Sthapana Diwas (April 25, 2025): The foundation day was celebrated with an MSME Knowledge Series event focusing on new developments in the MSMED Act and an analysis of the Goa Budget 2025.
- Goa Pharma & Lab Expo (May 8-10, 2025): Supported and participated in the Goa Pharma & Lab Expo, a major event for the pharma, and laboratory sectors.
- Ahilyadevi Holkar's 300th Birth Anniversary (May 24, 2025): A special event was co-organized to honor the 300th birth anniversary of Ahilyadevi Holkar.
- Courtesy Visit to Goa GST Commissioner (June, 2025): The team paid a courtesy visit to the Goa GST Commissioner.
- LEAP Portal Onboarding (July 3, 2025): An exclusive webinar was held for Goa members on the LUB E-Vyapar Advanced Platform (LEAP) to enhance their digital presence and market access.
- Workshop on Packaging and Branding (July 25, 2025): A full-day workshop on "Effective Packaging and Branding Strategies" was organised for Micro and Small Enterprises (MSEs) and Self-Help Groups (SHGs).
- Workshop on Goa Exports Unlocked (August



 2025): A workshop, Export Forum 2025, organised by Global Chambers in association with LUB Goa and WTC Goa, attended by 100 MSMEs.

Areas of Focus Moving Forward:

- Establishment of a LUB Office in Goa.
- Skill Development & Capacity Building Programs, with a focus on sustainability.
- Promoting Innovation through industry collaboration and CSIR Technology adoption by Goan MSMEs – in tune with 100 days, 100 Technologies.
- Enhanced policy advocacy to address the needs of MSMEs. Making representation to Chief Minister and Industry Minister, GIDC, MSME DFO Goa, Deregulation Committee, GST commissioner, RBI empowered committee for MSMEs and others.
- Membership Growth, with a target of over 200 members by 2025.
- Setting up an Export Facilitation Council in association with Global Chamber and WTC Goa, as well as future roundtable programs to help MSMEs in Goa scale and export.
- Helping MSEs in packaging and branding with a joint initiative of LUB Goa and DITC- Govt of Goa.
- Awareness programs on GEM, Vendor Development, ZED Certification program, LEAN, etc. to boost the competitiveness of Goan Industries through the MSME DFO Goa office.
- Boost Industry-Academia connection, by inviting students to attend our programs, as well as LUB members, to visit the colleges with signed MoUs for practical training and industry exposure.
- Partnering with the 'Goa Food Expo' for boosting trade business in the Food sector in Goa.



Laghu Udyog Bharati

Karnatalka State



K. Narayana Prasanna President president@lubkarnataka.org





The past two years were significant for LUB's Karnataka, involving extensive changes, challenges, and transformations within the MSME sector. A cornerstone of LUB-K's work during this period was its proactive policy engagement and remaining in constant dialogue with policymakers, and regulatory authorities to ensure that the voice of MSMEs was heard and acted upon.

Key outcomes included:

- Administrative and procedural reforms simplifying compliance and easing business operations.
- Policy submissions highlighting sector-specific challenges and growth opportunities.
- Regular interaction with thought leaders and domain experts to shape a more conducive industrial environment.

Beyond policy, LUB-K focused heavily on member engagement and capacity building. Over the last two years, the organization hosted initiatives aimed at empowering entrepreneurs with knowledge, networks, and resources.

- Conferences and webinars addressing key industry trends, technological disruptions, and business best practices.
- Business delegation meetings that opened up new markets and collaborative opportunities for local MSMEs.



- Special focus on rural entrepreneurship, helping drive industrial development beyond urban centres.
- Support for Farmer Producer Organizations (FPOs) and women-led enterprises, reinforcing inclusive growth and gender equity.
- Initiatives in the healthcare infrastructure space, indicating LUB-K's willingness to explore and support emerging sectors critical to national development.

Through knowledge-sharing platforms, exposure visits, and expert-led discussions, members were encouraged to:

- Adopt digital tools and automation to improve operational efficiency.
- Embrace Industry 4.0 technologies for better scalability and sustainability.

 Stay updated on emerging trends to remain competitive in both domestic and global markets.

This tech-led push has helped MSMEs stay resilient and agile in the face of industry disruption, opening new growth frontiers.

As LUB-K enters its next phase of growth, the momentum built over the last two years offers a strong foundation for continued success.

Future priorities for the organization include:

- Deepening policy impact through strategic alliances.
- Accelerating rural industrialization and decentralized growth.
- Expanding support for innovation-driven enterprises.
- Promoting sustainability and green manufacturing practices.

Some of the key programs hosted by LUB-K includes:

- Conclave on Viksit Bharat
- Launch of Milletzkart
- MSME Sangaman
- Import Substitution Conclave
- Cohorts on Export Business Opportunities, Seminar on Innovation & Entrepreneurship
- Industrial Visit to TVS Motos & Toyoda Gosei
- Clinic on Wheels Healthcare
- IMS-2023
- MSME Excellence Award
- International MSME Day
- GeM Portal Registration
- Valvx Conference cum-Expo
- Surface Expo
- Food Fest-Experience Millets
- Design Awareness Program for Innovating MSMEs
- Gramashilpi Prakosta: Skill Test for Artisans Card

LUB-K: Way Forward: Next Two years

LUB-Karnataka has laid out a dynamic roadmap for the next two years, focusing on empowering MSMEs and fostering innovation, global outreach, and inclusive growth.

Strategic Direction:

Launch of more Export Business Cohorts with experts like Dr. Jagat Shah to guide MSMEs in tapping international markets.

Collaborations with entities like the Embassies and Trade Commission and Chambers of Commerce to explore global trade opportunities.

Technology & Innovation

- Hosting seminars and webinars on entrepreneurship and innovation, including sessions on emerging tech and global trends.
- Dynamic LUB-K website to better serve members and showcase digital capabilities

Policy Advocacy & Government Engagement

- Regular interactions with Policymakers to address MSME concerns.
- Participation in national forums like MSME Seminars and Import Substitution Conclaves.

Skill Development & Youth Empowerment

- Expansion of Entrepreneurship Development Programs (EDPs) in colleges and institutions.
- Industrial visits and hands-on training at leading companies like OEMs and Large Corporations.

Inclusive Growth & Women Entrepreneurship

- Dedicated verticals to promote women-led enterprises and rural entrepreneurship.
- Events like Handicraft Melas to showcase local talent and support grassroots innovation.

Key Upcoming Events

- India Manufacturing Show 2025 A major industrial trade show in Bengaluru.
- SurfacExpo-2024 First edition launched to spotlight surface engineering and related sectors.
- ValveX Expo- Promoting Valves, Pumps and Actuators manufacturing in the country
- TechBharat- A startup nurturing initiative scheduled for next year.
- Rural Artisans Melas In Mysuru, Hassan and Shivamogga

LUB-K's vision is clear: to be the leading MSME organization in Karnataka by adding value through innovation, collaboration and inclusiveness.

	м	_	
	и.		_
_		_	=



Achievements - (2023 - 2025)

1. Awareness Programs

- GeM Portal: Conducted an awareness program for entrepreneurs on Government e-Marketplace (GeM) Portal, enabling participation in government procurement.
- MSME Schemes: Organized a program in Bhadrachalam on Central & State Govt. schemes for MSMEs.
- 2) Organizational Growth:

New Unit Warangal was inaugurated in the presence of Shri Prakash Chandra Ji.



Membership Growth: Expanded membership from 380 to 460 members in the last two years.

3) Policy Advocacy & Industry Issues





GST Issue on Paper Pulp Egg Trays: The Bhadrachalam (Bhadradri Kothagudem district) Unit raised a concern regarding high GST on egg trays made from paper pulp, a waste by-product of ITC Paper Mill.

GST on waste pulp is higher than finished paper, creating an unreasonable burden on small manufacturers.

The issue was escalated to LUB's National Team and is under process for resolution.

- Vishwakarma Jayanti in 17 industrial units the artisans, engineers and entrepreneurs were honoured.
- Workshop for State Executive Body was conducted at Hyderabad on 19th April 2025.
- New Team for 2025-27 was announced in State General Body meeting in the presence of Shri Prakash Chandra ji on 9th July, 2025.

Plan for Next 2 years (2025 - 2027)

We would like to take following things to strengthen the LUB in Telangana:

Formation of a Technical Committee

To conduct technical workshops for entrepreneurs



across Telangana. Focus on technology adoption, process improvement, and productivity enhancement in MSMEs.

Establishment of a Grievance Committee

Dedicated to resolving grievances raised by industries and members. The Committee will coordinate with relevant govt, departments and policy bodies for quicker redressal.

Formation of a Legal Committee

To investigate legal matters of industry, compliance, dispute resolution, contract issues and legal awareness for members.

Women Entrepreneurs' Unit

A special unit formed for women entrepreneurs to



encourage & support women-led businesses.

Activities will include mentorship, networking & access to schemes for women entrepreneurs.

State-Level MSME Expo

Showcase products & services from MSMEs.

Facilitate B2B & B2G interactions.

Promote collaboration between industries, buyers, and government departments

 Membership Drive to increase the members from 460 to 1000.

To conclude, last two years have been a period of growth, advocacy, and awareness building. Moving forward, our focus will be on technical empowerment, grievance resolution, legal support & women entrepreneurship.







Dr. VSV. Verchezhian President ceo@srikvsindustries.com

R. Kalyansundaram General Secretary alyansundaram@speedpumps.in



Important Activities & Programs:

LUB Tamil Nadu has worked tirelessly to strengthen the MSME ecosystem, guided by its six-pillar approach. The team continues to empower entrepreneurs and contribute to the vision of Viksit Bharat.

1. Membership Drive

LUB Tamil Nadu rapidly expanded its presence by inaugurating new units in Virudhunagar, Erode, Karur increased to 24 fully functional units and planning further launches in 14 district units. Membership drives under the "Each One Bring One" campaign broadened participation, with over 200+ meetings and outreach across 25+ locations.

2. Government Interaction

LUB TN has consistently engaged with Ministers and officials to resolve critical MSME issues:

Interaction with Finance Minister: Over 500

MSMEs presented grievances directly to ministerial secretaries, with 200+ issues raised and 50+ resolved immediately. We thank our FM for acceding our demands of ECLGS, MSME Credit Card, 43(b)Hetc.

Interaction with Railway Minister: A 30-year pending culvert expansion in Ambattur Industrial Estate was expedited, preventing recurring flood losses.

Road & Connectivity: Minister Shri Nitin Gadkari directed immediate steps to address Connectivity challenges in Chennai's industrial zones.

Governor: LUB TN was invited as a stakeholder for MSME-related discussions and provided direct input on Union Budget policy matters.

Flood Relief (Dec. 2023): Special insurance cells were created based on LUB's request, enabling quick settlement of claims for thousands of affected enterprises.

LUB TN represented MSMEs at national and state forums, engaging in manifesto consultations and advocating on GST, EB issues, and delayed payments.

3. Training

Training has been a cornerstone of LUB TN's work, with 40+ structured programs, 7,500+ skill hours, and 30+ expert trainers.

LEAN Manufacturing programs in seven districts saw 400+ MSMEs pledge adoption, with a goal of 100% among office bearers and medium units. Soft skills and technology workshops on time management, emotional intelligence, ONDC, GeM, digital marketing, and finance engaged 1,000+ participants in six months. Awareness drives enabled 500+ ZED and 1,000+ quality certifications, supported by partners like RBI, Zoho, ONDC, and L&T. Going forward, LUB will hold monthly training at units, quarterly zonal programs.

4. Business Development

- Defence & Aviation: A Defence Testing Centre was sanctioned in Trichy. LUB also played a role in reopening Salem Airport under UDAAN after five years.
- Technology Transfers: Under the "100 Days 100 Technologies" initiative with CSIR, Tamil Nadu led the nation by transferring 50+ technologies, including food processing innovations.
- MoUs: Partnerships with SIDBI (PROMO scheme) and Tally solutions have offered members on a discount.
- Buyer-Seller: LUB promoted digital trade platforms like ONDC, LEAP and onboarded MSMEs for wider market access and organized Vendor Sourcing meet for PSUs.

5. Skill Development

Skill development programs have trained thousands of youth and entrepreneurs:

- SRIJAN Kendra: Operational in Villupuram with 80 CNC trainees, with new centres planned for Coimbatore, Tiruppur, and Tiruvarur.
- College Outreach: EDP programs conducted across 25+ colleges reached 5,000+ students, MoU with Chennai Institute of Technology.
- Industry Collaboration: Discussions are underway with IIT-M and SASTRA University for entrepreneurship curriculum design.

6. Grievance Redressal



LUB TN secured ₹40 crore refunds under *Vivad se Vishwas*, negotiated extensions on BHEL debit notes, resolved 15+ GST cases, and achieved partial relief on EB issues, showing strong advocacy for member interests.

Events & Initiatives

 MSME Sangamam-2023 (South Zone Conclave), Coimbatore

LUB TN's first mega event drew over 900 participants, delivering valuable takeaways for MSMEs and setting the stage for an annual conclave.

- MSME Sangamam-2024 (South Zone Conclave) @Chennai: The conclave drew 1,200 participants from 45+ locations, was oversubscribed despite modest fees, earned 95% five-star ratings, and offered rich networking, policy dialogue, and knowledge sharing.
- Sthapana Diwas-2025: A three-day celebration in April 2025 featured membership drives, start-up events, factory celebrations, tree plantations, employee felicitation, and social initiatives like blood donation and health camps.
- State Working Committee: The Salem meeting in March-2025 reviewed progress on membership, awareness, skill-building, and government advocacy, with resolutions passed for state and central governments.
- State Annual Meet: Held on 1" June, 2025 in the presence of national dignitaries, the meet inducted the new state leadership. The event reflected unity and commitment to MSME growth.
- Prashikshana Varga 10th Aug, 2025: Release of Thozhil Sudaroli magazine to highlight MSME voices.
- Launch of an LUB Handbook for members as a ready reference and guide.

Membership will grow from 3,000 to 6,000 in two years, supported by 14 new district units. A **Grievances App** will provide faster redressal. Office bearers will drive registrations on the **LEAP portal**. Social media will highlight success stories, while **Pravas** will deepen member engagement.





<u>Laghu Udyog Bharti - Yamunanagar</u>

"Promoting Small Industries, Empowering Entrepreneurs"

SR. NO.	ORGANIZATION'S NAME	NAME OF THE OWNER	FOR BUSINESS ENQUIRIES CONTACT E-MAIL ADDRESS	CONTACT	PRODUCT DETAILS
T.	Erol Exports Pvt.Ltd.	Mrs. Anita Saluja	erolexports@gmail.com	9896400567	Abrasive Blasting Equipment, Air Treatment & Accessories and Valves
2.	Shree Gururam Dass International Pvt Ltd	Mr. Jaideep Chawla	jalcoagro@gmail.com	9812003416	Manufacturer of agricultural implements
3.	Polyplastics Industries (I) Pvt. Ltd.	Mr. Kapil Gupta	kapilgupta@polyplasticsindia.com	9812051531	Automotive plastic component
4	Unique Wood Industries	Mr. Sanjiv Gupta	uniquewoodind@gmail.com	9355352898	Commercial plywood
5,	Chanderpur Works Pvt.Ltd.	Mr. Sudhir Chandra	sudhirchandra@chanderpur.com	9812095635	Turnkey solutions providers for cement, mineral, time, waste-to- energy through gasification, petrochemical industries and more
6	Oriental Engg, Works Pvt.Ltd	Mr. Raman Saluja	ramansaluja@oewin.com	9896351753 9215551753	Offers hydraulic equipment and industrial cylinders, such as double-acting cylinders, pull- pack cylinders, hydraulic power packs, jacks, and other related products
ž.	Shri Pooja Decorative Plywood's	Mr. Ved Rekhan	Ved1948@rediffmail.com	9416021580	Decorative plywood, block boards & marine plywood
8.	Kalyan Industries	Mr. Jagmohan Singh	info@kalyanindutries.com	98120-92416	Manufacturer of Plywood & woodworking machinery
9.	Rajnish Garg & Co.	Mr. Rajnish Garg	rajnishgargca@yahoo.com	98120-92416	Chartered Accountant firm
10	CBMEW India Pvt. Ltd	Mr. Nakul Chandra	Ctrm.info@yahoo.in	9996925845	Hydro-mechanical & imigation systems, pressure vessels, boilers, heavy equipment
tt.	Ruby Enterprises	Mr. Vikas Gupta	Jaishreeram,vikas@gmail.com	9812020060	Luxury bespake home furnishing and décar brand
12.	Natraj Tyres	Mr. Bhupinder S. Chauhan	777bsc@gmail.com	9216933583	Authorized tyre dealer
13_	Ambay Engineering Corporation	Mr. Aashish Luthra	Ashish.ynr@gmail.com	9812032462	Control panels (HT/LT), agitator tanks, AC sheet plant machinery, corrugated plant equipment
14.	Anurag Decoratives Ltd (Modak Ply)	Mr. Gagan Aggarwal	anuragdecoratives@gmail.com	9896082198	Commercial plywood
15.	Kehar Singh & Sons	Mr. Manish Dhirnan	ranbirsingh@yamunapiston.com	9896400515 9896400516	Automobile part manufacturing —likely pistons or related components
16.	United Wood Products	Mr. Ajay Oberoi	unitedtimberworks@gmail.com	9996033888	Manufacturer of Waterproof Film Faced Shuttering Plywood
17.	Hargun Industries	Mr. Hardeep Anand	mail@hargunindustries.in	9812034127	Plywood, Block Board, Flush Door, Marine Ply, and more
18	Steel Craft Industries	Mr. Raman Gupta	Ramangupta75@yahoo.com	9215598515	Heat Exchangers, Vessels, Tanks, Piping and Heavy Structure.



<u>Laghu Udyog Bharti - Yamunanagar</u>

"Promoting Small Industries, Empowering Entrepreneurs"

SR. NO.	ORGANIZATION'S NAME	NAME OF THE OWNER	FOR BUSINESS ENQUIRIES CONTACT E-MAIL ADDRESS	CONTACT	PRODUCT DETAILS
19,	Super Floorings Pvt.Ltd.	Mr. Ish Anand	ish@superflooringsgroup.com	9355361232	PVC & rubber floorings, insulation sheets, multi-purpose flooring
20.	Birnal Aluminums Pvt.Ltd.	Mr. Rajnish Kharbanda	info@bimalindia.com	9313579643 9355310258	Exporter and Manufacturer of Aluminium Alloy Milk Cans, Bulk Milk Coolers, and Aluminum Extrusion Sections/Profiles
21.	Yamuna Power & Infrastructure Ltd	Mr. Rajeev Sardana	rajeevsardana@yamunapower.com	9991700670	Power Cable Jointing Accessories
22.	T.R Industries Pvt Ltd	Mr. Chirag Vinayak	bloomburgschool@yahoo.com	9729092417	Supplying & Trading Of Scap Dish, Sink Waste Coupling, Sis Corner Rack Etc.
23.	Upper India Smelting & Refinery Works	Mr. Atul Gupta	atulgupta@uizincoxide.com	9812022418	The Most Credible Zinc Oxide Manufacturers
24	Ajay Wood Products	Mr. Ajay Gupta	Ajaywood222@gmail.com	9812021684	Commercial plywood
25.	Shive Plywood Industries	Mr. Sushil Aggarwal	Contactoriental@rediffmail.com	9812050949 9355350949	Commercial plywood
26.	Ajay Oil Mills	Mr. Nipun Gupta	Ajayoilmilis78@gmail.com	9812020725	Cottonseed oil, Cottonseed cake, and Cattle feed
27,	Bishan Dass Nayar & Sons	Mr. Rajesh Nayar	Rajeshnayar@gmail.com	9812003501	Commercial plywood
28.	Shree Ram Wood Industries	Mr. Rajesh Treban	Rajeshtrehan63@grnail.com	9355343150	Commercial plywood
29.	Astha Industries	Mr. Rajat Gupta	Asthe.ynr@gmail.com	9355123458	Paper Products
30,	Northern Timbers	Mr. Sandeep Jindal	info@northernply.com	9416038689	Commercial plywood
31,	Oberoi Wood Industries	Mr. Arun Oberoi	oberoiwood@gmail.com	9355538016 9355324886	Commercial plywood
32.	Lakstimi Industries	Mr. Rajeev Vasudeva	Svasudeva87@gmail.com	9355323636 9812032999	Brass Copper Circle, Aluminiun Wesher
33.	Jagdish Saw Mill-III	Mr. Hemant Gupta	hemant5689gupta@gmail.com	9315394695	Commercial plywood
34.	Metal Cast & Alloy Pvt Ltd	Mr. Harvinder Singh	info@metalcastindia.com	9896351615	Bronze Casting & Aluminium Casting Products
35.	Globe Panel Industries Pvt Ltd	Mr. Sourabh Aggarwai	globepanel@gmail.com	8199950343	Plywood & Laminate manufacturers
36.	Great India Steel Fabricators	Mr. Varinder Mehndiratta	ceo@greatindia.co.in	9896321175	Heavy/medium steel structures, machining, fabrication for power/refinery/infrastructure projects, bridges
37:	UE Alloy Pvt Ltd	Mr. Vibhor Pahuja	vibhorpahuja@yahoo.co.in	9416021392	Copper & brass sheets
38.	Delhi Public School	Mr. Ram Niwas Garg	mgg16@gmail.com	9812037746	SCHOOL (Education Sector)
39.	Gupta Metal Industries	Mr. Kapil Gupta	kapil@guptametals.in	9896000019	Copper and copper alloy product
40.	Pragati Industries	Mr. Neeraj Jain	info@pragatiinds.com	9215534575	Plastic components, labels and stickers & electroplating plant
41	Modern Fabricators & Engineers	Mr. Vikas Bhanot	vicky4bhanot@gmail.com	9355565465	Fabrication of turbines, turbo generators, electric motors
42	Imperial Engineering Company	Mr. Amit Ghai	Imperialengineeringcompany57 @gmail.com	9215526393	Steel Ammunition Boxes & Wooden Ammunition Boxes
43	Om Engineering Enterprises	Mr. Gobind Dhall	govindd21@gmail.com	9896353718	Heavy duty reactor vessels and tanks.



<u>Laghu Udyog Bharti - Yamunanagar</u>

"Promoting Small Industries, Empowering Entrepreneurs"

SR. NO.	ORGANIZATION'S NAME	NAME OF THE OWNER	FOR BUSINESS ENQUIRIES CONTACT E-MAIL ADDRESS	CONTACT	PRODUCT DETAILS
44.	Indian Plywood Company	Mr. Kuriwar Sukhraj Singh	indianplywoodcompany @yahoo.com	9416021557	Hardwood, Marine, Alternative Plywood
45.	Smartx Infra Holdings Pvt Ltd	Mr. Bharat Agarwal	bharatsmartxinfra@gmail.com	9812108885	Real Estate and Rental and Leasing
46.	Omag Electricals	Mr. Karıv Gandhi	kanvgandhi@gmail.com	9992006108	Aluminium Terminals, Connectors & Copper braid
47	Prakash Cookware and Appliances	Mr. Tarun Kumar Goyal	tarun@prakashalloy.com	9812042699	Kitchenware
48.	Shree Raghunath Enterprises	Mr. Ashu Gupta	shreeraghunath@gmail.com	9896045065	Kitchenware
49	Gargsons Industries	Mr. Shikant Garg	Shikantgarg@gmail.com	9813626246	Stainless Steel Products
50	Vikram Power Technologies Pvt Ltd	Mr. Vikram Bali	sales@vptel.com	9996630201	Electrical Products
51,	Sunnse Panels	Mr. Samar Gupta	sunrisepanels@gmail.com	8059222555	Manufacturing only Film face plywood
52	Dimple Cineplex	Mr. Aayush Gupta	dimplecineplex@gmail.com	9354979797	Movie theater
53.	Ganpati Plywood	Mr. Sanjeeev Gupta	sunrisepanels@gmail.com	93156081081	Plywood Products
54.	Gopal Industries	Mr. Ajay Malik Tala	plyinsight@gmail.com	9812004976	Plywood Products
55.	Goel Wood Industries	Mr. Himanshu Goel	goelsushil2@gmail.com	8397000244	Classic Wood Polished Swing Door.
56.	Star Laminate India Pvt. Ltd	Mr. Ashwani Aggarwal	info@starlaminates.com	9896300553	Industrial Laminates Manufacturers
57.	Subhash Saw Mills	Mr. Rajesh Gupta	rajmini207@gmail.com	9896000669	Plywood Products
58.	PS Enterprises	Mr. Prikshit Singla	prksht24@gmail.com	9355555951	Distributor of biomass pellets
59.	Evergreen Wood Industries	Mr. Munish Jindal	enquiry@evergreenply.com	9355638758	Plywood Products
60.	GNG Industries	Mr. Brijesh Garg	gmgplywoods@gmail.com	9996010819	Plywood Products
61.	Arun Oxygen Ltd	Mr. Samarth Garg	arunoxygen@yahoo.co.in	9215586739	Manufacturer of Oxygen & Co2 Gas Cylinder
62	CA Tarun Bhetie	Mr. Tarun Bhatia	catarunbhatia@gmail.com	9254550055	Investment Banking
63.	Chanana Udyog	Mr. Samrat Channana	sam@chananaudyog.com	9996045325	Utensil Manufacturing Company
64.	Snow Farm Fresh LLP	Mr. Shivam Vashishtha	B28@snowfarmfresh.com	9582146390	Agericus Bisporus (Button Mushrooms)
65.	Jai Bharat Ispat Udyog	Mr. Sajal Jain	jaibharatispa@gmail.com	9416268923	Utensits And Art Wares Metal Products
66.	BRS Industries	Mr. Rajan Sapra	rajansapra@yahoo.com	9416026061	Plastic Product, Forging and stamping, Medical equiptment manufacturer.
67.	CA Rakshit Madaan	Mr. Rakshit Madaan	camadaanO1@gmail.com	9896000679	Investment Banking





जेम अपनाएं

अपने व्यवसाय को राष्ट्रीय मंच पर दें पहचान



वुमनिया महिला उपमियों के लिए विशेष मंच



स्टार्टअप रनवे

रीपीआईआईटी-पंजीकृत स्टार्टअप्स के लिए विशेष अवसर



सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

आसान ऑनवोर्डिंग सरीदारों तक सीधी पहुँच देश की आत्मनिर्भरता में भागीदारी

1.6 लाख+

सरकारी खरीदारों तक सीधी पहुँच

~45%

ऑर्डर सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मिला (~ १६.८८ लाख करोड़+) ₹5 लाख करोड़+

के व्यावसायिक अवसर

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

file of grown it we are

the of 2004-35 di alique es 45 inu mis

जेम से जुड़ें, कारोबार बढ़ाएं!

हमसे जुड़ें रहने के लिए क्यू आर स्केन करें।















30 August - 2025

Registration No. RAJBIL/2016/69093 Postal Reg. No.: Jaipur City/433/2020-22



Follow us



lubindia



lubindia



@lubBharat



lub,india



in laghu-udyog-bharati